

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2022 की संख्या 33
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ)

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)

2022 की संख्या 33

(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ)

विषय सूची

अध्याय/पैराग्राफ	विषय	सीपीएसई	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन		v
	कार्यकारी सार		vii
ऊर्जा क्लस्टर			
अध्याय I	कोयला मंत्रालय		
1.1	डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए भत्तों का भुगतान	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	1
1.2	डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए कार्य निष्पादन संबंधी वेतन का भुगतान	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	3
अध्याय II	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
2.1	पट्टे के नवीकरण में देरी के कारण ₹16.93 करोड़ का परिहार्य व्यय	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	6
2.2	डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कर्मचारियों को अनियमित भुगतान	चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	9
2.3	वाहनों के 'चालन और रखरखाव' व्यय के भुगतान के रूप में कार्यकारियों को अनुचित लाभ	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	12
2.4	निर्यात सब्सिडी की वसूली न होने से हानि	एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड	21
2.5	प्रोपलीन हैंडलिंग सुविधाओं के सृजन पर निष्फल व्यय	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	26

2.6	ऊर्जा संरक्षण के अवसर को छोड़ा गया	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	30
2.7	कम हाइड्रोकार्बन और जोखिम भरे अन्वेषण और उत्पादन ब्लॉक में भागीदारी के कारण ₹145 करोड़ का निष्फल व्यय	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	34
2.8	अव्यवहार्य एनईएलपी ब्लॉकों के त्याग के बाद उन पर परिहार्य व्यय	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	38
2.9	कंडेनसेट की विक्रय के लिए निविदा को अंतिम रूप देने में अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के परिणामस्वरूप राजस्व की कम वसूली हुई	ऑयल इंडिया लिमिटेड	42
अध्याय III विद्युत मंत्रालय			
3.1	वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के कारण हानि	दामोदर घाटी निगम	46
3.2	₹85.35 करोड़ का परिहार्य व्यय	नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	49
3.3	एनएचपीसी, मुजफ्फरपुर को ₹13.09 करोड़ की हानि	एनएचपीसी लिमिटेड	53
3.4	गैस रूपांतरण पर निरर्थक व्यय	एनटीपीसी लिमिटेड	58
उद्योग क्लस्टर			
अध्याय IV वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग)			
4.1	'स्टॉप लॉस' की सीमा का पालन न करने के कारण निवेश का मूल्यहास	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	65
4.2	माल और सेवा कर के प्रति इनपुट टैक्स क्रेडिट की हानि	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	70

4.3	मोटर बीमा प्रीमियम का कम प्रभार	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और दी ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	74
4.4	निवेश नीति के अनुसार इक्विटी शेयरों की निकासी में विफलता के कारण परिहार्य हानि	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	79
अध्याय V			
स्टील मंत्रालय			
5.1	अविवेकपूर्ण वित्तपोषण के परिणामस्वरूप ₹26.87 करोड़ की हानि हुई	एमएसटीसी लिमिटेड	82
5.2	परियोजना प्रबंधन में कमियों के कारण हानि	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	86
5.3	राउरकेला स्टील संयंत्र में स्थापित गैस धारक के निष्क्रिय होने से हानि	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	90
इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर			
अध्याय VI			
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय			
6.1	प्रतिपूर्ति प्रभारों का परिहार्य भुगतान	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	95
अध्याय VII			
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय			
7.1	रियायतग्राही से ₹693.24 करोड़ की क्षति की वसूली करने में एनएचएआई की असमर्थता	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	98
7.2	टोल राजस्व की हानि	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	103
7.3	संविदात्मक प्रावधानों को लागू न करने के कारण टोल प्रभारों की संदिग्ध वसूली	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	108

अध्याय VIII	लेखापरीक्षा में बताए जाने पर सीपीएसईज द्वारा की गई वसूली और सुधार/परिशोधन		
8.1	लेखापरीक्षा में बताए जाने पर वसूली	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयर इंडिया लिमिटेड, एपिटको लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, दामोदर घाटी निगम, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स पेमेंट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	119
8.2	लेखापरीक्षा में बताए जाने पर सुधार/परिशोधन	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	119
अध्याय IX	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई		120
	अनुलग्नक		123

प्राक्कथन

1. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित सरकारी कंपनियों के लेखाओं (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनी मानी जाने वाली कंपनियों सहित) की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (सन्दी लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं, जिनकी टिप्पणियां वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक हैं। इसके अलावा, ये कम्पनियां नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के भी अधीन हैं।
2. कुछ निगमों और प्राधिकरणों को शासित करने वाली संविधियों के अनुसार उनके लेखाओं को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने की आवश्यकता होती है। ऐसे पांच निगमों अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम के संबंध में प्रासंगिक संविधियों में, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उनके एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में नामित किया गया है। एक निगम अर्थात् केन्द्रीय भंडारण निगम के संबंध में, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास निगम को शासित करने वाली संविधि के अंतर्गत नियुक्त सन्दी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के बाद पूरक और नमूना लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।
3. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के अंतर्गत, जैसा कि 1984 में संशोधित किया गया है, सरकार को किसी सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदन नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
4. वर्ष 31 मार्च 2021 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सात मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन 23 सीपीएसईज से संबंधित 26 पृथक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं। इन मंत्रालयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में आगे तीन क्लस्टरों अर्थात् ऊर्जा, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा क्लस्टर के अंतर्गत 15, उद्योग क्लस्टर के अंतर्गत 7 और इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर के तहत 4 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत उन में से हैं जो 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा के समय संज्ञान में आए थे और साथ ही साथ वे दृष्टांत भी हैं जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आए थे। कुछ मामलों में मार्च 2021 के बाद संव्यवहारों के लेखापरीक्षा परिणामों का भी उल्लेख किया गया है।
5. इस प्रतिवेदन में 'कंपनियों/निगमों या सीपीएसईज' के लिए सभी संदर्भ 'केन्द्र सरकार की कंपनियों/निगमों' के लिए संदर्भ माना जा सकता है जब तक कि संदर्भ में अन्यथा सुझाव न दिया जाए।
6. यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) या संदर्भित निगमों को शासित करने वाली संविधियों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार की कंपनियों और निगमों के लेखाओं और अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

2. इस प्रतिवेदन में सात मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत 23 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित 26 पृथक अभ्युक्तियाँ शामिल हैं। इन मंत्रालयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में आगे तीन क्लस्टरों अर्थात् ऊर्जा, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा क्लस्टर के अंतर्गत 15, उद्योग क्लस्टर के अंतर्गत 7 और इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर के अंतर्गत 4 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ हैं। मसौदा अभ्युक्तियों को छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्येक मामले में अपने उत्तर/टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को अग्रेषित किया गया था, जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में सीपीएसई कार्य कर रहे हैं। इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने तक 12 अभ्युक्तियों के प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुए थे जैसा कि नीचे पैरा 3 में दर्शाया गया है। इससे पहले, मसौदा अभ्युक्तियों को संबंधित सीपीएसई के प्रबंधनों को भेजा गया था, जिनके उत्तर को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

3. इस प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई से संबंधित हैं:

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग (शामिल सीपीएसई)	पैराग्राफ की संख्या	पैराग्राफों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालयों/विभागों के उत्तर प्रतीक्षित हैं
ऊर्जा क्लस्टर			
1.	कोयला (एनएलसी इंडिया लिमिटेड)	2	0
2.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया))	9	6

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग (शामिल सीपीएसई)	पैराग्राफ की संख्या	पैराग्राफों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालयों/विभागों के उत्तर प्रतीक्षित हैं
	लिमिटेड, एचपीसीएल, एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड, आईओसीएल, ओआईएल और ओएनजीसी)		
3.	विद्युत् (दामोदर घाटी निगम, नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड और एनटीपीसी)	4	1
उद्योग क्लस्टर			
4.	वित्त - वित्तीय सेवा विभाग (भारतीय साधारण बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड)	4	2
5.	इस्पात (एमएसटीसी लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड)	3	1
इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर			
6.	आवासन और शहरी कार्य (चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड)	1	0
7.	सड़क परिवहन और राजमार्ग (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)	3	2
कुल		26	12

4. पृथक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹4,068.64 करोड़ है।

5. इस प्रतिवेदन में पृथक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

- 11 लेखापरीक्षा पैराग्राफों¹ में शामिल ₹3,499.17 करोड़ के संविदा के नियमों, निर्देशों, प्रक्रिया, नियम एवं शर्तों आदि का अनुपालन नहीं किया जाना।

¹ पैरा संख्या 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1 और 7.3

- 5 लेखापरीक्षा पैराग्राफों² में शामिल संगठनों के ₹71.09 करोड़ मूल्य के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं किया जाना।
- 7 लेखापरीक्षा पैराग्राफों³ में ₹296.73 करोड़ का दोषपूर्ण/अक्षम नियोजन।
- 3 लेखापरीक्षा पैराग्राफों⁴ में ₹201.65 करोड़ की अपर्याप्त/अक्षम निगरानी।

6. इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा के बताने पर सीपीएसईज द्वारा “वसूली एवं सुधार/संशोधन” पर एक अध्याय शामिल है। अध्याय में दो पैराग्राफ अर्थात् (क) लेखापरीक्षा के बताने पर 13 सीपीएसईज द्वारा की गई ₹209.90 करोड़ की वसूली/बचत, और (ख) लेखापरीक्षा के बताने पर एक सीपीएसईज द्वारा किए गए सुधार/संशोधन शामिल हैं।

II प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने दिशानिर्देश जारी (अगस्त 2017) किए, जिसमें कहा गया कि 'कैफेटेरिया दृष्टिकोण' के अंतर्गत कार्यकारियों को विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य अनुलाभ और भत्ते मूल वेतन के 35 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन होंगे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएलसीआईएल ने डीपीई दिशानिर्देशों और कोयला मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एनएलसीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के कार्यकारियों को मूल वेतन के 35 प्रतिशत के सामान्य भत्ते के अलावा रियायती बिजली के गैर-मौद्रिक अनुलाभ को मंजूरी दी। इसके परिणामस्वरूप एनएलसीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के कार्यकारियों को ₹17.22 करोड़ की सीमा तक डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनुलाभों का अनियमित और आवर्ती भुगतान हुआ।

(पैरा 1.1)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह (बंदरगाह) से पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण के लिए हल्दिया तटीय संस्थापन की स्थापना के लिए 20 साल की अवधि के लिए पट्टे पर भूमि ली थी और फरवरी 2013 में इसकी अवधि समाप्त हो गई थी। बंदरगाह ने ₹1.81 करोड़ के ब्याज सहित ₹6.03 करोड़ के बढ़े हुए पट्टे किराए का भुगतान न करने के कारण पट्टे के

² पैरा संख्या 2.4, 2.8, 4.1, 5.1 और 6.1

³ पैरा संख्या 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 3.4, 5.2 और 7.2

⁴ पैरा संख्या 2.1, 3.2 और 5.3

नवीकरण के लिए कंपनी के प्रस्ताव (जनवरी 2013) को अस्वीकार कर दिया। कंपनी को ₹36.71 करोड़ के अग्रिम प्रीमियम के भुगतान पर 30 वर्षों के लिए उपर्युक्त पट्टे के नवीकरण के लिए बंदरगाह के प्रस्ताव (मार्च 2016) पर अपनी स्वीकृति के बारे में अवगत (नवंबर 2017) कराने में 21 माह का समय लगाया। इस बीच, किराये में वृद्धि और माल एवं सेवा कर लागू होने के कारण उपरोक्त पट्टे के नवीकरण के लिए कर सहित कुल अग्रिम प्रीमियम को बढ़ाकर ₹53.64 करोड़ कर दिया गया। इस प्रकार, प्रबंधन द्वारा पट्टे के नवीकरण के लिए बंदरगाह के प्रस्ताव को स्वीकार करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹16.93 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैरा 2.1)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक वाहनो के परिचालन और अनुरक्षण व्यय का भुगतान करके अपने कार्यकारियों को ₹2,609.47 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया।

(पैरा 2.3)

भारत सरकार ने एक योजना अधिसूचित (12 सितंबर 2019) की, जिसमें प्रत्येक चीनी मिल के लिए निर्धारित अधिकतम स्वीकार्य निर्यात मात्रा निर्धारित की गई थी और चीनी के निर्यात पर व्यय के लिए सहायता के रूप में ₹10,448 प्रति टन की राशि तय की गई थी। भारत सरकार ने एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड चीनी मिलों की अधिकतम स्वीकार्य निर्यात मात्रा 13,266 टन निर्धारित की। एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड को एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड द्वारा विक्रेता के पैनल, दस्तावेजों के सत्यापन, बयाना राशि जमा की वसूली, निविदा को अंतिम रूप देने और ऑनलाइन नीलामी का कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया। श्री वेंकटेश्वर ग्लोबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड एच1 बोलीदाता के रूप में सामने आया और निर्यात चीनी बिक्री करार को निष्पादित किया गया (30 दिसंबर 2019)।

निर्यातक ने 1 जनवरी 2020 से 3 मार्च 2020 के बीच 13,266 टन चीनी उठाई और तदनुसार एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड को चीनी की बिक्री के कारण ₹27.86 करोड़ की प्राप्ति हुई। तथापि, निर्यातक ने सब्सिडी के दावे के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए। निर्यातक द्वारा अपेक्षित निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड अधिकतम स्वीकार्य निर्यात मात्रा योजना के अंतर्गत

सरकार से ₹13.86 करोड़ की सब्सिडी का दावा नहीं कर सका। एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड को सफल बोलीदाता की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में उत्तर-दिनांकित चेक की स्वीकृति में विफलता के कारण ₹13.76 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 2.4)

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की विशाख रिफाइनरी में, इस बात से अवगत होने के बावजूद कि एकमात्र ग्राहक - मैसर्स आंध्र पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड विशाख रिफाइनरी से सीधे समर्पित पाइपलाइन के माध्यम से उत्पाद उठा रहा था, अतिरिक्त प्रोपलीन हैंडलिंग सुविधाओं का सृजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹11.50 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैरा 2.5)

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की विशाख रिफाइनरी में निरंतर उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई के नेट गैस कंप्रेसर में निरंतर क्षमता नियंत्रण प्रणालियों के कार्यान्वयन में विलंब के परिणामस्वरूप जून 2014 से नवंबर 2018 के दौरान ऊर्जा संरक्षण के लिए ₹10.59 करोड़ की बचत करने का अवसर खो गया।

(पैरा 2.6)

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) ने कैम्बे बेसिन, गुजरात में अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) के लिए ब्लॉकों, हाइड्रोकार्बन के व्यवहार्य भंडार की उपलब्धता का संकेत देने वाले मूल तत्वों की उपस्थिति / अनुपस्थिति की संभावना के बारे में आंतरिक सलाहकार के साथ-साथ तृतीय पक्ष के सलाहकार द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों की अनदेखी करके, विशेष रूप से जब कंपनी को ई एंड पी गतिविधियों में ऑपरेटरशिप का कोई अनुभव नहीं था, 100 प्रतिशत भागीदारी हित और ऑपरेटरशिप के साथ दो तटवर्ती टाइप-एस अन्वेषण ब्लॉकों का अधिग्रहण किया। अधिग्रहीत ब्लॉक में हाइड्रोकार्बन नहीं पाए जाने के कारण, ब्लॉक को छोड़ने का निर्णय (अगस्त 2015) लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹145 करोड़ (न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के पूरा नहीं होने के कारण ₹37.32 करोड़ के निर्णीत हर्जाना और निर्णीत हर्जाना के विलंब से भुगतान पर ₹15 लाख के ब्याज सहित) का निष्फल व्यय हुआ।

(पैरा 2.7)

भारत सरकार ने क्रमशः अप्रैल 2000 और जुलाई 2001 में ओएनजीसी को महानदी बेसिन में दो एनईएलपी ब्लॉक अर्थात् एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/3 और एमएन-ओएसएन-2000/2 प्रदान किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना की प्रतिकूल आर्थिक व्यवहार्यता और सीसीईए द्वारा अनुमोदित परीक्षण आवश्यकता नीति, 2015 के अनुसार वाणिज्यिकता की घोषणा के अनुमोदन के लिए आवश्यक ड्रिल स्टेम टेस्ट करने में विफलता के बावजूद, ओएनजीसी ने अपने दो एनईएलपी ब्लॉकों पर उनके त्याग दिए जाने के बाद ₹23.12 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैरा 2.8)

कंडेनसेट की पर्याप्त मात्रा और इच्छुक बोलीदाताओं की उपलब्धता के बावजूद, ओआईएल ने निविदा रद्द कर दी और अंततः, कंडेनसेट को कच्चे तेल के साथ मिश्रित कर दिया। इस प्रकार, ओआईएल ने अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया क्योंकि इसने सम्मिश्रण के परिणामस्वरूप केवल कच्चे तेल की कीमत प्राप्त की, जो कंडेनसेट की कीमतों से बहुत कम थी। ओआईएल वैध बोलीदाताओं के प्रस्तावों को स्वीकार करके ₹24 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त कर सकती थी।

(पैरा 2.9)

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने 1 जनवरी 2016 से खनन पट्टे को बढ़ाने के लिए जिला खनन कार्यालय, बोकारो को आवेदन (दिसंबर 2014) दिया। डीवीसी के पास वैध खनन योजना नहीं होने के कारण खनन पट्टे को नहीं बढ़ाया गया। डीवीसी ने बेरमो खदानों से कोयले के अधिभार को हटाने और परिवहन के लिए भारी अर्थ मूविंग मशीनरी के परिनियोजन का कार्य ₹14.11 करोड़ की लागत पर मैसर्स बीकेबी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (संविदाकार) को दिया (सितंबर 2016)। उपायुक्त सह मजिस्ट्रेट के कार्यालय, बोकारो ने 1 नवंबर 2016 से अयस्क भेजने के लिए ऑनलाइन चालान अनिवार्य कर दिया। ये ऑनलाइन चालान डीवीसी द्वारा जनरेट नहीं किए जा सके क्योंकि उनके पास अनुमोदित खनन योजना नहीं थी। इस प्रकार, डीवीसी को ऑनलाइन चालान के अभाव में कोयले की ढुलाई नहीं होने का हवाला देते हुए अगस्त 2017 से खनन कार्य बंद करना पड़ा। निगम ने अधिभार को हटाने के लिए संविदाकार को ₹7.78 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार, बेरमो माइंस के लिए वैध खनन पट्टे के बिना खनन संविदा देने से अधिभार हटाने की लागत के लिए ₹7.78 करोड़ की हानि के साथ साथ ₹17.95 करोड़ मूल्य के 59,850.10 मीट्रिक टन कोयले की हानि हुई।

(पैरा 3.1)

नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक कार्यान्वयन करार किया (18 मार्च 2016), जिसमें संचरण लाइन को 30 अप्रैल 2019 तक चालू किया जाना था। हालांकि, कंपनी ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से सितंबर 2017 तक पहली इकाई के चालू होने के साथ मेल खाने वाली एक संचरण लाइन चालू करने का अनुरोध किया (मार्च 2016)। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मई 2018 में संचरण लाइन का कार्य पूरा कर लिया था, परंतु नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लाइन का प्रयोग नहीं कर सकी क्योंकि इकाई 1 तब तक चालू नहीं हुई थी। परिणामस्वरूप, एक उत्पादक कंपनी होने के नाते इसे कार्यान्वयन करार के अनुसार संचरण प्रभार वहन करना पड़ा। नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को निष्क्रिय संचरण प्रभारों के भुगतान के कारण ₹85.35 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ, क्योंकि वह अपनी बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय का निर्धारण करने में असमर्थ थी और संचरण लाइन के साथ तुल्यकालन में परियोजना को पूरा करने में भी विफल रही।

(पैरा 3.2)

एनएचपीसी को एक निष्पादन एजेंसी के रूप में चुना गया और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण/उन्नयन के लिए नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय करार (31 अगस्त 2004) किया गया था।

एनएचपीसी को उपर्युक्त कार्य के लिए वर्ष 2008-09 से 2014-15 के दौरान ₹127.98 करोड़ की फीस प्राप्त हुई। तथापि, कंपनी द्वारा उपर्युक्त फीस पर सेवा कर इस धारणा पर समय पर जमा नहीं किया गया कि बिहार में सड़क परियोजनाओं के निर्माण और अनुरक्षण के लिए निष्पादन एजेंसी के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं सेवा कर से मुक्त थीं। एनएचपीसी को निर्धारित समय के भीतर सेवा कर का भुगतान नहीं किए जाने के कारण वर्ष 2008-09 और 2014-15 के बीच की अवधि के लिए ₹13.09 करोड़ के ब्याज और शास्ति के परिहार्य भुगतान के कारण हानि हुई।

(पैरा 3.3)

गैस की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना एनटीपीसी-कायमकुलम की नैफ्था आधारित राजीव गांधी संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना का बहु-ईंधन आधारित संयंत्र, जो ईंधन के

रूप में प्राकृतिक गैस या पुनः गैसीभूत तरलीकृत प्राकृतिक गैस या नैफ्था का उपयोग कर सकता है, में परिवर्तन, किये जाने के परिणामस्वरूप ₹17.27 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैरा 3.4)

भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक निवेश पॉलिसियां निर्धारित की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इक्विटी पोर्टफोलियो की निरंतर निगरानी करके पूंजी की हानि को कम करने और समय पर निस्तारण का निर्णय लेने के लिए 'हानि रोध' सीमाएं शामिल हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्क्रिप के कम लेनदेन होने के आधार पर हानि रोध सीमा ट्रिगर किए जाने के बावजूद जीआईसी ने स्क्रिप का निस्तारण नहीं किया। कंपनी के इक्विटी पोर्टफोलियो में ₹4,541.89 करोड़ के बही-मूल्य के 123 स्क्रिप थे, जो 31 मार्च 2020 तक घटकर ₹1,701.28 करोड़ (20 प्रतिशत से 99.87 प्रतिशत तक मूल्यहास) हो गए। 31 मार्च 2020 तक 123 स्क्रिपों में से, ₹216.28 करोड़ के बही-मूल्य वाले 20 स्क्रिपों की कीमत में बही-मूल्य के 90 फीसदी से अधिक की गिरावट आई थी। लेखापरीक्षा ने जीआईसी द्वारा निर्धारित हानि रोध मापदंडों और 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए शेयर बाजार के आंकड़ों के संबंध में इन 20 स्क्रिपों का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शेयर बाजार में इन स्क्रिपों का कम लेनदेन नहीं हुआ था और यदि जीआईसी ने औसतन बही मूल्य से नीचे के सबसे कम बाजार मूल्य पर भी इन स्क्रिपों की बिक्री कर दी होती, तो वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹134.89 करोड़, ₹66.22 करोड़, ₹28.03 करोड़, ₹8.49 करोड़ और ₹9.19 करोड़ तक की न्यूनतम अनुमानित राशि अर्जित की जा सकती थी। कीमत घटे हुए स्क्रिपों की बिक्री नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप पूंजी/ब्याज की अतिरिक्त हानि हुई है।

(पैरा 4.1)

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-1, जो दिल्ली में परिचालित कंपनी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से माल और सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान के उद्देश्य से नामित केन्द्रीय कार्यालय है, ने उसके द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट की सही राशि का पता लगाने के लिए जीएसटी पोर्टल के साथ इनपुट सेवा बीजकों का मिलान नहीं किया। इसके अलावा, इसकी आईटी प्रणाली में बीजकों के आधार मूल्य और जीएसटी घटक को अलग से दर्ज करने के लिए कार्यक्षमता का अभाव

था, जिसके कारण इसके द्वारा दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (फॉर्म जीएसटीआर-3 बी के माध्यम से) और जीएसटी पोर्टल पर परिलक्षित इनपुट टैक्स क्रेडिट (फॉर्म जीएसटीआर-2 ए में) के बीच महत्पूर्ण अंतर का मिलान करने में बाधा उत्पन्न हुई। परिणामस्वरूप, यह पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सका और 2017-18 से 2020-21 के दौरान इसको ₹97.44 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 4.2)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में चोट, तृतीय पक्ष की मृत्यु या उनकी संपत्ति को हानि से संबंधित थर्ड पार्टी के जोखिमों के प्रति मोटर वाहनों के अनिवार्य बीमा का प्रावधान है। मोटर वाहनों का 'निजी क्षति' के लिए भी बीमा किया जाता है, जो वैकल्पिक है और थर्ड पार्टी के कवर के साथ संयोजन के रूप में दिया जाता है। वाणिज्यिक वाहनों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सार्वजनिक और निजी माल वाहक वाहनों (टाइप 'ए') का थर्ड पार्टी प्रीमियम अन्य श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत वाहनों की तुलना में अधिक राशि का होता है।

एनआईसीएल में, 10 परिचालन कार्यालयों में, 42,333 मोटर बीमा पॉलिसियों (टाइप 'डी') में से, लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए 4,863 पॉलिसियों (11.48 प्रतिशत) का एक नमूना चुना गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,433 पॉलिसियों में जहां टाइप 'डी' वाहनों पर लागू बीमा प्रीमियम प्रभारित किया गया था; वाहनों को संबंधित वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) में माल वाहक वाहनों के रूप में पंजीकृत किया गया था। एनआईसीएल द्वारा जोखिम अंकन के समय वाहनों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप थर्ड पार्टी प्रीमियम में ₹2.96 करोड़ और निजी क्षति प्रीमियम में ₹2.07 करोड़ की कम राशि प्रभारित की गई।

ओआईसीएल में, 2016-17 से 2018-19 के दौरान 23,79,450 पॉलिसियां (14,11,746 माल वाहक वाहन) जारी की गईं। लेखापरीक्षा ने आगे के विश्लेषण के लिए 10,59,755 पॉलिसियों (5,91,936 माल वाहक वाहन) का चुनाव किया और पाया कि 5,175 पॉलिसियों (3,400 वाहनों) में जहां 'माल वाहक वाहन' के लिए टाइप 'ए' की दरों के अनुसार प्रीमियम प्रभारित किया जाना चाहिए था, यह टाइप 'डी' - विविध और विशेष प्रकार के वाहनों की दरों के अनुसार प्रभारित किया गया था। 5,175 पॉलिसियों में से, 2,577 पॉलिसियां (1,703 वाहन) कैरियर कारोबार का परिचालन करने वाली और माल वाहक वाहन रखने वाली एक कंपनी (मैसर्स दिल्ली बड़ौदा रोड कैरियर लिमिटेड) को जारी

की गई थीं, जिसके लिए ₹8.59 करोड़ का थर्ड पार्टी प्रीमियम प्रभारित किए जाने की आवश्यकता थी। इसके सापेक्ष, केवल ₹1.37 करोड़ का थर्ड पार्टी प्रीमियम प्रभारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹7.22 करोड़ का कम प्रीमियम प्रभारित किया गया। अन्य को जारी की गई शेष 2,598 पॉलिसियों (1,701 वाहनों) में ₹3.12 करोड़ का थर्ड पार्टी प्रीमियम प्रभारित किया जाना था। इसके सापेक्ष, केवल ₹1.32 करोड़ का थर्ड पार्टी प्रीमियम प्रभारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.80 करोड़ का कम प्रीमियम प्रभारित किया गया।

(पैरा 4.3)

एमएसटीसी लिमिटेड (कंपनी) ने दिसम्बर 2009 में फैसिलिटेटर मोड के तहत हार्ड कोकिंग कोयले की अधिप्राप्ति के वित्तपोषण के लिए ग्लोबल कोक लिमिटेड (पार्टी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिसम्बर 2011 में उपर्युक्त करार की समाप्ति के बाद कंपनी ने पार्टी की खराब वित्तीय स्थिति से अवगत होने के बावजूद इसे समय-समय पर बढ़ाया। कंपनी ने जुलाई 2019 तक अपनी बकाया देय राशि का भुगतान करने के लिए पार्टी की प्रस्तुति पर विचार करते हुए अपनी ₹31.37 करोड़ के बकाया राशि की वसूली के लिए पार्टी की गिरवी रखी गई सामग्री की जोखिम बिक्री नहीं की। इसके अलावा, अनुकूल मध्यस्थता निर्णय के बावजूद, कंपनी ने इसे लागू करने के लिए कार्रवाई नहीं की। पार्टी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता का दरवाजा खटखटाया और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने अंततः पार्टी के परिसमापन के लिए आदेश दिया (मई 2018)। कंपनी को अंततः गिरवी रखी गई सामग्री के निपटान से प्राप्ति के रूप में परिसमापक से केवल ₹1.35 करोड़ प्राप्त (सितंबर 2019) हुए और पार्टी से बकाया ₹26.87 करोड़ की देय राशि को उसने अपने खाता बही में डूबी रकम के रूप में दर्शाया।

(पैरा 5.1)

सेल/ बोकारो इस्पात संयंत्र में 'स्टील मेल्टिंग शॉप-II में हॉट मेटल डिसल्फराइजेशन स्टेशन' की संस्थापना की परियोजना अनुमोदित (जुलाई 2008) की गई थी और इसे मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (संविदाकार) और मैसर्स डेनियली कोरस बीवी के कंसोर्टियम को अक्टूबर 2008 में ₹51.21 करोड़ और यूरो 1,696,979 के संविदा मूल्य पर प्रदान किया गया था। इस परियोजना को अप्रैल 2010 तक पूरा किया जाना था। सेल ने 31 मार्च 2015 तक (जिसके बाद केवल मध्यस्थता निर्णय भुगतान और कुछ

माइलस्टोन भुगतान किए गए) परियोजना पर ₹53.55 करोड़ व्यय किए और जुलाई 2021 तक लागत बढ़कर ₹67.82 करोड़ हो गई। परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि से 11 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मुख्य रूप से विभिन्न अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सुविधाओं को पूरा नहीं होने के कारण, जिन्हें सेल द्वारा किया जाना था, परियोजना का कमीशनिंग और निष्पादन गारंटी परीक्षण नहीं किया जा सका। सेल/बोकारो इस्पात संयंत्र ने अपने त्रुटिपूर्ण परियोजना प्रबंधन के कारण ₹67.82 करोड़ की धनराशि को अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण हॉट मेटल डिसल्फराइजेशन स्टेशन परियोजना पूरी नहीं हुई और परिणामस्वरूप ₹33.34 करोड़ (दिसंबर 2021 तक) के ब्याज की हानि हुई। संविदाकार को भुगतान की गई स्थगितकरण लागत के कारण ₹15.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी हुआ। इसके अलावा, 7-8 वर्ष पहले संस्थापित उपकरणों को नवीनीकरण की आवश्यकता है, जिसकी अनुमानित लागत ₹57.75 करोड़ है।

(पैरा 5.2)

वर्ष 1960 के दौरान सेल/ राउरकेला इस्पात संयंत्र में संस्थापित गैस होल्डरों का 18 वर्षों का उपयोगी जीवन काल समाप्त हो गया था और तदनुसार सेल बोर्ड ने प्रतिस्थापन के रूप में 1,00,000 घन मीटर कोक ओवन गैस होल्डर की संस्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान (अक्टूबर 2006) किया। कार्य आदेश ₹99.37 करोड़ की लागत से जारी (जुलाई 2007) किया गया और नए गैस होल्डर को चालू (अगस्त 2010) किया गया। यह 7 नवंबर 2012 तक परिचालन में था, जिसके बाद एक दुर्घटना के कारण उपकरण परिचालन में नहीं था।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के कोयला और रसायन विभाग ने गैस होल्डर की मरम्मत के लिए एक प्रस्ताव (जनवरी 2015) दिया, परंतु राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। एक बहु-अनुशासनात्मक समिति का गठन (जून 2020) किया गया जिसने गैस होल्डर के सुधार के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की सिफारिश (सितंबर 2020) की। तथापि, गैस होल्डरों के पुनरुत्थान को आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के बाद कोक ओवन गैस की स्थिति में सुधार को देखते हुए कोक ओवन गैस नेटवर्क के लिए गैस होल्डर की आवश्यकता नहीं थी। अपने आगामी आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम के मद्देनजर नए कोक ओवन गैस होल्डर की

आवश्यकता का निर्धारण करने में प्रबंधन की विफलता के कारण ₹99.37 करोड़ की लागत से संस्थापित गैस होल्डर केवल 27 महीने के उपयोग और नौ साल से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने के बाद निरर्थक हो गया।

(पैरा 5.3)

भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य में एनएच-4 के सतारा-कागल खंड में मौजूदा 2-लेन सड़क को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राधिकृत (फरवरी 1999) किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएचएआई रियायत करार की शर्तों को, विशेष रूप से एस्करो करार को करने में विफलता के कारण राजमार्ग की मरम्मत और अनुरक्षण करने में विफलता के लिए रियायतग्राही (महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड) पर लगाए गए ₹693.24 करोड़ (स्वतंत्र अभियंता द्वारा की गई गणना के अनुसार) की हानि की वसूली करने में असमर्थ था।

(पैरा 7.1)

एनएचएआई ने एनएच-73 के यूपी/हरियाणा बॉर्डर-पंचकूला खंड को ईपीसी मोड पर तीन पैकेजों के अंतर्गत चार लेन का निर्माण करने का कार्य सौंपा, जिसमें दो टोल प्लाजा प्रस्तावित हैं। दो खंडों (पैकेज-I और II) के पूरा होने की निर्धारित तिथि मई 2018 और अप्रैल 2018 में थी, जबकि एक खंड (पैकेज-III) को नवंबर 2018 में निर्धारित पूर्णता तिथि के साथ विलंबित किया गया था। एक टोल प्लाजा (टीपी-1) पैकेज-1 पर और दूसरा टोल प्लाजा (टीपी-2) पैकेज-III पर निर्मित करने की योजना बनाई गई थी। एनएचएआई ने टीपी-2, जो अधूरे खंड पर था, के साथ टीपी-1 की फीस की अधिसूचना के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा, जिसके कारण टीपी-1 के लिए फीस की अधिसूचना में विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, एनएचएआई के पास टीपी-2 को पैकेज-III से पैकेज-II में स्थानांतरित करके अस्थायी टोल प्लाजा का निर्माण करने का विकल्प था, तथापि, इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि पैकेज-III के निर्माण में विलंब हो रहा था, एनएचएआई सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहा और चूंकि पैकेज-III का निर्माण निर्धारित समापन तिथि से 15 माह से अधिक के विलंब से किया गया था, पैकेज-II 20 माह की अवधि से अधिक के लिए टोल-रहित रहा। इससे एनएचएआई/राजकोष को ₹39.92 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(पैरा 7.2)

शास्ति सहित बकाया देय राशियों की वसूली के लिए संविदात्मक प्रावधानों को लागू करने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/इसके विशेष प्रयोजन वाहन की विफलता के परिणामस्वरूप चार टोल प्लाजाओं के एक संविदाकार से ₹21.35 करोड़ की वसूली संदिग्ध है।

(पैरा 7.3)

ऊर्जा क्लस्टर

अध्याय I: कोयला मंत्रालय

एनएलसी इंडिया लिमिटेड

1.1 डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए भत्तों का भुगतान

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) के निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के विचलन में मूल वेतन के 35 प्रतिशत की अधिकतम भत्ता सीमा के अलावा रियायती विद्युत् के गैर-मौद्रिक अनुलाभ को मंजूरी दे दी, जिसके परिणामस्वरूप एनएलसीआईएल और इसकी दो सहायक कंपनियों के कार्यकारियों को ₹17.22 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 1 जनवरी 2017 से लागू बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के वेतनमानों में संशोधन पर दिशानिर्देश जारी किए (अगस्त 2017)। दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुलाभ और भत्ते 'कैफेटेरिया दृष्टिकोण'¹ के तहत कार्यकारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य होंगे, जो मूल वेतन के 35 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन होंगे।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) ने बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों² के संबंध में वेतन, अनुलाभ और भत्तों में संशोधन के लिए कोयला मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (नवंबर 2017)। कोयला मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एनएलसीआईएल को अनुलाभों और भत्तों के लिए मूल वेतन की 35 प्रतिशत की सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया (फरवरी 2018)। एनएलसीआईएल ने 1 जनवरी 2017 से नए वेतन, अनुलाभ और भत्तों को लागू किया (मार्च 2018) जिसमें सामान्य भत्ते के रूप में मूल वेतन का 35 प्रतिशत शामिल है।

¹ कैफेटेरिया दृष्टिकोण नियोक्ताओं द्वारा लाभों के लिए कर्मचारियों की वरीयताओं को समायोजित करने की अनुमति देने वाली पृथक योजना है।

² वे कर्मचारी जिनके रोजगार के नियम और शर्तें किसी भी श्रम करार के तहत कवर नहीं किए गए हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएलसीआईएल के निदेशक मंडल³ ने 1 जनवरी 2017 से प्रभावी डीपीई दिशानिर्देशों (अगस्त 2017) और कोयला मंत्रालय जो एनएलसीआईएल का प्रशासनिक मंत्रालय है, के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एनएलसीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों अर्थात् एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड (एनटीपीएल) और नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) के कार्यकारियों को मूल वेतन के 35 प्रतिशत पर भुगतान किए जा रहे सामान्य भत्ते के अलावा रियायती विद्युत् के गैर-मौद्रिक अनुलाभ को मंजूरी दी थी।

इसके परिणामस्वरूप, एनएलसीआईएल और इसकी दो सहायक कंपनियों के कार्यकारियों को 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए ₹17.22 करोड़⁴ की सीमा तक डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनुलाभों का अनियमित भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि कर्मचारियों को गैर-शहरी क्षेत्रों में स्थित एनएलसीआईएल संयंत्रों और खानों में कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए विद्युत् का छोटा हिस्सा कम दरों पर प्रदान किया जाता है, जैसा कि अन्य सीपीएसई में किया जाता है। इसमें आगे कहा गया कि एनएलसीआईएल द्वारा विद्युत् उत्पादन कंपनी होने के नाते उद्योग पद्धति के अनुसार 200 यूनिट तक रियायती विद्युत् प्रदान की गई है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन करते हुए कहा (अप्रैल 2022) कि कार्यकारियों को कामगारों/गैर-कार्यकारियों के समतुल्य रियायती दरों पर विद्युत् प्रदान की गई थी। मंत्रालय ने आगे कहा कि राज्य सरकारों द्वारा अपने निवासियों को रियायती विद्युत् भी प्रदान की गई थी, जिससे बिना किसी भेदभाव के सभी को लाभ हुआ। इसलिए, इसे सीपीएसई के कर्मचारियों को अनुलाभों और भत्तों के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता।

मंत्रालय और प्रबंधन के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि रियायती दरों पर प्रदान की जाने वाली विद्युत् मूल वेतन के 35 प्रतिशत की अधिकतम अनुलाभों और भत्तों की सीमा से अधिक थी। इसके अलावा, मंत्रालय का यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है कि रियायती विद्युत्

³ कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व 9 जून 2017 से 10 अप्रैल 2019 तक कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में एक अपर सचिव स्तर के अधिकारी ने किया।

⁴ ₹4.11 करोड़ (2017-18); ₹4.49 करोड़ (2018-19); ₹4.98 करोड़ (2019-20); ₹3.64 करोड़ (2020-21) = ₹17.22 करोड़

को अनुलाभों और भत्तों के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि एनएलसीआईएल ने स्वयं रियायती विद्युत् को आयकर उद्देश्य के लिए कर योग्य अनुलाभ के रूप में माना है। मंत्रालय का यह उत्तर भी तर्कसंगत नहीं है कि कार्यकारियों को रियायती दर पर प्रदान की जाने वाली विद्युत् कामगारों/गैर-कार्यकारियों के समतुल्य होनी थी, क्योंकि डीपीई दिशानिर्देश बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों पर लागू होते हैं और कामगारों/गैर-कार्यकारियों पर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, कार्यकारियों को कई अनुलाभ/भत्ते दिए जाते हैं, जो कामगारों/गैर-कार्यकारियों को नहीं दिए जाते हैं, इसलिए समानता का यह तर्क मान्य नहीं है।

इस प्रकार, एनएलसीआईएल ने डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए एनएलसीआईएल, एनटीपीएल और एनयूपीपीएल के कार्यकारियों को रियायती विद्युत् के रूप में ₹17.22 करोड़ के भत्तों का अनियमित भुगतान किया, जो प्रकृति में आवर्ती हैं।

1.2 डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए कार्य निष्पादन संबंधी वेतन का भुगतान

एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों से विचलन में सहायक कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर अपने कार्यकारियों को कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन के लिए ₹8.91 करोड़ के भुगतान को मंजूरी दी।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) की एक सहायक कंपनी, नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल)⁵ को नवंबर 2012 में घाटमपुर, उत्तर प्रदेश में 3x660 मेगावाट विद्युत् परियोजना की संस्थापन के उद्देश्य से निगमित किया गया था। भारत सरकार ने जुलाई 2016 में परियोजना के लिए मंजूरी दी थी। यह परियोजना निर्माणाधीन है (जून 2022) और मार्च 2023 तक इसकी पहली इकाई शुरू होने की उम्मीद है। संयुक्त उद्यम करार के अनुसार धारक कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति आधार⁶ पर एनयूपीपीएल में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

⁵ एनएलसी इंडिया और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी वाला एक संयुक्त उद्यम।

⁶ अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति एक विशिष्ट अवधि के लिए सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों की गतिविधियों के लिए कार्यकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं के प्लेसमेंट को संदर्भित करता है, जिसे शुरू में तीन वर्ष और एनएलसीआईएल के विवेक पर प्रत्येक अवसर पर दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2007 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर से नीचे और बोर्ड स्तर के कार्यकारियों के साथ-साथ गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के वेतनमान में संशोधन करते हुए निर्देश⁷ जारी किए थे, जिसमें यह दर्शाया गया था कि सीपीएसई के कार्यकारियों को दिया जाने वाला कार्य निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) सीधे सीपीएसई के लाभ से जोड़ा जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया कि अन्य सीपीएसई में प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले कार्यकारी, आदाता सीपीएसई पर लागू पीआरपी आहरित करने के हकदार थे। पीआरपी को लाभ से जोड़ने के उक्त प्रावधान को अगस्त 2017 में बाद के वेतन संशोधन के दौरान डीपीई द्वारा दोहराया गया था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, पीआरपी एनयूपीपीएल में प्रतिनियुक्त एनएलसीआईएल के कार्यकारियों पर लागू नहीं था, क्योंकि परियोजना कार्यान्वयन चरण में थी और वित्तीय वर्ष 2021-22 तक वहाँ कोई लाभ नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनयूपीपीएल ने 2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान एनयूपीपीएल में प्रतिनियुक्ति पर एनएलसीआईएल के कार्यकारियों को पीआरपी के रूप में ₹8.91 करोड़⁸ का भुगतान किया। प्रतिनियुक्त कार्यकारियों के लिए उपरोक्त पीआरपी को एनएलसीआईएल के निदेशक मंडल द्वारा क्रमशः वर्ष 2014-15 से 2016-17 और 2017-18 से 2019-2020 के लिए एनएलसीआईएल के एकल लाभ और समेकित लाभ के आधार पर अनुमोदित किया गया था। चूंकि एनयूपीपीएल कार्यान्वयन चरण (जून 2022) में था, इसलिए कार्यकारियों को पीआरपी का भुगतान डीपीई के उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार, एनएलसीआईएल ने ₹8.91 करोड़ के पीआरपी को मंजूरी दी, जिसका डीपीई दिशानिर्देशों से विचलन में सहायक कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर गए एनएलसीआईएल के कार्यकारियों को एनयूपीपीएल द्वारा भुगतान किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2021) कि एनएलसीआईएल के कार्यकारियों को अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति के आधार पर एनयूपीपीएल में भेजा गया था। ये कार्यकारी एनएलसीआईएल के उपस्थिति पंजिका पर बने हुए हैं और प्रशासनिक नियंत्रण सहित उनके वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें एनएलसीआईएल के नियमों और विनियमों के तहत शासित होती हैं।

⁷ दिनांक 26 नवम्बर 2008 के ओएम संख्या 2 (70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XVII/08 के माध्यम से।

⁸ 2014-15: ₹1.02 करोड़; 2015-16: ₹1.00 करोड़; 2016-17: ₹1.71 करोड़; 2017-18: ₹1.70 करोड़; 2018-19: ₹1.28 करोड़; 2019-20: ₹2.20 करोड़

इसमें आगे कहा गया है कि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई के समग्र लाभ को पीआरपी की गणना के लिए लिया जाएगा और एनएलसीआईएल द्वारा अपनी सहायक कंपनियों के साथ एक विशिष्ट सीपीएसई होने के नाते, पीआरपी के भुगतान के लिए समेकित लाभ को ध्यान में रखा गया था। मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन करते हुए कहा (अप्रैल 2022) कि कर्मचारियों को एनयूपीपीएल में तैनात करना बेहद मुश्किल होगा यदि पीआरपी का भुगतान इस आधार पर नहीं किया जाता है कि एनयूपीपीएल ने लाभ प्राप्त नहीं किया है क्योंकि उसने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है।

मंत्रालय और प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत नहीं है कि एनएलसीआईएल और एनयूपीपीएल अलग-अलग सीपीएसई थे। डीपीई के अनुदेशों के अनुसार, सीपीएसई के कार्यकारियों को देय पीआरपी सीधे सीपीएसई के लाभ से जुड़ा हुआ था। एनएलसीआईएल के एकल/समेकित लाभ के आधार पर एनयूपीपीएल के कार्यकारियों को पीआरपी का भुगतान करना गलत था क्योंकि इसने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया था। इसके अलावा, सहायक कंपनियों में एनएलसीआईएल कर्मचारियों की अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति शर्तों के अनुसार, इस प्रकार तैनात कार्यकारियों और कर्मचारियों को सहायक कंपनी के कार्यकारी और अन्य कर्मचारियों के रूप में माना जाएगा। मूल कंपनी की सेवा शर्तें, ऐसे मुआवजे को छोड़कर जो सीधे लाभ या भौतिक लक्ष्य उपलब्धि से संबंधित हैं जैसे की पीआरपी, अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारियों पर लागू होंगी। इसलिए, एनयूपीपीएल के कार्यकारियों को पीआरपी का भुगतान सही नहीं था।

इस प्रकार, एनएलसीआईएल यानी धारक कंपनी के लाभ पर सहायक कंपनी अर्थात एनयूपीपीएल के कार्यकारियों को पीआरपी स्वीकार्यता का गलत विचार करने के परिणामस्वरूप 2014-15 से 2019-20 के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹8.91 करोड़ का भुगतान किया गया।

सिफारिश संख्या 1: मंत्रालय लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारियों को किए गए अपात्र पीआरपी भुगतान की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर सकता है और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

अध्याय II: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

2.1 पट्टे के नवीकरण में देरी के कारण ₹16.93 करोड़ का परिहार्य व्यय

हल्दिया तटीय संस्थापन के दीर्घकालिक पट्टे के नवीकरण के प्रस्ताव के अनुमोदन में देरी के कारण ₹16.93 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, सुपीरियर केरोसिन तेल आदि जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण के लिए हल्दिया तटीय संस्थापन (संस्थापन) की स्थापना की थी। बीपीसीएल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट (पोर्ट ट्रस्ट) से संस्थापन के लिए 20 वर्ष की अवधि के लिए 1.76 लाख वर्ग मीटर¹ की कुल जमीन पट्टे पर ली थी और यह 17 फरवरी 2013 को समाप्त हो गई।

बीपीसीएल ने मूल पट्टा किराए का भुगतान किया, लेकिन बढ़े हुए पट्टा किराए के भुगतान में अनियमित था, जो प्रत्येक वर्ष बढ़ाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.81 करोड़ के ब्याज के साथ ₹6.03 करोड़ का पट्टा किराया बकाया हो गया। पोर्ट ट्रस्ट ने बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के कारण पट्टे के नवीकरण के बीपीसीएल के प्रस्ताव (जनवरी 2013) को अस्वीकार (दिसंबर 2013) कर दिया। बीपीसीएल ने पोर्ट ट्रस्ट द्वारा कई बार अनुरोध² के बाद जून 2014 में ही संस्थापन के बकाया पट्टा किराए के रूप में ₹6.03 करोड़ के बकाया का भुगतान किया। संस्थापन के पट्टे के नवीकरण के लिए बीपीसीएल के अनुरोध को पोर्ट ट्रस्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि उसने ब्याज की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था। आखिरकार, बीपीसीएल ने जनवरी 2016 में पोर्ट ट्रस्ट को पट्टे के किराए के देरी से भुगतान के लिए ब्याज के रूप में ₹1.81 करोड़ का भुगतान किया। चूंकि फरवरी 2013 में पट्टा समाप्त हो गया था और इसका नवीकरण नहीं किया गया था, इसलिए पोर्ट ट्रस्ट ने अंतरिम अवधि के दौरान मासिक लाइसेंस फीस का भुगतान करके उक्त भूमि के उपयोग की अनुमति दी।

¹ एचएएल संख्या 733 के तहत 1,74,865 वर्ग मीटर और एचएएल संख्या 1454 के तहत 720 वर्ग मीटर।

² 17 दिसंबर 2012, 26 मार्च 2013, 9 सितंबर 2013, 2 दिसंबर 2013, 11 दिसंबर 2013 और 30 जनवरी 2014।

पोर्ट ट्रस्ट ने बीपीसीएल को ₹36.71 करोड़ (अर्थात पट्टे किराए के रूप में ₹32.06 करोड़ और सेवा कर के रूप में ₹4.65 करोड़) के कुल अग्रिम प्रीमियम के भुगतान पर 30 वर्ष के लिए संस्थापन भूमि के पट्टे के नवीकरण के लिए एक प्रस्ताव दिया (मार्च 2016)। सात दिनों के भीतर प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति से अवगत कराने का भी अनुरोध किया गया। पोर्ट ट्रस्ट के बार-बार अनुरोध के बावजूद, कंपनी को संस्थापन भूमि के पट्टे के नवीकरण के लिए पोर्ट ट्रस्ट के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति (नवंबर 2017) में 21 महीने (मार्च 2016 से नवंबर 2017) लगे। इसी बीच, पट्टे के किराए की अनुसूची को 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर के साथ बढ़ाया गया। इस प्रकार, 30 वर्षों के लिए पट्टे के नवीकरण के लिए कुल अग्रिम प्रीमियम (18 फरवरी 2013 से 17 फरवरी 2043 की अवधि के दौरान) बढ़कर ₹53.64 करोड़ (अर्थात पट्टा किराया के रूप में ₹45.46 करोड़ और जीएसटी के रूप में ₹8.18 करोड़) हो गया और बीपीसीएल ने फरवरी 2013 से नवंबर 2018 तक भुगतान की गई मासिक लाइसेंस फीस को समायोजित करने के बाद भुगतान किया (नवंबर 2018)। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- i. प्रबंधन ने पट्टा किराया और उस पर ब्याज के अपने पहले के बकाया का भुगतान करने में अनावश्यक देरी की। तीन वर्ष बीत जाने के बाद जनवरी 2016 में इसे मंजूरी दी गई थी।
- ii. हालांकि पोर्ट ट्रस्ट ने मार्च 2016 में ₹36.71 करोड़ के अग्रिम भुगतान पर संस्थापन भूमि के 30 वर्ष के पट्टे के लिए एक प्रस्ताव की पेशकश की थी, लेकिन बीपीसीएल ने इस पर जल्दी से अम्ल करने के लिए कोई पहल नहीं की।
- iii. प्रबंधन ने पोर्ट ट्रस्ट से दो अनुस्मारक के बाद भी नए पट्टे को देने के लिए पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित वित्तीय शर्तों पर अपनी स्वीकृति से अवगत नहीं कराया।
- iv. बीपीसीएल इस तथ्य से भलीभांति परिचित था कि पोर्ट ट्रस्ट की सभी भूमि भारत सरकार द्वारा तैयार की गई भूमि नीति द्वारा विनियमित और शासित थी और किराए की अनुसूची को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। साथ ही प्रस्ताव स्वीकार करने में देरी के कारण किराया भी बढ़ जाएगा, लेकिन यह समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा।

इस प्रकार, प्रबंधन द्वारा पट्टे के नवीकरण के लिए पोर्ट ट्रस्ट की पेशकश की स्वीकृति (नवंबर 2017) में देरी के परिणामस्वरूप किराया की अनुसूची और कर की दर में वृद्धि के

कारण 30 वर्ष के पट्टे के लिए अग्रिम प्रीमियम बढ़कर ₹53.64 करोड़ हो गया। इसके परिणामस्वरूप प्रबंधन द्वारा ₹16.93 करोड़³ (अर्थात् पट्टे के किराए के रूप में ₹13.40 करोड़ और जीएसटी के रूप में ₹3.53 करोड़) का परिहार्य व्यय किया गया।

प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2021) कि संस्थापन भूमि के पट्टे के किराए के प्रति देय राशि प्रोदभूत की गई थी क्योंकि पोर्ट ट्रस्ट ने एकतरफा रूप से पट्टे के किराए को दो प्रतिशत के बजाय पांच प्रतिशत बढ़ा दिया था (2009)। बीपीसीएल ने पुरानी दरों के अनुसार किराया देना जारी रखा। इसके अलावा बीपीसीएल ने समय पर ब्याज के लिए बकाया राशि का भुगतान नहीं किया क्योंकि पट्टा करार में किसी दंडात्मक ब्याज का प्रावधान नहीं था। पोर्ट ट्रस्ट के पास पट्टे के किराए में कमी और दंडात्मक ब्याज माफ करने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बीपीसीएल को जनवरी 2016 में सभी बकाया का भुगतान करना पड़ा था। यह भी कहा गया कि पोर्ट ट्रस्ट की पेशकश को स्वीकार करने में देरी के लिए पूरी तरह से कंपनी जिम्मेदार नहीं थी क्योंकि लेनदेन में दो सरकारी संगठन शामिल थे और बीपीसीएल को उचित शासन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन लेने थे।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि किराए की संशोधित अनुसूची के अनुसार फरवरी 2009 से, किराए में पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्रभावी होनी चाहिए। इसलिए पट्टे के किराए के बकाया के भुगतान की दिशा में प्रबंधन द्वारा की गई देरी तर्कसंगत नहीं थी। इसके अतिरिक्त, दण्डात्मक ब्याज के संबंध में प्रबंधन का उत्तर सही नहीं है क्योंकि पट्टा किराए की बकाया राशि के लिए पट्टा करार⁴ के अनुसार 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लागू था। बीपीसीएल इस तथ्य से भी अवगत था कि संस्थापन के सुचारू संचालन के लिए पोर्ट ट्रस्ट से दीर्घकालिक पट्टा आवश्यक था। पोर्ट ट्रस्ट ने न केवल समय बढ़ाने की अनुमति दी, बल्कि बीपीसीएल से पट्टे के नवीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति से अवगत कराने का भी कई बार अनुरोध किया। हालांकि, कंपनी ने इस संबंध में समय पर कार्रवाई नहीं की और पोर्ट ट्रस्ट के प्रस्ताव को 21 महीने के अंतराल के बाद स्वीकार कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹16.93 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। अतः सुशासन को

³ ₹53.64 करोड़ - ₹36.71 करोड़

⁴ पट्टा करार के ट्रस्टियों के साथ पट्टेदार अनुबंध की क्रम संख्या 19।

सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की याचिका पर देरी बीपीसीएल के वित्तीय और परिचालन हित में नहीं थी।

इस प्रकार, बीपीसीएल को संस्थापन के पट्टे के नवीकरण के लिए अनुमोदन में देरी के कारण ₹16.93 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

इस मामले की सूचना जनवरी 2022 में मंत्रालय को दी गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2022)।

सिफारिश संख्या 2: प्रबंधन भूमि पट्टे के नवीकरण के लिए पोर्ट ट्रस्ट की पेशकश का उत्तर देने में देरी के लिए जिम्मेदारी तय करे और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपयुक्त उपाय भी करें।

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

2.2 डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कर्मचारियों को अनियमित भुगतान

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों और प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दीर्घ सेवा योजना/सेवानिवृत्ति योजना के तहत कर्मचारियों को ₹9.09 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया था।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देश (नवम्बर 1997) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को अनुग्रह, मानदेय, पुरस्कार, विशेष प्रोत्साहन आदि के भुगतान पर तब तक रोक लगाता है जब तक कि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राशि प्राधिकृत न हो।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की सहायक कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) अपने कर्मचारियों को सेवा की अवधि के आधार पर सोने के सिक्कों के रूप में चार दशकों से अधिक समय से दीर्घ सेवा पुरस्कार/सेवानिवृत्ति पुरस्कार प्रदान कर रहा था। हालांकि, सभी तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के निर्देशानुसार जो विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर आधारित थी, इसे बंद कर दिया गया था (फरवरी 2015), क्योंकि यह डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था।

इसके बाद सीपीसीएल ने फरवरी 2015 से पूर्वव्यापी रूप से दीर्घ सेवा/सेवानिवृत्ति पुरस्कार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजना की समीक्षा की (मार्च 2016)। एक संशोधित योजना को सीपीसीएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था (नवंबर 2016)। संशोधित योजना के अनुसार, कर्मचारियों को एक प्री-पेड कार्ड दिया जाएगा, जिसका मूल्य सेवा की अवधि पर निर्भर करता है। 15/25 वर्ष पूरा करने वाले कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रति कर्मचारी पुरस्कार की राशि ₹1,500 और उन कर्मचारियों को ₹2,500 थी जिन्होंने 30/35 वर्ष पूरे कर लिए थे। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली थी, वे भी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए ₹2,500 की दर से सेवानिवृत्ति पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीपीसीएल की संशोधित योजना सोने के सिक्कों को जारी करने की पुरानी योजना का प्री-पेड कार्ड द्वारा एक प्रतिस्थापन था, जिसे प्रशासनिक मंत्रालय की मंजूरी के बिना लागू किया गया था और नवंबर 2017 के डीपीई दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन था।

इस प्रकार, सीपीसीएल ने डीपीई दिशानिर्देशों और प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 2015-16 से 2021-22 (जनवरी 2022 तक) की अवधि के लिए संशोधित योजना के तहत ₹9.09 करोड़ का व्यय किया, जैसा कि तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए संशोधित योजना के तहत व्यय

वर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
2015-16	0.79
2016-17	0.78
2017-18	0.98
2018-19	1.87
2019-20	1.87
2020-21	1.72
2021-22	1.08
कुल	9.09

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि डीपीई का 20 नवंबर 1997 का ओएम सीपीसीएल के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होता जो प्रति माह ₹3,500 से अधिक वेतन ले रहे थे। इसमें आगे कहा गया है कि डीपीई दिशानिर्देशों और सीपीसीएल के दीर्घ सेवा पुरस्कार के बीच कोई संबंध नहीं था। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक उद्यमब्यूरो (बीपीई) के निर्देशों पत्र संख्या 7 (3)/79-बीपीई (जीएम-1) दिनांक 14 फरवरी 1983 के आधार पर बोर्ड⁵ के अनुमोदन से दीर्घ सेवा पुरस्कार का भुगतान किया गया था और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार 2015 में दीर्घ सेवा पुरस्कार का भुगतान बंद करने के साथ सीपीसीएल ने कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा को स्वीकृत एवं पुरस्कृत करने के लिए नवंबर 2016 में योजना को पुनःस्थापित किया। प्रबंधन ने यह भी तर्क दिया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी योजना के बारे में सूचित किया गया था, जिसके लिए मंत्रालय से कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी। अंत में, दीर्घ सेवा पुरस्कार जैसे प्रथागत विशेषाधिकार को वापस लेना एक कर्मचारी की सेवा शर्तों को बदलने के बराबर होगा।

उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के प्रति देखा जाना चाहिए:

- डीपीई दिशा-निर्देशों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, जो प्रशासनिक मंत्रालय है, के निर्देशों के बाद बीपीई के निर्देश (फरवरी 1983) अब प्रासंगिक नहीं हैं।
- डीपीई दिशानिर्देश (नवम्बर 1997) में कहा गया है कि सीपीएसई द्वारा तब तक कोई अनुग्रह, मानदेय, पुरस्कार इत्यादि का भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधिवत अनुमोदित प्रोत्साहन योजनाओं के तहत राशि प्राधिकृत न हो। संशोधित योजना पुरानी योजना में जारी सोने के सिक्कों को प्री-लोडेड कार्ड से बदलना था जो डीपीई दिशानिर्देशों (नवंबर 1997) के उल्लंघन के समान था।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दीर्घ सेवा पुरस्कार का भुगतान बंद करने का भी निर्देश दिया था। चूंकि यह योजना प्रदान की गई सेवा की अवधि पर आधारित थी, इसलिए डीपीई दिशानिर्देशों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दीर्घ सेवा/सेवानिवृत्ति पुरस्कार का भुगतान अनियमित था।

⁵ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व 2016-17 के दौरान अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में एक उप सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया था।

- प्रशासनिक मंत्रालय (एमओपीएनजी) से टिप्पणियां प्राप्त न होने को योजना के लिए अनुमोदन के रूप में नहीं माना जा सकता है। नवंबर 2016 में जब योजना बहाल की गई थी तब कंपनी के निदेशक मंडल में मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को नियुक्त किए जाने के बावजूद सीपीसीएल को योजना की मंजूरी नहीं मिल सकी थी। इसलिए, सद्भावना के रूप में सीपीसीएल द्वारा दीर्घ सेवा पुरस्कार का भुगतान अनियमित प्रकृति का है।
- प्रबंधन का यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है कि दीर्घ सेवा पुरस्कार जैसे प्रथागत विशेषाधिकार को वापस लेना किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों में बदलाव के समान होगा क्योंकि लंबी और संतोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए पुरस्कार के भुगतान के लिए प्रोत्साहन योजना के रूप में एक प्रथागत रियायत या विशेषाधिकार सीपीसीएल के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का हिस्सा नहीं है। दीर्घ सेवा पुरस्कार का भुगतान न तो नियुक्ति के प्रस्ताव में उल्लिखित है और न ही भर्ती नियमों का हिस्सा है।

इस प्रकार, दीर्घ सेवा पुरस्कार योजना के तहत सीपीसीएल द्वारा किया गया ₹9.09 करोड़ का व्यय डीपीई दिशानिर्देशों और प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन था।

इस मामले की सूचना फरवरी 2022 में मंत्रालय को दी गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2022)।

सिफारिश संख्या 3: डीपीई दिशानिर्देशों एवं मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारियों को किए गए दीर्घ सेवा पुरस्कार/सेवानिवृत्ति पुरस्कार के अनियमित भुगतान की वसूली के लिए मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई शुरू कर सकता है एवं इसके लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

2.3 वाहनों के 'संचालन और रखरखाव' व्यय के भुगतान के रूप में कार्यकारियों को अनुचित लाभ

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए वाहनों के 'संचालन और रखरखाव' का भुगतान करके अपने कार्यकारियों को ₹2,609.47 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने कार्यालय जापन (ओएम)⁶ दिनांक 26 नवंबर 2008 और दिनांक 3 अगस्त 2017 के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारियों के साथ-साथ गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के वेतन और भत्तों में संशोधन को मंजूरी दे दी है जो क्रमशः 1 जनवरी 2007 और 1 जनवरी 2017 से प्रभावी है। उक्त कार्यालय जापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि सीपीएसई कैफेटेरिया दृष्टिकोण का अनुसरण कर सकते हैं जिससे कार्यकारियों को मूल वेतन के 50 प्रतिशत (35 प्रतिशत⁷ पर संशोधित) की अधिकतम सीमा के अधीन अनुलाभों और भत्तों में से चुनने की अनुमति दे सकते हैं।

केवल चार भत्ते, अर्थात् पूर्वोत्तर और लद्दाख क्षेत्र में सेवा करने के लिए स्थान आधारित प्रतिपूरक भत्ता, अंडमान और निकोबार के द्वीप क्षेत्रों में सेवा करने के लिए प्रतिपूरक भत्ता, कठिन और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए विशेष भत्ता और चिकित्सा अधिकारियों के लिए गैर-अभ्यास भत्ता मूल वेतन के 50 प्रतिशत (35 प्रतिशत पर संशोधित) की सीमा के दायरे से बाहर रखा गया था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि

क. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने अनुलाभों और भत्तों के भुगतान के लिए कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत शामिल परिवहन भत्ते के रूप में ₹800 प्रति माह की निश्चित राशि पर विचार किया था। कार्यकारी स्तर के लिए लगभग ₹7,600 से ₹49,300 प्रति माह की सीमा तक व्यक्तिगत वाहनों के लिए वाहन संचालन और रखरखाव व्यय (सीआरएमई) से संबंधित शेष राशि कैफेटेरिया दृष्टिकोण के बाहर रखी गई थी।

अप्रैल 2009 से अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान, आईओसीएल ने अपने कार्यकारियों को परिवहन भत्ते के अलावा सीआरएमई के लिए ₹1,447.72 करोड़ की राशि का भुगतान किया। कैफेटेरिया दृष्टिकोण की 50 प्रतिशत (35 प्रतिशत पर संशोधित) सीमा के अलावा

⁶ जापन संख्या 2 (70)/08 डीपीई-(डब्ल्यूसी)-जीएल-xvi/08 दिनांक 26 नवंबर 2008 में प्रावधान है कि निदेशक मंडल मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन कार्यकारियों की विभिन्न श्रेणियों के स्वीकार्य भत्तों और अनुलाभों पर निर्णय लेगा जिसमें (i) मूल वेतन के 12.5 प्रतिशत तक सीमित पूर्वोत्तर भत्ता, (ii) भूमिगत खानों के लिए भत्ता मूल वेतन के 15 प्रतिशत तक सीमित, (iii) लोक उद्यम विभाग के परामर्श से संबंधित मंत्रालयों द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित दुर्गम और दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत तक विशेष भत्ता और (iv) चिकित्सा अधिकारियों के लिए मूल वेतन के 25 प्रतिशत तक सीमित गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता शामिल नहीं है।

⁷ संख्या डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-xiii /17 दिनांक 3 अगस्त 2017 ।

वाहनों के 'संचालन और रखरखाव' व्यय का भुगतान डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप आईओसीएल द्वारा कार्यकारियों को अनुचित लाभ दिया गया था। आईओसीएल ने कहा (जुलाई 2022) कि यह निगम की जिम्मेदारी है कि वह कर्मचारियों को व्यावसायिक आवश्यकताओं के संबंध में यात्रा करने के लिए पर्याप्त माध्यम और साधन प्रदान करे। सीआरएमई परिवहन के लिए वाहनों को किराए पर लेने की तुलना में अधिक किफायती और प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक है। इसके अलावा कार्यकारियों को, प्रमुख अधिकारियों के अलावा 21 जनवरी 2013 के डीपीई ओएम के अनुसार वाहन प्रतिपूर्ति या वाहन भत्ते का भुगतान किया जा सकता है। आईओसीएल ने आगे कहा कि तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) ने अपनी रिपोर्ट में क्षेत्रीय/परिचालन आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श किया था जो प्रत्येक सीपीएसई के लिए विशिष्ट हैं और इसके व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हैं। पीआरसी ने देखा कि ऐसे कार्य संबंधी/प्रशासनिक व्यय के लिए मुआवजे/प्रतिपूर्ति को व्यक्तिगत प्रकृति के अनुलाभों/भत्तों के रूप में नहीं माना जा सकता। इस मामले में इस तरह का प्रशासनिक व्यय कार्यकारियों को वाहन प्रतिपूर्ति पर किया गया व्यय है। आईओसीएल ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आधिकारिक उद्देश्यों के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वाहन पर किए गए व्यय, या तो प्रत्यक्ष या प्रतिपूर्ति को कर योग्य अनुलाभ के रूप में नहीं माना जा सकता।

आईओसीएल के उत्तर को निम्नलिखित के मद्देनज़र में देखा जाए:

- i. डीपीई ने समय-समय⁸ पर पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 26 नवंबर 2008/3 अगस्त 2017 के अपने ओएम में उल्लिखित भत्तों के अलावा कोई भी भत्ता/लाभ/अनुलाभ 'कैफेटेरिया दृष्टिकोण' की सीमा के बाहर स्वीकार्य नहीं हैं।
- ii. कर्मचारियों को कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाता है। सीआरएमई का भुगतान संगठन में उनके स्तर के आधार पर व्यक्तिगत वाहनों के लिए किया जाता है न कि वास्तविक आधार पर और इसलिए यह प्रतिपूर्ति हेतु अर्हता प्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार, सीआरएमई के लिए भुगतान प्रतिपूर्ति के बजाय भत्ते की श्रेणी में आता है और इसे कैफेटेरिया दृष्टिकोण में शामिल किया जाना चाहिए था।

⁸ 8 अप्रैल 2009, जून 2011, जून 2012 और जून 2013 ।

- iii. कंपनी के इस तर्क को उचित नहीं ठहराया जा सकता कि वह सीआरएमई का भुगतान विशुद्ध रूप से परिचालन गतिविधियों के लिए कर रही है, क्योंकि वह दैनिक गतिविधियों के लिए अपने सभी विभागों/स्थानों के लिए वार्षिक संविदा आधार पर वाहनों को किराए पर लेने के अलावा अपने कार्यकारियों को 15 किलोमीटर से अधिक की स्थानीय आवाजाही के लिए स्थानीय वाहन प्रभार के आधार पर अतिरिक्त भुगतान भी कर रही है।
- iv. तीसरी पीआरसी सिफारिश (नवंबर 2016) सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गयी थी (मई 2017) कि सीपीएसई, सरकार⁹ के अनुमोदन से, अनुलाभों और भत्तों पर अनुशंसित सीमा के दायरे से बाहर अपने काम से संबंधित/प्रशासनिक व्यय को विनियमित करने की अनुमति दे सकते हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के मामले में जहां लेखापरीक्षा ने इसी तरह के मुद्दे को दर्शाया था, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निर्देश दिया (अक्टूबर 2018) कि कैफेटेरिया की सीमा के अलावा कार्यकारियों को भुगतान किए गए वाहनों के संचालन और रखरखाव व्यय का भुगतान डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन है और इस संबंध में भुगतान किए गए किसी भी अनधिकृत भत्ते को उपरोक्त उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुरूप वसूल किया जाए।
- v. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनज़र, जैसा कि ऊपर कहा गया है, आधिकारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले कर्मचारी के वाहन पर नियोक्ता द्वारा की गई प्रतिपूर्ति या वास्तविक राशि को कर योग्य अनुलाभ के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, आयकर नियमों के अनुसार, प्रतिपूर्ति की पात्र राशि हेतु विवरण सहित इस आशय का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है कि व्यय पूरी तरह से और विशेष रूप से कार्यालय कार्यों के निष्पादन के लिए किया गया था। कंपनी द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है और साथ ही कंपनी की ओर से अपने कार्यकारियों को इसके अनुपालन के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

इस प्रकार, मूल वेतन के 50 प्रतिशत (35 प्रतिशत पर संशोधित) के अलावा सीआरएमई का भुगतान डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था और इसके परिणामस्वरूप आईओसीएल के कार्यकारियों को ₹1,447.72 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।

⁹ सचिवों की समिति की 12 मई, 2017 को हुई बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 29 मई, 2017 के कार्यालय जापन संख् या 252/2/1/2017 और दिनांक 16 अगस्त, 2017 के कार्यालय जापन के माध्यम से परिचालित किया गया, जिसमें तीसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर मंत्रिमंडल के निर्णय को परिचालित किया गया।

इस मामले की सूचना सितंबर 2022 में मंत्रालय को दी गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2022)।

ख. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने अनुलाभों और भत्तों के भुगतान के लिए कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत शामिल परिवहन भत्ते के रूप में ₹800 प्रति माह की राशि निश्चित की गई। निजी वाहनों के लिए वाहन रखरखाव प्रतिपूर्ति व्यय (सीएमआरई) से संबंधित शेष राशि कार्यकारी स्तरों के लिए ₹6,445 से ₹23,315 प्रति माह तक कैफेटेरिया दृष्टिकोण के बाहर रखी गई थी।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, ओएनजीसी ने अपने कार्यकारियों को सीएमआरई के लिए ₹732.93 करोड़ की राशि का भुगतान किया। कैफेटेरिया दृष्टिकोण की 35 प्रतिशत की सीमा के अलावा वाहन के 'संचालन और रखरखाव' व्यय का भुगतान डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप ओएनजीसी द्वारा कार्यकारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था।

ओएनजीसी ने कहा (जनवरी 2022) कि वह दूर-दराज के क्षेत्रों और पूर्वोत्तर जैसे अधिक दूरदराज के क्षेत्रों में चौबीसों घंटे संचालन का काम करती है। कई बार, कर्मचारियों को असामयिक इयूटी पर बुलाया जाता है जब सार्वजनिक वाहन मिलना मुश्किल होता है। कर्मचारियों की नौकरी की जिम्मेदारियों में व्यवसाय को बढ़ावा देने और परिचालन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए स्थानीय आवाजाही शामिल है। इस प्रकार सीएमआरई की प्रतिपूर्ति को अनुलाभों और भत्तों का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। कर्मचारी द्वारा पिछले महीने वाहन के 'संचालन और रखरखाव' के लिए पहले से ही खर्च की गई राशि, वास्तविक आधार पर स्तर-वार सीमा के अधीन है और केवल सीएमआरई के रूप में इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। इसमें आगे कहा गया है कि सीएमआरई परिवहन के लिए वाहनों को किराए पर लेने की तुलना में अधिक किफायती और प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक है। इसके अलावा, प्रमुख अधिकारियों के अलावा अन्य कार्यकारियों को 21 जनवरी 2013 के डीपीई ओएम के अनुसार वाहन प्रतिपूर्ति या वाहन भत्ते का भुगतान किया जा सकता है।

ओएनजीसी का उत्तर निम्नलिखित के मद्देनजर मान्य नहीं है:

- i. कार्यकारियों को पूर्वोत्तर राज्यों और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत भत्तों और अनुलाभों के अलावा विशेष भत्तों का भुगतान किया जाता है। वाहन के लिए, कर्मचारियों को कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत परिवहन भत्ते

का भुगतान किया जाता है। कर्मचारियों को संगठन में उनके स्तर के आधार पर व्यक्तिगत वाहनों के लिए सीएमआरई का भुगतान किया जाता है, न कि वास्तविक आधार पर और इसलिए यह प्रतिपूर्ति के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार सीएमआरई का भुगतान प्रतिपूर्ति के बजाय भत्ते की श्रेणी में आता है और इसे कैफेटेरिया दृष्टिकोण में शामिल किया जाना चाहिए था।

- ii. ओएनजीसी का यह तर्क कि कर्मचारी को वाहन उपलब्ध कराने की लागत सीएमआरई से कहीं अधिक है, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी कार्यकारी, चाहे उनका स्तर कुछ भी हो, दूर-दराज के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इस प्रकार, यह तर्क सही नहीं है।
- iii. दिनांक 21 जनवरी 2013 के डीपीई ओएम के आधार पर वाहन भत्ते की स्वीकार्यता पर ओएनजीसी का तर्क भी सही नहीं है क्योंकि ओएनजीसी ने 3 अगस्त 2017 के डीपीई ओएम के अनुसार कैफेटेरिया दृष्टिकोण अपनाया था, जो अनुलाभों और भत्तों के लिए 35 प्रतिशत की सीमा का प्रावधान करता है।

इस प्रकार, डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित सीमा के अलावा वाहनों के 'संचालन एवं रख रखाव' व्यय के भुगतान से ओएनजीसी के कार्यकारियों को ₹732.93 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

इस मामले की सूचना फरवरी 2022 में मंत्रालय को दी गई थी; उनका जवाब प्रतीक्षित है (अगस्त 2022)।

ग. गेल ने अपने सभी कर्मचारियों/कार्यकारियों के लिए वाहन अनुरक्षण व्यय प्रतिपूर्ति (सीएमईआर) नामक एक योजना (24 फरवरी 1986) शुरू की थी ताकि उन्हें अपने वाहन के स्वामित्व और रखरखाव के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और आधिकारिक उद्देश्य के लिए की गई यात्राओं पर ऐसे वाहनों का उपयोग किया जा सके जिससे गेल के वाहनों के उपयोग पर मांग कम हो सके। योजना के अनुसार, कर्मचारी मासिक सीएमईआर प्रभारों (1 अगस्त 2003 से 1 अक्टूबर 2010 की अवधि के दौरान) के हकदार थे, जो क्रमशः चार पहिया और दोपहिया वाहनों के लिए ₹528 से ₹4,919 और ₹110 से ₹588 प्रति माह के बीच थे। इसके बाद निदेशक मंडल (मई 2011) ने इस योजना को संशोधित किया (1 अप्रैल 2011 से) जिसमें चार पहिया और दो पहिया वाहनों के लिए क्रमशः पेट्रोल की अधिकतम सीमा 35 लीटर से बढ़ाकर 175 लीटर एवं 25 लीटर से 35 लीटर और रखरखाव शुल्क क्रमशः ₹1,500 से बढ़ाकर ₹5,000 और ₹650 से ₹800 प्रति माह कर दिया गया।

31 मार्च 2011 तक गेल ने परिवहन भत्ते के रूप में केवल ₹800 प्रति माह और 01 अप्रैल 2011 से कैफेटेरिया दृष्टिकोण की 50 प्रतिशत सीमा के तहत ₹800 से ₹2,000 प्रति माह (कैडर-वार) रखा और कार्यकारी स्तर के लिए व्यक्तिगत वाहनों के लिए सीएमईआर से संबंधित शेष राशि कैफेटेरिया दृष्टिकोण के बाहर रखी गई।

अप्रैल 2009 से अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान, गेल ने परिवहन भत्ते के अलावा अपने कार्यकारियों को सीएमईआर के आधार पर ₹414.66 करोड़ की राशि का भुगतान किया। कैफेटेरिया दृष्टिकोण की 50 प्रतिशत (35 प्रतिशत पर संशोधित) सीमा के अलावा वाहन के 'संचालन और रखरखाव' व्यय का भुगतान डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप गेल द्वारा कार्यकारियों को अनुचित लाभ दिया गया था।

गेल ने कहा (दिसंबर 2021) कि संचालन और रखरखाव के लिए देय सीएमईआर राशि को अनुलाभ और भत्तों के कैफेटेरिया के बाहर रखा गया है क्योंकि यह व्यय विशुद्ध रूप से परिचालन/व्यवसाय प्रकृति का है और उन कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है जो आवाजाही हेतु अपना वाहन रखते हैं और कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए की गई यात्राओं पर इस तरह के वाहन का उपयोग करते हैं; जिससे गेल के वाहनों के उपयोग पर मांग कम हो जाती है और इस प्रकार कार्यालयीन कर्तव्यों के त्वरित और कुशल प्रदर्शन को बढ़ावा मिलता है। गेल ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि आधिकारिक उद्देश्यों के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वाहन पर किए गए व्यय, या तो प्रत्यक्ष या प्रतिपूर्ति को कर योग्य अनुलाभ के रूप में नहीं माना जा सकता।

गेल के उत्तर को निम्नलिखित के मद्देनजर में देखा जाए:

- i. डीपीई ने समय-समय¹⁰ पर स्पष्ट किया था कि 26 नवंबर 2008/3 अगस्त 2017 के अपने ओएम में उल्लिखित भत्तों के अलावा कोई भी भत्ता/लाभ/अनुलाभ 'कैफेटेरिया दृष्टिकोण' की सीमा के बाहर स्वीकार्य नहीं हैं।
- ii. कर्मचारियों को कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाता है। सीएमईआर का भुगतान व्यक्तिगत वाहनों के लिए संगठन में उनके स्तर के आधार पर किया जाता है न कि वास्तविक आधार पर और इसलिए यह प्रतिपूर्ति के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार, सीएमईआर का भुगतान प्रतिपूर्ति के बजाय

¹⁰ अप्रैल 2009, जून 2011, जून 2012 और जून 2013 ।

भत्ते की श्रेणी में आता है और इसे कैफेटेरिया दृष्टिकोण में शामिल किया जाना चाहिए था।

- iii. गेल के इस तर्क को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता कि वह सीएमआईआर का भुगतान विशुद्ध रूप से परिचालन गतिविधियों के लिए कर रही है, क्योंकि वह अपने सभी विभागों/स्थानों के लिए दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए वार्षिक अनुबंध के आधार पर वाहनों को किराए पर लेने के अलावा आठ किलोमीटर से अधिक की दूरी के अपने स्थानीय आवागमन के लिए अपने कार्यकारियों/कर्मचारियों को स्थानीय वाहन प्रभार के आधार पर अतिरिक्त भुगतान भी कर रही है।
- iv. जैसा कि ऊपर कहा गया है माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय केवल कर्मचारी के वाहन पर खर्च की गई प्रतिपूर्ति या वास्तविक राशि के लिए लागू है, जिसका उपयोग आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और इसे कर योग्य अनुलाभ के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, आयकर नियमों के अनुसार, प्रतिपूर्ति के लिए इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि व्यय पूरी तरह से और विशेष रूप से आधिकारिक कार्यों के निष्पादन पर किया गया था। कम्पनी द्वारा इसका अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार, डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित सीमा के अलावा वाहनों के 'संचालन और रखरखाव व्यय' व्यय के भुगतान से गेल के कार्यकारियों को ₹414.66 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

इस मामले की सूचना फरवरी 2022 में मंत्रालय को दी गई थी; उनका जवाब प्रतीक्षित है (अगस्त 2022)।

घ. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने अनुलाभों और भत्तों के भुगतान के लिए कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत शामिल परिवहन भत्ते के रूप में कुल वाहन रखरखाव प्रतिपूर्ति व्यय (सीएमआईआर) में से केवल ₹800 प्रति माह की निश्चित राशि पर विचार किया था। कार्यकारी स्तरों के लिए ₹6,445 से ₹23,315 प्रति माह तक के व्यक्तिगत वाहनों के लिए सीएमआईआर से संबंधित शेष राशि कैफेटेरिया दृष्टिकोण के बाहर रखी गई थी।

2017-18 से 2021-22 (21 अक्टूबर) की अवधि के दौरान, ओवीएल ने अपने कार्यकारियों को सीएमआईआर के लिए ₹14.16 करोड़ की राशि का भुगतान किया था। कैफेटेरिया दृष्टिकोण

की 35 प्रतिशत की सीमा के अलावा वाहन के 'संचालन और रखरखाव' व्यय का भुगतान डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप ओवीएल द्वारा कार्यकारियों को अनुचित लाभ दिया गया था।

ओवीएल ने कहा (अगस्त 2022) कि यह चौबीसों घंटे काम करता है क्योंकि इसका संचालन दुनिया भर में फैला हुआ है और इसकी लगातार निगरानी करने की आवश्यकता है जिसके लिए कर्मचारियों को निगरानी और नियंत्रण उद्देश्य के लिए लगातार उपलब्ध रहने की आवश्यकता है। सीएमआरई के आधार पर किया गया व्यय , भत्ता नहीं है बल्कि परिचालन कार्य से जुड़ा व्यय है जो उन कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है जो योजना की अपेक्षित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में अपने वाहनों का उपयोग करते हैं और वाहन को अच्छी चालन स्थिति में बनाए रखते हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होगी कि किसी कर्मचारी को कंपनी वाहन प्रदान करने की लागत उसे सीएमआरई की प्रतिपूर्ति से बहुत अधिक है। इसलिए, यह कार्यालयीन दौरे पर यात्रा के लिए खर्चों की प्रतिपूर्ति के समान है और इस प्रकार, कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत शामिल नहीं किया जा सकता।

ओवीएल के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि कार्यकारियों को संगठन में उनके स्तर के आधार पर व्यक्तिगत वाहनों के लिए सीएमआरई का भुगतान किया जाता है, न कि वास्तविक आधार पर और इसलिए यह प्रतिपूर्ति के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार सीएमआरई का भुगतान प्रतिपूर्ति के बजाय भत्ते की श्रेणी में आता है और इसे कैफेटेरिया दृष्टिकोण में शामिल किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित सीमा के अलावा वाहनों के 'संचालन और रखरखाव' व्यय के भुगतान से इसके कार्यकारियों को ₹14.16 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। इस मामले की सूचना सितंबर 2022 में मंत्रालय को दी गई थी; उनका जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2022)।

इस प्रकार, डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित सीमा के अलावा वाहनों के 'संचालन और रखरखाव' व्यय के भुगतान से आईओसीएल, ओएनजीसी, गेल और ओवीएल के कार्यकारियों को ₹2,609.47 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

सिफारिश संख्या 4: कंपनियों को वाहनों के 'संचालन और रखरखाव' व्यय की प्रतिपूर्ति बंद कर देनी चाहिए क्योंकि यह लोक उद्यम विभाग दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड

2.4 निर्यात सब्सिडी की वसूली न होने से हानि

एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड सफल बोलीदाता की प्रामाणिकता के सत्यापन में परिश्रम की कमी और निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में उत्तर दिनांकित चेक की स्वीकृति के कारण निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹13.76 करोड़ की हानि हुई।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड (कंपनी), बिहार के सुगौली और लौरिया में एकीकृत चीनी इथेनॉल सह-उत्पादन संयंत्र संचालित करती है। कंपनी गन्ना खरीदती है और इसे चीनी और इथेनॉल में परिवर्तित करती है। चीनी के निर्यात को सुविधाजनक बनाने और चीनी मिलों की तरलता की स्थिति में सुधार करने के लिए, भारत सरकार ने एक योजना अधिसूचित की (12 सितंबर 2019), जिसमें प्रत्येक चीनी मिल के लिए निर्धारित अधिकतम स्वीकार्य निर्यात मात्रा तक चीनी के निर्यात पर व्यय के लिए सहायता के रूप में ₹10,448 प्रति टन तय किए गए थे। उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार ने एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड चीनी मिलों की अधिकतम स्वीकार्य निर्यात मात्रा (16 सितंबर 2019) 13,266 टन निर्धारित की। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड ने एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड को विक्रेता के पैनल, दस्तावेजों के सत्यापन, बयाना राशि जमा (ईएमडी) के संग्रह, निविदा को अंतिम रूप देने और ऑनलाइन नीलामी का कार्य करने के लिए नियुक्त किया। श्री वेंकटेश्वर ग्लोबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (निर्यातक) 27 दिसंबर 2019 को आयोजित ऑनलाइन नीलामी में ₹20,000 प्रति टन की बोली मूल्य के साथ एच 1 बोलीदाता के रूप में उभरा।

एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड और वेंकटेश्वर ग्लोबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच निर्यात चीनी बिक्री करार (30 दिसंबर 2019) निष्पादित किया गया था। निर्यातक को निर्यात के लिए ₹20,000 प्रति टन की दर से 13,266 टन चीनी खरीदनी थी, आय का 100 प्रतिशत एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए एस्करो खाते में जमा किया जाना था और निर्यातक के लिए डिलीवरी ऑर्डर सृजित किया जाना था। नीलामी के

समय निर्यातक द्वारा जमा की गई ₹10 लाख की ईएमडी को प्रतिभूति जमा माना जाना था। निर्यातक को राष्ट्रीयकृत बैंक से ₹13.86 करोड़ की निष्पादन बैंक गारंटी या सब्सिडी राशि के बराबर उत्तर दिनांकित चेक के साथ विधिवत समर्थित कॉर्पोरेट गारंटी जमा करने की आवश्यकता थी। उपरोक्त शर्तों को वेंकटेश्वर ग्लोबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया था और बाद में 1 जनवरी 2020 और 3 मार्च 2020 के बीच 13,266 टन चीनी खरीदी गई थी। एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड को चीनी की बिक्री से ₹27.86 करोड़ की प्राप्ति हुई।

उपर्युक्त आवश्यकताओं के अलावा, निर्यातक को चलान जारी होने के 30 दिनों के भीतर सब्सिडी का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने थे, लेकिन पहली खेप के प्रेषण के 90 दिनों के बाद नहीं। तथापि, निर्यातक द्वारा अपेक्षित निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड अधिकतम स्वीकार्य निर्यात मात्रा योजना के अंतर्गत सरकार से ₹13.86 करोड़ की सब्सिडी का दावा नहीं कर सका।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- i. वेंकटेश्वर ग्लोबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने निगमन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था (दिसंबर 2019)। लेखापरीक्षा द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट की जांच से पता चला है कि 29 अक्टूबर 2019 के अपने नोटिस के माध्यम से, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटा दिया था (25 अक्टूबर 2019), क्योंकि यह ठीक पहले के दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रहा था। इस प्रकार, कंपनी को भंग कर दिया गया था और निविदा प्रक्रिया शुरू होने के समय पर अस्तित्व में नहीं थी।
- ii. एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक वेब आधारित, ऑनलाइन कमोडिटीज स्पॉट मार्केट और सर्विसेज कंपनी है और एचपीसीएल बायोफ्यूल्स (2011) एक्सचेंज का ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया। एचपीसीएल बायोफ्यूल्स ने विक्रेता के पैनल, बोलीदाताओं के आवेदन के सत्यापन आदि की जिम्मेदारी एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी और उपयुक्त विक्रेता चयन के लिए इस पर भरोसा किया। इसे इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि करार के खंड 25 में प्रावधान किया गया है कि एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड केवल एक ई-कॉमर्स सेवा प्रदाता था और न ही एक पक्ष था और न ही विक्रेता/खरीदार और सफल बोलीदाता के बीच

लेनदेन को नियंत्रित कर सकता था। खंड 27 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी घटना में एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड किसी भी क्षति, अप्रत्यक्ष, परिणामी या आकस्मिक या अप्राप्त लाभ, राजस्व की हानि आदि की क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अलावा, करार के खंड 31 ने एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड को सभी लागतों, क्षति, ऐसी बिक्री या वितरण के लिए आकस्मिक किसी भी दावे के खिलाफ क्षतिपूर्ति भी की। परिणामस्वरूप, हालांकि एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड अपने चयनित बोलीदाता की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में विफल रहा, कंपनी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, क्योंकि एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड को करार की शर्तों के अनुसार सभी लागतों और क्षति के खिलाफ क्षतिपूर्ति की गई थी। इस प्रकार, कंपनी एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड के साथ अपने पारस्परिक करार में सेवा की कमी की स्थिति में अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित करने में विफल रही।

- iii. इसके अलावा, निर्यातक ने करार के अनुरूप भारतीय स्टेट बैंक के उत्तर दिनांकित चेक द्वारा समर्थित (दिसंबर 2019) कॉर्पोरेट गारंटी प्रस्तुत की। हालांकि, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, निर्यातक ने निर्यात सब्सिडी का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड ने तब नकदीकरण के लिए चेक प्रस्तुत किया, जिसे बैंक द्वारा (26 अगस्त 2020) बाउंस कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में उत्तर दिनांकित चेक जमा करने की अनुमति दी, हालांकि यह एक असुरक्षित वित्तीय साधन है और कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रहा है।
- iv. भारत सरकार की अधिसूचना (12 सितंबर 2019) के खंड 4 ने चीनी मिलों को दो किस्तों में अपने सब्सिडी दावों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी, जिनमें से पहला अधिकतम स्वीकार्य निर्यात मात्रा के कम से कम 50 प्रतिशत के निर्यात पर प्रस्तुत किया जाना था और कुल दावा लदान के अंतिम बिल जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 4 फरवरी 2020 तक 50 प्रतिशत चीनी भेज दी गई थी। एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड ने (18 जनवरी 2020) वेंकटेश्वर ग्लोबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को सूचित किया कि 50 प्रतिशत चीनी उठाए जाने के बाद दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता थी ताकि इसके लिए सब्सिडी का दावा किया जा सके। हालांकि, बाद में, चीनी की पूरी मात्रा भेजे जाने के बाद ही कंपनी ने निर्यातक को अपेक्षित दस्तावेज जमा करने के लिए कहा

(4 मार्च 2020)। यदि कंपनी अधिकतम स्वीकार्य निर्यात मात्रा का 50 प्रतिशत भेजने के बाद दस्तावेज जमा करने का प्रयास करती, तो वह शेष मात्रा में चीनी के प्रेषण को रोक सकती थी।

इस प्रकार, सफल बोलीदाता की प्रामाणिकता के सत्यापन में उचित परिश्रम की कमी और निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में उत्तर दिनांकित चेक की स्वीकृति के कारण, एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड निर्यात प्रोत्साहनों को प्राप्त नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹13.76 करोड़ की हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि काम पूरी तरह से एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड को आउटसोर्स किया गया था और एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड बोली लगाने वाले के पंजीकरण में कहीं भी शामिल नहीं था। एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड के साथ करार ने एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड को सभी लागतों, क्षतियों और ऐसी बिक्री या डिलीवरी के लिए आकस्मिक किसी भी दावे के प्रति क्षतिपूर्ति की, इसलिए एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। निष्पादन बैंक गारंटी के बदले उत्तर दिनांकित चेक एकत्र करने का निर्णय अच्छी तरह से सोचा गया था और यह उनकी मानक संचालन प्रक्रिया का हिस्सा था। इसमें आगे कहा गया है कि अधिकतम स्वीकार्य निर्यात मात्रा का 50 प्रतिशत भेजने के बाद दस्तावेज जमा करना अनिवार्य नहीं था।

प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने बोलीदाता के चयन के लिए एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड पर भरोसा किया, लेकिन उनके आपसी करार की शर्तों ने सेवा की कमी की स्थिति में भी एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड को सभी लागतों और क्षति से क्षतिपूर्ति की। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, कंपनी एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड के साथ अपने पारस्परिक करार में अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही। हालांकि, इसे निम्नलिखित के मद्देनजर देखा जा सकता है:

- i. एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड ने एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड द्वारा निर्धारित तकनीकी योग्यता के अनुसार सफल बोलीदाता का चयन किया था। इसके अलावा, करार के खंड 8 के अनुसार एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड को सफल बोलीदाता के ब्यौरे कंपनी को सूचित करना अपेक्षित था। इसके अलावा, खंड 25 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड केवल एक ई-कॉमर्स सेवा प्रदाता था और

किसी भी लेनदेन के लिए एक पार्टी या नियंत्रक नहीं हो सकता था। इसलिए, करार एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड के लिए एकतरफा रूप से अनुकूल था और एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड को लेनदेन में उचित परिश्रम करने के लिए अपनी देयता से मुक्त नहीं किया। एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड के पास बोलीदाता की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का अवसर और उद्देश्य था, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे और पूरी तरह से एनसीडीईएक्स ई मार्केट लिमिटेड पर भरोसा किया।

- ii. खरीद प्रणाली में पाई गई सामान्य अनियमितताओं/कमियों से संबंधित केन्द्रीय सीवीसी के दिशा-निर्देशों (15 जनवरी, 2002) के पैरा 18.1 में कहा गया है कि सरकारी हितों की रक्षा के लिए संविदा के उचित निष्पादन के लिए वारंटी अवधि तक वैध निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में उचित राशि लेना उचित होगा। उत्तर दिनांकित चेक की अनुमति देने का कंपनी का निर्णय सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था।
- iii. यद्यपि अधिकतम स्वीकार्य निर्यात मात्रा का 50 प्रतिशत प्रेषण के बाद दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं था, क्योंकि निर्यातक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुआ था (जनवरी 2020), कंपनी को अपने हितों की रक्षा के लिए उस स्तर पर सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए था और लागू करना चाहिए था।

इस प्रकार, एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड को सफल बोलीदाता की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में विफल रहने और निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में उत्तर दिनांकित चेक की स्वीकृति के कारण ₹13.76 करोड़ (₹13.86 करोड़ में से जब्त ईएमडी राशि के ₹0.10 करोड़ घटाकर) की हानि हुई।

इस मामले की सूचना फरवरी 2022 में मंत्रालय को दी गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2022)।

सिफारिश संख्या 5: प्रबंधन को सफल बोलीदाता की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में विफलता और निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में उत्तर दिनांकित चेक की स्वीकृति के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। प्रबंधन कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए उत्तर दिनांकित चेक के बजाय निष्पादन बैंक गारंटी पर जोर देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

2.5 प्रोपलीन हैंडलिंग सुविधाओं के सृजन पर निष्फल व्यय

अतिरिक्त प्रोपलीन हैंडलिंग सुविधाओं का सृजन इस बात से अवगत होने के बावजूद किया गया था कि मैसर्स आंध्र पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड प्रोपलीन के लिए एकमात्र ग्राहक था और विशाख रिफाइनरी से सीधे समर्पित पाइपलाइन के माध्यम से उत्पाद उठा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप ₹11.50 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने विशाख रिफाइनरी में अपनी शोधन क्षमता को 2015 तक 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की योजना (अगस्त 2007) बनाई थी और विपणन भंडारण सुविधाओं और रेल/सड़क लदान सुविधाओं को विशाख न्यू एलपीजी टर्मिनल नामक एक नए टर्मिनल में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया था। विशाख न्यू एलपीजी टर्मिनल की संस्थापना के लिए एचपीसीएल द्वारा नियुक्त मैसर्स टीसीई कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड ने दिसम्बर, 2008 में एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ एलपीजी सुविधाएं भी शामिल थीं।

विशाख न्यू एलपीजी टर्मिनल की एलपीजी सुविधा में जिन उत्पादों के प्रबंधन का प्रस्ताव था, वे एलपीजी, ऑटो एलपीजी और प्रोपलीन थे। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट में प्रोपलीन की लोड आवश्यकता 1,000 मीट्रिक टन प्रति माह पर परिकल्पित की गई थी। तदनुसार, प्रोपलीन के भंडारण के लिए 250 मीट्रिक टन क्षमता के साथ एक मॉल्डेड भंडारण बुलेट निर्धारित की गई थी, जिसे विशाख रिफाइनरी से एक समर्पित 6 इंच क्रॉस-कंटी पाइपलाइन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा, केवल टैंक ट्रकों के माध्यम से प्रोपलीन के प्रेषण के लिए एक पूरी तरह से स्वचालित टैंक ट्रक गैन्ट्री बे की भी परिकल्पना की गई थी। विशाख न्यू एलपीजी टर्मिनल पर प्रोपलीन की प्राप्ति, भंडारण और हैंडलिंग के लिए ₹11.50 करोड़¹¹ की लागत से उपरोक्त सभी सुविधाएं बनाई गई थीं। इस टर्मिनल को अप्रैल 2012 में चालू किया गया था।

¹¹ टैंक (₹7.30 करोड़), लोडिंग पंप (₹0.36 करोड़), संबद्ध सुविधाएं जैसे उत्पाद लाइन, टीटी कंप्रेसर, एडुक्टर इत्यादि जैसी संबद्ध सुविधाएं (₹3.84 करोड़) की लागत शामिल हैं, लेकिन स्वचालित टैंक ट्रक गैन्ट्री की लागत को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि गैन्ट्री का उपयोग एलपीजी लोड करने के लिए भी किया जाता है।



आकृति 2.1: प्रोपलीन टैंक



आकृति 2.2: टैंक ट्रक गैन्ट्री

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- i. मैसर्स आंध्र पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड एकमात्र ग्राहक था जो 1991 से विशाख रिफाइनरी से उत्पादित प्रोपलीन खरीद रहा था। प्रोपलीन को 1993 में बिछाई गई एक समर्पित पाइपलाइन के माध्यम से विशाख रिफाइनरी से सीधे मैसर्स आंध्र पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड को हस्तांतरित किया जाता था। विशाख रिफाइनरी में प्रोपलीन की हैंडलिंग के लिए पर्याप्त अवसंरचना की मौजूदगी के बावजूद, विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट में मैसर्स टीसीई कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित एचपीसीएल द्वारा टैंक ट्रकों द्वारा संचालित 250 मीट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण सुविधा का सृजन किया गया था।
- ii. विशाख न्यू एलपीजी टर्मिनल पर प्रोपलीन के भंडारण और हैंडलिंग के लिए बनाई गई सुविधाएं अप्रैल 2012 में इसके चालू होने से दिसंबर 2021 तक निष्क्रिय रहीं क्योंकि इस अवधि के दौरान इस टर्मिनल से प्रोपलीन प्राप्त, संग्रहीत या प्रेषित नहीं किया गया था।
- iii. लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2020) द्वारा इंगित किए जाने के बाद, एचपीसीएल के प्रबंधन ने इन सुविधाओं के उपयोग को प्रोपलीन से एलपीजी में बदलने के लिए (15 मार्च 2021) मंजूरी दी और एलपीजी के भंडारण के लिए प्रोपलीन के लिए बनाई गई सुविधा का उपयोग करने के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन को आवेदन किया, जबकि एलपीजी के लिए अतिरिक्त भंडारण की कोई आवश्यकता नहीं थी।

इस प्रकार, ₹11.50 करोड़ के व्यय के बाद सृजित प्रोपलीन हैंडलिंग सुविधाएं नौ वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रहीं और बाद में, एलपीजी के लिए पहले से ही पर्याप्त भंडारण

सुविधा होने के बावजूद एलपीजी भंडारण सुविधा के रूप में उनके उपयोग के लिए अनुमोदन लिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा (अक्टूबर 2020/अगस्त 2021) इंगित किए जाने पर, मंत्रालय/प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2022/अगस्त 2021) में कहा कि:

i. पुराने एलपीजी संयंत्र में मौजूदा और संभावित औद्योगिक ग्राहकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रोपलीन टैंकरों के लिए एक समर्पित टैंक ट्रक लोडिंग बे था। पुनर्स्थापन योजना के अनुसार, सभी मौजूदा सुविधाओं को नए स्थान पर दोहराया जाना था। मैसर्स आंध्र पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड की 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने के बाद प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए इस सुविधा की स्थापना की गई थी। तत्पश्चात मैसर्स आन्ध्र पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड की प्रोपलीन मांग बढ़कर 150 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई और उनकी संपूर्ण मांग को रिफाइनरी द्वारा समर्पित पाइपलाइन के माध्यम से पूरा किया गया। परिणामस्वरूप, विशाख न्यू एलपीजी टर्मिनल के लिए रिफाइनरी के पास कोई अतिरिक्त प्रोपलीन उपलब्ध नहीं था, जिससे सुविधा का उपयोग नहीं हो रहा था।

ii. प्रोपलीन हैंडलिंग सुविधाओं का निर्माण भावी ग्राहकों द्वारा उत्पाद की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था ताकि प्रोपलीन की भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे को तैयार रखा जा सके। बाद के चरण में इस तरह के बुनियादी ढांचे का निर्माण महंगा और चुनौतीपूर्ण होता।

iii. एचपीसीएल को एलपीजी के भंडारण के लिए प्रोपलीन सुविधा का उपयोग करने के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की अंतिम मंजूरी मिल गई है और दिसंबर 2021 से सुविधाओं का उपयोग शुरू कर दिया है।

मंत्रालय और प्रबंधन के जवाबों को निम्नलिखित तथ्यों के मद्देनजर देखने की आवश्यकता है:

i. प्रोपलीन की खरीद के लिए मैसर्स आंध्र पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड एकमात्र ग्राहक है और जब भी मैसर्स आंध्र पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड में शटडाउन होता था या इसने विशाख रिफाइनरी से प्रोपलीन की खरीद नहीं की थी, प्रोपलीन रिकवरी यूनिट को बंद कर दिया जाता था। इस प्रकार, अपेक्षित अतिरिक्त प्रोपलीन उत्पादन को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में औचित्य का अभाव है। लेखापरीक्षा का तर्क इस तथ्य से और पुख्ता हो

जाता है कि एलपीजी के भंडारण के लिए प्रोपलीन सुविधा का उपयोग करने के लिए अब अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

ii. मौजूदा प्रोपलीन रिकवरी यूनिट का पुनरुद्धार विशाख रिफाइनरी की आधुनिकीकरण परियोजना का एक हिस्सा था। हालांकि, प्रबंधन ने निदेशक मंडल को विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना¹² के दायरे से ₹118 करोड़ की लागत से प्रोपलीन रिकवरी यूनिट (उत्पादन क्षमता को 10,400 मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लिए) के परिकल्पित पुनरुद्धार को हटाने का प्रस्ताव (सितंबर 2019) किया, क्योंकि मौजूदा प्रोपलीन उत्पादन के अलावा, प्रोपलीन के लिए कोई अतिरिक्त मांग की उम्मीद नहीं थी। तदनुसार, बोर्ड ने प्रोपलीन रिकवरी यूनिट के पुनरुद्धार प्रस्ताव को हटाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

iii. रिफाइनरी और विशाख न्यू एलपीजी टर्मिनल में पहले से ही 9,900 मीट्रिक टन¹³ की एलपीजी भंडारण सुविधा थी। इसके विपरीत, विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट में अनुमानित मासिक हैंडलिंग आवश्यकता 50,300 मीट्रिक टन¹⁴ थी और 2018-19 से 2021-22 के दौरान औसत दैनिक मात्रा कभी भी 2,535 मीट्रिक टन से अधिक नहीं हुई। इसलिए, 9,900 मीट्रिक टन एलपीजी के लिए मौजूदा भंडारण सुविधा का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। इसलिए, मौजूदा प्रोपलीन भंडारण टैंक को एलपीजी भंडारण में परिवर्तित करने के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन का अनुमोदन प्राप्त करना पहले से ही सृजित अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए केवल एक बाद का विचार था।

इस प्रकार, इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि आंध्र पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड प्रोपलीन के लिए एकमात्र ग्राहक था और विशाख रिफाइनरी से सीधे समर्पित पाइपलाइन के माध्यम से उत्पाद उठा रहा था, ₹11.50 करोड़ के व्यय पर प्रोपलीन हैंडलिंग सुविधाओं का अनुचित सृजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹11.50 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

¹² विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना में विशाख रिफाइनरी की शोधन क्षमता को बढ़ाकर 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने की परिकल्पना की गई है।

¹³ रिफाइनरी के अंदर 1,200 मीट्रिक टन की क्षमता वाली पांच मॉऊडेड बुलेट और विशाख न्यू एलपीजी टर्मिनल पर 1,300 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाली तीन मॉऊडेड बुलेट हैं।

¹⁴ प्रतिदिन लगभग 1,677 मीट्रिक टन।

2.6 ऊर्जा संरक्षण के अवसर को छोड़ा गया

एचपीसीएल की विशाख रिफाइनरी में निरंतर उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई के नेट गैस कंप्रेसर में निरंतर क्षमता नियंत्रण प्रणालियों के कार्यान्वयन में देरी के परिणामस्वरूप ऊर्जा संरक्षण के लिए ₹10.59 करोड़ की बचत करने का अवसर खो गया।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की विशाख रिफाइनरी ने (अगस्त 2009) भारी नाफथा में पैराफिन¹⁵ और नेफथीन¹⁶ को सुगंधित समृद्ध रिफार्मेट¹⁷ और हाइड्रोजन उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए एक सतत उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई शुरू की। यूनिट के लिए प्रोसेस लाइसेंसदाता¹⁸ मैसर्स यूओपी था। निरंतर उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई में निवल गैस सेवा के लिए दो¹⁹ प्रत्यागामी निवल गैस कंप्रेसर होते हैं और 25/50/70/90/100 प्रतिशत लोडिंग क्षमता पर काम कर सकते हैं। तथापि, निवल गैस कंप्रेसर को सामान्यतः 70 अथवा 90 प्रतिशत क्षमता पर संचालित किया जाता था जिसमें खुली स्थिति में स्पिल बैक कंट्रोल वाल्व²⁰ लगातार 20 से 30 प्रतिशत तक होता था।

चूंकि कंप्रेसर की विद्युत् की खपत अधिक थी, इसलिए पर्याप्त ऊर्जा बचत का लाभ उठाने के लिए, स्पिल बैक प्रवाह को कम करना पड़ा और निवल गैस कंप्रेसर को वांछित क्षमता पर संचालित किया जाना था। इसे प्राप्त करने के लिए, निवल गैस कंप्रेसर पर स्टेप-लेस/सतत क्षमता नियंत्रण प्रणाली शुरू की जानी थी। सतत क्षमता नियंत्रण प्रणाली के साथ, निवल गैस कंप्रेसर निरंतर उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई से शुद्ध गैस उत्पादन के आधार पर कोई स्पिल बैक प्रवाह के साथ आवश्यक क्षमता (10 से 100 प्रतिशत तक) पर चल

¹⁵ पैराफिन ज्वलनशील, सफेद, पारदर्शी, मोमी ठोस होते हैं जिनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जो पेट्रोलियम या शेल से आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है और मोमबत्तियों, सौंदर्य प्रसाधनों, पॉलिश और सीलिंग और वाटरप्रूफिंग यौगिकों में उपयोग किया जाता है।

¹⁶ नेफथीन, जिसे साइक्लोएल्केन्स के रूप में भी जाना जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की कम से कम एक रिंग होती है।

¹⁷ रिफार्मेट एक उच्च ऑक्टेन तरल उत्पाद है और उच्च ऑक्टेन गैसोलीन के लिए प्रीमियम सम्मिश्रण स्टॉक है।

¹⁸ प्रक्रिया लाइसेंसधारक प्रक्रिया डिजाइनिंग करता है और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए लाइसेंस भी प्रदान करता है।

¹⁹ 74-के -02 ए और 74-के -02 बी; एक ऑपरेटिंग और एक स्टैंडबाय।

²⁰ स्पिल बैक कंट्रोल वाल्व का उपयोग प्रत्यागामी कंप्रेसर के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रक्रिया की मांग के अनुसार गैस प्रवाह को विनियमित करने के लिए, संपीड़ित गैस के हिस्से को फिर से विस्तारित किया जाता है और वृषण पक्ष में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण ऊर्जा हानि होती है।

सकता है और कंप्रेसर लोड को न्यूनतम 10 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। एचपीसीएल के अनुमान के अनुसार सतत क्षमता नियंत्रण प्रणाली के चालू होने से प्रत्याशित बचत ₹3.30 करोड़ प्रतिवर्ष थी। सतत क्षमता नियंत्रण प्रणाली के चालू होने के लिए निरंतर उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई के शटडाउन की आवश्यकता थी और इसलिए, निरंतर उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई के शटडाउन के दौरान लागू करने की योजना बनाई गई थी।

तदनुसार, एचपीसीएल की विशाख रिफाइनरी ने सतत उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई के निवल गैस कंप्रेसर पर सतत क्षमता नियंत्रण प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव (सितम्बर, 2012) शुरू किया। वर्ष 2016-17 के बजट के तहत योजना के लिए आवश्यक ₹9.40 करोड़ का बजट (मई 2016) आवंटित किया गया था। एचपीसीएल की विशाख रिफाइनरी ने (अगस्त 2016) ₹6.18 करोड़ के मूल मूल्य पर सतत क्षमता नियंत्रण प्रणाली की आपूर्ति के लिए एक आदेश दिया और सामग्री दिसंबर 2016 में प्राप्त हुई। प्रारंभ में, दिसंबर 2018 में निरंतर उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई के शटडाउन के दौरान 74-के -02 बी कंप्रेसर के लिए निरंतर उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई पर निरंतर क्षमता नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। इसके बाद, सितंबर 2019 में निरंतर उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई सुधार के दौरान 74-के-02 ए कंप्रेसर के लिए निरंतर क्षमता नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। एचपीसीएल की विशाख रिफाइनरी ने अप्रैल 2020 में प्रभाव आकलन किया और पाया कि वास्तविक बचत प्रति वर्ष ₹3.30 करोड़ की अनुमानित बचत की तुलना में प्रति वर्ष ₹2.53 करोड़ थी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

i. लाइसेंसदाता मैसर्स यूओपी ने वर्ष 2005 से सतत क्षमता नियंत्रण प्रौद्योगिकी अपनाई थी। परियोजना की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, सतत क्षमता नियंत्रण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित लीड समय न्यूनतम दो वर्ष था और इसके लिए निरंतर उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई को बंद करने की आवश्यकता थी। अगस्त, 2009 में सतत उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई के चालू होने के बाद अगली योजनाबद्ध टर्नअराउंड और निरीक्षण²¹ शटडाउन अप्रैल, 2014 में था, एचपीसीएल की विशाख रिफाइनरी को अप्रैल, 2014 में नियोजित शटडाउन से मेल खाने के लिए समय पर सतत क्षमता नियंत्रण प्रणाली के कार्यान्वयन का

²¹ टर्नअराउंड और निरीक्षण एक नियोजित शटडाउन है जो चार वर्ष में एक बार होता है। 2012 के बाद, पहला उपलब्ध टर्नअराउंड और निरीक्षण शटडाउन 2014 में था और बाद में 2018 में चार वर्ष बाद। इस शटडाउन के दौरान, मैकेनिकल, सिविल, रोटरी, इंस्ट्रुमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल जॉब आदि सहित यूनिट में सभी मरम्मत और रखरखाव कार्यों के साथ-साथ तकनीकी सुधार के किसी भी काम को यूनिट के विभिन्न उपकरणों पर किया जाता है।

प्रस्ताव शुरू करना चाहिए था। हालांकि एचपीसीएल की विशाख रिफाइनरी ने सितंबर 2012 में प्रस्ताव शुरू किया था और अगले शटडाउन में केवल 18 महीने बचे थे। परिणामस्वरूप, यह अप्रैल 2014 में शटडाउन के दौरान सिस्टम को पूरा नहीं कर सका।

ii. इसके अलावा, सितंबर 2012 में प्रस्ताव की शुरुआत के बाद, की आंतरिक स्वीकृति प्राप्त करने सक्षम प्राधिकारी (मई 2016) की आंतरिक स्वीकृति प्राप्त करने और आदेश देने (अगस्त 2016) में चार वर्ष का समय लिया गया था और इसलिए, सतत क्षमता नियंत्रण प्रणालियों को दिसंबर 2018/सितंबर 2019 में ही निरंतर उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई में चालू किया जा सका है।

इस प्रकार, प्रस्ताव को शुरू करने में देरी के साथ-साथ चार वर्ष के बाद की प्रक्रियात्मक देरी ने निरंतर उत्प्रेरक पुनर्जनन प्रणालियों के चालू होने में देरी की और एचपीसीएल ने जून 2014 से नवंबर 2018 के दौरान ऊर्जा संरक्षण के लिए ₹10.59 करोड़²² बचाने का अवसर खो दिया।

मंत्रालय (दिसंबर 2021)/प्रबंधन (सितंबर 2021/मई 2022) ने कहा कि:

i. यद्यपि मैसर्स यूओपी ने वर्ष 2005 से सतत क्षमता नियंत्रण प्रौद्योगिकी अपनाई थी, तथापि प्रबंधन को वर्ष 2005 में इसकी जानकारी नहीं थी। किसी भी नई तकनीक की विशेषताओं को सभी रिफाइनरियों द्वारा अपनाए जाने से पहले साबित करने की आवश्यकता होती है। सतत उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई के डिजाइन चरण के दौरान मैसर्स यूओपी द्वारा इस प्रौद्योगिकी पर विचार नहीं किया गया था और इसलिए इस प्रौद्योगिकी के बिना यूनिट को 2009 में चालू किया गया था। यूनिट के चालू होने और इसके स्थिरीकरण के बाद एचपीसीएल की विशाख रिफाइनरी ने सतत क्षमता नियंत्रण प्रणाली को लागू करके ऊर्जा के संरक्षण की क्षमता का अवलोकन किया और तदनुसार इस प्रणाली को स्थापित करने का प्रस्ताव शुरू किया गया।

ii. परियोजना की जटिलता और निष्पादन के दौरान कंप्रेसर के मूल उपकरण निर्माता की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, निरंतर क्षमता नियंत्रण प्रणाली के शुरू करने के लिए

²² टर्नअराउंड और निरीक्षण शटडाउन के बाद निरंतर उत्प्रेरक पुनर्जनन इकाई ने 16 मई 2014 से परिचालन शुरू किया। इसलिए नुकसान की गणना जून 2014 से की गई। इसके अलावा, सतत उत्प्रेरक पुनर्जनन प्रणाली को दिसंबर 2018 में एक कंप्रेसर में चालू किया गया था, इसलिए, नुकसान की गणना नवंबर 2018 तक की गई है।

अनुमानित लीड समय न्यूनतम दो वर्ष था। इस प्रस्ताव के निष्पादन के लिए अप्रैल 2014 की समय-सीमा को पूरा करने के लिए खरीद मांग जून, 2013 तक ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, जिसके लिए बजट अनुमोदन प्रक्रिया को कम से कम मई, 2013 तक पूरा करने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर, बजट के लिए अनुरोध केवल यह सुनिश्चित करने के बाद प्रस्तुत किया जाता है कि परियोजना सभी पहलुओं में पूरी तरह से विकसित है जो इस मामले में अक्टूबर 2013 में हासिल की गई थी। चूंकि बजट अनुमोदन प्राप्त करने, ऑर्डर प्लेसमेंट और साइट पर सामग्री की उपलब्धता के लिए उपलब्ध समय अप्रैल 2014 टर्नअराउंड और निरीक्षण शटडाउन के दौरान परियोजना को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए इसे 2018 में अगले टर्नअराउंड और निरीक्षण के लिए निर्धारित किया गया था। तदनुसार, 2018 टर्नअराउंड और निरीक्षण शटडाउन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए परियोजना का पदमापन किया गया था।

मंत्रालय और प्रबंधन के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है:

i. लेखापरीक्षा आपत्ति 2009 में सतत उत्प्रेरक पुनरुद्धार इकाई के साथ सतत क्षमता नियंत्रण प्रणाली को चालू न करने पर नहीं है बल्कि सतत क्षमता नियंत्रण प्रणाली को अप्रैल, 2014 के शटडाउन के दौरान चालू करने के प्रस्ताव में विलंब को लेकर है। अगस्त 2009 में सतत उत्प्रेरक पुनरुद्धार इकाई के चालू होने के समय सतत क्षमता नियंत्रण प्रौद्योगिकी उपलब्ध थी। एचपीसीएल को पता था कि उसे सतत क्षमता नियंत्रण प्रणाली को लागू करने के लिए कम से कम दो वर्ष की आवश्यकता थी और 2014 के शटडाउन के दौरान इसकी स्थापना के प्रस्ताव को शुरू करने के लिए उसके पास दो वर्ष से अधिक का पर्याप्त समय भी था। इस तरह से परियोजना की योजना बनाना अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि, यदि अप्रैल 2014 में शटडाउन छूट गया, तो अगला टर्नअराउंड और निरीक्षण शटडाउन केवल चार वर्ष बाद, अर्थात् 2018 में निर्धारित किया गया था। हालांकि, एचपीसीएल ने अप्रैल 2014 में अगले उपलब्ध टर्नअराउंड और निरीक्षण शटडाउन से सिर्फ 18 महीने पहले सितंबर 2012 में प्रस्ताव शुरू किया था।

ii. इसके अतिरिक्त, चूंकि प्रस्ताव अप्रैल 2014 में नियोजित अगले टर्नअराउंड और निरीक्षण शटडाउन से दो वर्ष से भी कम समय के साथ सितंबर 2012 में शुरू किया गया था, समझदारी इसमें थी कि एचपीसीएल को अप्रैल 2014 में नियोजित टर्नअराउंड और निरीक्षण शटडाउन के साथ मेल हेतु अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास करना

चाहिए था। एचपीसीएल के अनुमान के अनुसार, क्रय मांग जारी करने से प्रणाली की स्थापना/कमीशनिंग के लिए 10 महीने की अवधि की आवश्यकता थी। इस प्रकार, आंतरिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आठ महीने का समय उपलब्ध था। तथापि, प्रक्रिया में तेजी लाने के बजाय एचपीसीएल की विशाख रिफाइनरी को प्रबंधन अनुमोदन²³ के लिए प्रस्ताव शुरू करने में आठ महीने और निधियों²⁴ के आबंटन के लिए 20 महीने का समय लगा। परिणामस्वरूप, एचपीसीएल की विशाख रिफाइनरी ने 2014 में सतत क्षमता नियंत्रण प्रणाली को चालू करने का अवसर खो दिया और प्रणाली को चालू करने के लिए चार वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ी।

इस प्रकार, अप्रैल, 2014 के पहले टर्नअराउंड और निरीक्षण शटडाउन के दौरान सतत क्षमता नियंत्रण प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव शुरू करने में विलंब के साथ-साथ प्रक्रियात्मक विलंब से बचने के लिए प्रभावी निगरानी की कमी के कारण निरंतर उत्प्रेरक पुनरुद्धार इकाई के शुद्ध गैस कंप्रेसर में सतत क्षमता नियंत्रण प्रणालियों के कार्यान्वयन में समग्र विलंब हुआ। परिणामस्वरूप, एचपीसीएल की विशाख रिफाइनरी ने ऊर्जा संरक्षण के लिए ₹10.59 करोड़ बचाने का अवसर खो दिया।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

2.7 कम हाइड्रोकार्बन और जोखिम भरे अन्वेषण और उत्पादन ब्लॉक में भागीदारी के कारण ₹145 करोड़ का निष्फल व्यय

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में कोई ऑपरेटरशिप अनुभव नहीं होने के अतिरिक्त व्यवहार्य भंडार की उपलब्धता को दर्शाने वाले बुनियादी तत्वों की अनुपस्थिति के बावजूद हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियां शुरू कीं। इससे ₹145 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने 2008 में एनईएलपी²⁵ के 7वें दौर के अंतर्गत कैम्बे बेसिन, गुजरात में अन्वेषण और उत्पादन के लिए दो तटवर्ती टाइप-एस

²³ परियोजना सुरक्षा और इंजीनियरिंग स्वीकृति अक्टूबर 2012 में प्राप्त हुई थी, प्रबंधन अनुमोदन के लिए प्रस्ताव जून 2013 में शुरू किया गया था।

²⁴ धन के आवंटन का प्रस्ताव 8 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था और 28 मई 2016 को धन आवंटित किया गया था।

²⁵ नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति।

अन्वेषण ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2005/7 का अधिग्रहण किया था। इसके लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) पर भारत सरकार के साथ 22 दिसम्बर, 2008 को हस्ताक्षर किए गए थे। पीएससी के अनुसार, उक्त ब्लॉक के लिए अन्वेषण अवधि सात वर्ष थी, जिसे दो चरणों अर्थात् चार वर्षों के चरण-I और तीन वर्षों के चरण-II में विभाजित किया गया था। इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

i. संभावना का निर्धारण करने और बोली दौर के तहत प्रस्तावित ब्लॉकों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, आईओसीएल ने हाइड्रोकार्बन महानिदेशक (डीजीएच) की वेबसाइट से प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों के मूल्यांकन के लिए अपने इन-हाउस अंशकालिक सलाहकार को प्रतिनियुक्त किया। प्रस्तावित 57 ब्लॉकों के प्रारंभिक आंकड़ों के आवश्यक मूल्यांकन के बाद अंशकालिक परामर्शदाता ने कुल 14 अन्वेषण ब्लॉकों का चयन (अप्रैल, 2008) किया और चिंता व्यक्त की कि ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2005/7 में पहले ड्रिल किए गए सभी पांच कुओं को सूखा घोषित कर दिया गया था। इन-हाउस कंसल्टेंट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन/समयक् तत्परता की भी सिफारिश की कि ब्लॉक के पश्चिमी भाग में विकसित कीचड़ लॉगिंग इकाइयों और पतली कैम्बे शेल (सोर्स रॉक) और ब्लॉक क्षेत्र में खराब कैप रॉक के मद्देनजर, ब्लॉक में सफलता की भूवैज्ञानिक संभावना केवल तीन प्रतिशत होगी।

ii. इस ब्लॉक के आगे के मूल्यांकन के लिए कंपनी ने (फरवरी 2008) मैसर्स रिसोर्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स (आरआईएससी) को नियुक्त किया, जिन्होंने प्रत्येक ब्लॉक से डेटा के तकनीकी मूल्यांकन के बाद (मार्च 2008) मूल्यांकन में निम्नलिखित सीमाओं/बाधाओं को व्यक्त किया:

क) अपर्याप्त लॉग डेटा तथा परमिट के भीतर कुओं के लिए कुओं की पूरक जानकारी और पड़ोसी क्षेत्रों से बिल्कुल कोई डेटा नहीं।

ख) भूकंपीय डेटा केवल उन कुओं तक सीमित है जो विशेष रूप से परमिट के भीतर आते हैं।

ग) अधिकांश भूकंपीय डेटा खराब गुणवत्ता के थे; पेपर अनुभागों से एक महत्वपूर्ण अनुपात स्कैन किया गया था और स्कैनिंग शोर की शुरुआत ने डेटा में रखे गए

आयाम की जानकारी को सीमित कर दिया था, इसलिए आत्मविश्वास के साथ भूकंप-सूचक में कुओं की एक छोटी संख्या को बांधना संभव था।

घ) कई भूकंपीय लाइनें या तो माइग्रेट नहीं की गई थीं या बहुत खराब तरीके से माइग्रेट की गई थीं, जिससे इन लाइनों पर गलती और संरचनात्मक व्याख्याएं कठिन हो गईं।

ड) चेक शॉट उपलब्ध नहीं थे और अच्छी तरह से बांधना अविश्वसनीय था इसलिए वेग मानचित्र उत्पन्न करना संभव नहीं था।

च) उपरोक्त ब्लॉकों में से प्रत्येक में 1,250 मीटर से 1,500 मीटर की गहराई तक पहले ड्रिल किए गए पांच अन्वेषण कुओं ने कोई हाइड्रोकार्बन नहीं दिया।

ii. अन्वेषण ब्लॉकों के प्रचालन का कोई पिछला अनुभव न होने के बावजूद आईओसीएल ने अपने परामर्शदाताओं द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं को दरकिनार कर दिया और (मार्च, 2008) प्रचालक के रूप में ब्लॉकों का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया। आईओसीएल ने टाइप-एस ब्लॉकों (200 किमी² तक का क्षेत्र) के लिए बोली दौर और बोली मूल्यांकन मानदंड में किसी भी पूर्व-योग्यता तकनीकी क्षमता मानदंड की अनुपस्थिति को एक अनूठे अवसर के रूप में माना और 100 प्रतिशत भागीदारी ब्याज के साथ शॉर्टलिस्ट किए गए ब्लॉक का अधिग्रहण किया।

iii. आईओसीएल ने अपने निदेशक मंडल (बीओडी) से अनुमोदन प्राप्त करते समय परामर्शदाता द्वारा अनुशंसित पांच कुओं की तुलना में कुओं की संख्या को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध होने के पीछे के तर्क और दोनों सलाहकारों द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों को साझा नहीं किया था। हालांकि, कंपनी ने बाद में अधिग्रहित 3डी भूकंपीय डेटा के आधार पर 10 कुओं की अपनी प्रतिबद्धता के विरुद्ध केवल छह कुओं को ड्रिल किया। हाइड्रोकार्बन की कोई खोज नहीं होने के कारण इन सभी कुओं को छोड़ दिया गया था।

iv. ड्रिल किए गए कुओं की पोस्ट ड्रिलिंग विश्लेषण रिपोर्टों से यह देखा गया कि हाइड्रोकार्बन की अनुपस्थिति के पीछे का कारण मुख्य रूप से स्रोत चट्टान को जिम्मेदार ठहराया गया था, अर्थात्, कैम्बे शेल सीमित क्षमता वाले मिट्टी के पत्थर, स्थान से हाइड्रोकार्बन के गैर-प्रवास के साथ-साथ कैम्बे शेल में जलाशय का कोई विकास नहीं हुआ। यह भी दर्ज किया गया था कि भूकंप-सूचक से अच्छी तरह से टाई के लिए डेटा सीमित था।

v. चरण-I में हाइड्रोकार्बन की खोज न होने के कारण, यह निर्णय लिया गया (अगस्त 2015) अन्वेषण के चरण-II में प्रवेश नहीं करने और ब्लॉक को छोड़ने के परिणामस्वरूप ₹145 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ (न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के पूरा न होने के कारण ₹37.32 करोड़ की परिसमापन क्षति और परिसमापन क्षति के विलंब से भुगतान पर ₹0.15 करोड़ के ब्याज सहित)।

इस प्रकार, ब्लॉक में पर्याप्त स्रोत चट्टान, माइग्रेशन पथ, जलाशय और सील जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए बुनियादी तत्वों की कमी के परिणामस्वरूप किसी भी हाइड्रोकार्बन की खोज नहीं हुई थी और परिणामस्वरूप ₹145 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2021) में कहा कि इन-हाउस या बाहरी सलाहकारों द्वारा डीजीएच से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी से केवल तकनीकी तथ्य एकत्र किए गए थे और कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि सफलता की भूवैज्ञानिक संभावना का 3 प्रतिशत एक लीड के लिए मैसर्स आरआईएससी द्वारा गणना की गई थी और शेष चार लीड/संभावनाएं रेंज 9 प्रतिशत से 46 प्रतिशत तक थीं।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकृत नहीं है क्योंकि परामर्शदाताओं द्वारा अपनी रिपोर्टें (मार्च/अप्रैल 2008) में उल्लिखित सभी तकनीकी तथ्य परियोजनाओं में कम क्षमता स्थापित करने के लिए पर्याप्त थे और संबद्ध जोखिम और चुनौतियों के संबंध में स्व-व्याख्यात्मक थे। एकत्र किए गए तथ्यों और आंकड़ों ने ठोस सबूत प्रदान किए कि बाहरी सलाहकार रिपोर्ट में व्यक्त आरक्षण और सीमाएं, जैसे कि पहले ड्रिल किए गए कुओं में किसी भी हाइड्रोकार्बन का कोई संकेत नहीं था, खराब भूकंप-सूचक डेटा गुणवत्ता और लॉग डेटा / अच्छी तरह से जानकारी आदि की अपर्याप्तता, परियोजना की विश्वसनीयता और व्यवहार्यता पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त आईओसीएल ने इन ब्लॉकों के लिए बोली लगाने का निर्णय लेते समय इन तथ्यों को अपने बीओडी के साथ साझा नहीं किया था।

ब्लॉकों की संभावना, हाइड्रोकार्बन के व्यवहार्य भंडारों की उपलब्धता दर्शाने वाले बुनियादी तत्वों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के संबंध में इन हाउस सलाहकार के साथ-साथ तीसरे पक्ष के सलाहकार द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों की अनदेखी करने के परिणामस्वरूप, विशेष रूप से जब आईओसीएल को अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में कोई ऑपरेटरशिप अनुभव नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप ₹145 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ है।

इस मामले की सूचना अप्रैल 2022 में मंत्रालय को दी गई थी; उनके उत्तर (अगस्त 2022) प्रतीक्षित है।

सिफारिश संख्या 6: कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करे कि निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण जानकारी निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाए। कंपनी इस मामले में खामियों के लिए जिम्मेदारी भी निधारित करे।

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

2.8 अव्यवहार्य एनईएलपी ब्लॉकों के त्याग के बाद उन पर परिहार्य व्यय

परियोजना की प्रतिकूल आर्थिक व्यवहार्यता और परीक्षण आवश्यकता नीति, 2015 के अनुसार वाणिज्यिकता की घोषणा के अनुमोदन के लिए आवश्यक ड्रिल स्टेम टेस्ट करने में ओएनजीसी की विफलता के कारण इसके दो एनईएलपी ब्लॉकों पर उनके त्याग के बाद ₹23.12 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

भारत सरकार ने अप्रैल, 2000 और जुलाई, 2001 में ओएनजीसी को महानदी बेसिन में दो एनईएलपी²⁶ ब्लॉक अर्थात एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/3 और एमएन-ओएसएन-2000/2 प्रदान किए। ओएनजीसी एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/3 ब्लॉक में 100 प्रतिशत सहभागी हित के साथ ऑपरेटर थी। ब्लॉक एमएन-ओएसएन-2000/2 में ओएनजीसी अन्य कंसोर्टियम भागीदारों अर्थात गेल (इंडिया) लिमिटेड के साथ 40 प्रतिशत सहभागी हित, ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ 20 प्रतिशत सहभागी हित के साथ ऑपरेटर था। एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/3 ब्लॉक में कुओं एमडीडब्ल्यू-4ए और एमडीडब्ल्यू-5 में गैर-संबद्ध प्राकृतिक गैस²⁷ की दो खोजों को क्रमशः अप्रैल/दिसम्बर, 2007 में अधिसूचित किया गया था। एमएन-ओएसएन-2000/2 ब्लॉक में, दिसंबर 2006 में कूप एमडीडब्ल्यू-2ए में पहली गैर-संबद्ध प्राकृतिक गैस की खोज की गई थी और दिसंबर 2010 में कूप एमडीडब्ल्यू-10 में दूसरी खोज की गई थी। दूसरी खोज को दिसंबर 2010 में

²⁶ हाईड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन में पीयूब्लिक और पीरिवेट क्षेत्र की कंपनियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1997-98 के दौरान नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) तैयार की गई थी।

²⁷ प्राकृतिक गैस का उत्पादन या तो कच्चे तेल के सहयोग के बिना या कच्चे तेल की ऐसी मात्रा के सहयोग से किया जाता है जिसे स्वयं वाणिज्यिक रूप से उत्पादित नहीं किया जा सकता है।

अधिसूचित किया गया था। दोनों ब्लॉकों के संबंध में वाणिज्यिकता की घोषणा²⁸ नवंबर/दिसम्बर, 2013 में हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को प्रस्तुत की गई थी। हालाँकि, ड्रिल स्टेम टेस्ट (डीएसटी) की अनुपस्थिति में, डीजीएच द्वारा वाणिज्यिकता की घोषणा की समीक्षा नहीं की गई थी। ओएनजीसी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) से (नवम्बर, 2014) अनुरोध किया था कि जब तक उभरती प्रौद्योगिकियां वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में गैस विकास और उत्पादन को व्यवहार्य नहीं बना देतीं, तब तक कंपनी को दोनों ब्लॉकों के खोज क्षेत्र को बनाए रखने की अनुमति दी जाए। ओएनजीसी ने मंत्रालय को यह भी सूचित किया कि यह परियोजना तत्कालीन प्रचलित प्रौद्योगिकियों के आधार पर व्यवहार्य नहीं थी और यह परियोजना लगभग 11 अमरीकी डॉलर से 13/एमएमबीटीयू²⁹ तक गैस मूल्य पर ही अथक रूप से व्यवहार्य होगी।

संविदाकारों को खोजों का मुद्रीकरण करने की अनुमति देने के उद्देश्य से, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 12 खोजों के संबंध में परीक्षण आवश्यकता के लिए एक नीति (अप्रैल 2015) की घोषणा की, जिनकी ड्रिल स्टेम टेस्ट³⁰ डेटा की अनुपलब्धता के कारण समीक्षा नहीं की गई थी और जिनकी वाणिज्यिकता की घोषणा जमा करने की समयसीमा समाप्त हो गई थी। एमएन-डीडब्ल्यूटी-98/3 (एमडीडब्ल्यू-4ए और एमडीडब्ल्यू-5) में ओएनजीसी की दो खोजों और एमएन-ओएसएन-2000/2 (एमडीडब्ल्यू-10) में एक खोज को नीति के तहत कवर किया गया था। नीति के अनुसार, संविदाकारों के पास तीन विकल्प उपलब्ध थे, अर्थात्,

विकल्प 1: खोजों से जुड़े अनुबंध क्षेत्र को त्याग दें,

विकल्प 2: ड्रिल स्टेम टेस्ट का संचालन (जो पहले आयोजित नहीं किया गया था) और सीसीईए नीति की तिथि से एक वर्ष के भीतर संशोधित वाणिज्यिकता की घोषणा प्रस्तुत

²⁸ ठेकेदार द्वारा डीजीएच को भेजे गए कुएं से प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर लिखित संचार यह घोषणा करते हुए कि अनुबंधित क्षेत्र में की गई खोज वाणिज्यिक क्षेत्र है।

²⁹ मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (गर्मी ऊर्जा की इकाई, 1 बीटीयू 252 कैलोरी के बराबर है)।

³⁰ एक कुएं की ड्रिलिंग के दौरान भूवैज्ञानिक संरचना के दबाव, पारगम्यता और उत्पादक क्षमता को अलग करने और परीक्षण करने की प्रक्रिया। यह ड्रिल स्टेम पर दबाव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण माप है और गठन द्रव के बारे में जानकारी प्राप्त करने और यह स्थापित करने का एक मूल्यवान तरीका है कि क्या कुएं में प्रवाह क्षमता है।

करें और विकास के साथ आगे बढ़ें, जिसमें विफल रहने पर संविदाकार इन खोजों को शामिल करने वाले क्षेत्र और इन खोजों को विकसित करने के अधिकार को त्याग देगा, और

विकल्प 3: ड्रिल स्टेम टेस्ट और रिंग फेंसड ऐसी खोजों³¹ का संचालन किए बिना खोजों के विकास के साथ आगे बढ़ें।

नीति में आगे कहा गया है कि यदि इन खोजों के संविदाकारों ने सीसीईए नीति के 60 दिनों के भीतर तीन विकल्पों में से किसी एक का विकल्प का चयन नहीं किया, तो इन खोजों में शामिल क्षेत्र स्वतः त्याग दिया जाएगा।

ओएनजीसी ने दूसरे विकल्प के लिए (जून 2015) का चयन किया और तदनुसार, ड्रिल स्टेम टेस्ट आयोजित करने के अधीन संशोधित वाणिज्यिकता की घोषणा प्रस्तुत करने के लिए 29 अप्रैल 2015 से 28 अप्रैल 2016 तक, 12 महीने का विस्तार दिया गया। कंपनी ने ड्रिल स्टेम टेस्ट किए बिना 26 अप्रैल 2016 को डीजीएच/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को संशोधित वाणिज्यिकता की घोषणा प्रस्तुत की। यह नीति में प्रदान किए गए सीसीईए अनुमोदित विकल्प का विचलन था। डीजीएच ने ड्रिल स्टेम टेस्ट का संचालन नहीं करने के कारण ओएनजीसी द्वारा प्रस्तुत संशोधित वाणिज्यिकता की घोषणा (दिसंबर 2016/ मार्च 2017) को अस्वीकृत कर दिया और दोनों ब्लॉकों को 29 अप्रैल 2016 से छोड़ दिया गया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- i. ओएनजीसी ने सीसीईए नीति की तिथि से एक वर्ष की निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित ड्रिल स्टेम टेस्ट किए बिना डीजीएच/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को संशोधित वाणिज्यिकता की घोषणा प्रस्तुत की। परिणामस्वरूप, डीजीएच ने वाणिज्यिकता की घोषणा को खारिज कर दिया और 29 अप्रैल 2016 से दो ब्लॉकों को छोड़ दिया गया।
- ii. ओएनजीसी ने अप्रैल 2016 से डीजीएच द्वारा छोड़ने के बाद भी भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय गतिविधियों, प्रशासनिक ओवरहेड्स और पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस व्ययों के

³¹ रिंग फेंसड एक आभासी बाधा/कानूनी दीवार है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के एक हिस्से को अलग करती है जैसे खोज, विकास क्षेत्र/क्षेत्र/अनुबंध क्षेत्र। यह आमतौर पर एक विशिष्ट परियोजना के लिए धन आरक्षित/प्रतिबंधित करने के लिए होता है ताकि परिसंपत्तियों को नुकसान से बचाया जा सके जो रिंग फेंसड से परे अन्य जोखिम वाले क्षेत्र में संचालन के कारण हो सकता है। रिंग फेंसड खोजों से जुड़े राजस्व और लागत का अलग से हिसाब लगाया जाएगा।

लिए ₹23.12 करोड़ (2016-17 में ₹21.10 करोड़ और 2017-18 में ₹2.02 करोड़) का परिहार्य व्यय किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में कहा कि:

- i. एकीकृत परीक्षण रेंज में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण पहचाने गए रिग को परीक्षण के लिए तैनात नहीं किया जा सका।
- ii. पारंपरिक परीक्षण करने के लिए ओएनजीसी द्वारा अनुरोधित एक महीने के अतिरिक्त समय पर डीजीएच द्वारा सहमति नहीं दी गई थी और डीजीएच ने ब्लॉकों को छोड़ने का अनुरोध किया था।
- iii. ओएनजीसी ने विकल्प-2 के लिए त्वरित अनुमोदन के लिए (जनवरी 2017) फिर से अनुरोध किया, हालांकि, डीजीएच ने दोनों ब्लॉकों को छोड़ने के निर्णय (मार्च 2017) को सूचित किया।
- iv. ओएनजीसी ने ब्लॉकों में उन क्षेत्रों का पता लगाना जारी रखा जिनमें दिलचस्प संभावित विशेषताएं हैं; जो ज्ञान के आधार को बढ़ाने में मददगार होगा।
- v. जनशक्ति लागत और ओवरहेड्स की लागत प्रकृति में थी, और कंसोर्टियम भागीदारों की सहमति से व्यय की गई थी।
- vi. तथापि, मंत्रालय इस बात पर सहमत हुआ कि ओएनजीसी सीसीईए द्वारा अनुमोदित भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयबद्धता और प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही। इसलिए ओएनजीसी को मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए मंत्रालय और ओएनजीसी के प्रयासों और स्वीकृति को स्वीकार करते हुए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है:
 - i. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, रक्षा मंत्रालय द्वारा साइट पर लगाए गए प्रतिबंध केवल नवंबर-दिसंबर 2015 के दौरान लागू थे। उसके बाद लंबित परीक्षण पूरे किए जा सकते थे।
 - ii. ओएनजीसी द्वारा जनवरी 2017 में विकल्प-2 का प्रयोग करने का फिर से अनुरोध करने के बारे में प्रतिक्रिया बिंदु विकल्प मौजूद थी, क्योंकि ओएनजीसी ने जून 2015 में ही इस विकल्प का उपयोग किया था।

iii. ओएनजीसी भले ही कहीं और दिलचस्प अन्वेषण में लगी हुई हो, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि ड्रिल स्टेम टेस्ट समय पर पूरा किया जाएगा- जो ओएनजीसी को संविदात्मक रूप से करने के लिए अनिवार्य किया गया था, जिसके लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, ओएनजीसी ने एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि प्राप्त की थी। इस प्रकार, परियोजना की प्रतिकूल आर्थिक व्यवहार्यता और सीसीईए द्वारा अनुमोदित परीक्षण आवश्यकता नीति, 2015 के अनुसार वाणिज्यिकता की घोषणा के अनुमोदन के लिए आवश्यक ड्रिल स्टेम टेस्ट करने में विफलता के बावजूद, ओएनजीसी ने अपने दो एनईएलपी ब्लॉकों पर उनके छोड़ने के बाद ₹23.12 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

सिफारिश संख्या 7: ओएनजीसी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रियाएं/प्रक्रिया स्थापित कर सकती है जिसके द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ऑयल इंडिया लिमिटेड

2.9 कंडेनसेट के विक्रय के लिए निविदा को अंतिम रूप देने में अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के परिणामस्वरूप राजस्व की कम वसूली हुई

कंडेनसेट की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता के बावजूद, ओआईएल इच्छुक बोलीदाताओं के साथ कंडेनसेट के विक्रय के लिए किसी भी अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहा और अंततः, इसे कच्चे तेल के साथ मिश्रित कर दिया और ₹24 करोड़ की अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया।

ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल), एक राष्ट्रीय तेल कंपनी, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस निकालती है। यह असम के दुलियाजान में अपने एलपीजी संयंत्र में प्राकृतिक गैस का प्रसंस्करण करके तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का उत्पादन भी करता है। एलपीजी का उत्पादन करते समय, कंडेनसेट³² नामक एक उप-उत्पाद उत्पन्न होता है। ओआईएल घरेलू बाजार में रासायनिक उत्पादों के विनिर्माताओं को कंडेनसेट विक्रय करती है और तेल रिफाइनरियों को आपूर्ति के लिए बिना विक्रय मात्रा, यदि कोई हो, को कच्चे तेल के साथ

³² कंडेनसेट हल्के तरल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, जो बहुत हल्के कच्चे तेल के समान है। यह आमतौर पर उत्पादन के बिंदु पर प्राकृतिक गैस धारा से अलग हो जाता है जब गैस का तापमान और दबाव वायुमंडलीय स्थिति में गिरा दिया जाता है।

मिश्रित किया जाता है। दुनियाजान में ऐसे कंडेनसेट का उत्पादन लगभग 20,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और अधिकतम मासिक उत्पादन 2,000 मीट्रिक टन है। ओआईएल घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली के तहत खुली निविदा के एवज में इच्छुक पात्र खरीदारों को कंडेनसेट विक्रय करती है।

कंडेनसेट के विक्रय के लिए पिछला अनुबंध ओआईएल द्वारा सितंबर 2016 में दो वर्ष के लिए दिया गया था। ओआईएल ने अप्रैल 2018 में फिर से, कंडेनसेट विक्रय जारी रखने के लिए, निविदा जारी किया। लेकिन बाद में, बोली खोलने की तिथि से पहले, आधार-मूल्य निर्धारित करने की विधि के बारे में एक मुद्दे को हल करने के लिए इसे रद्द कर दिया गया था।

ओआईएल ने आधार मूल्य के निर्धारण के मुद्दे को सुलझाने के बाद मई 2019 में एक नई निविदा जारी की थी। 300 एम.टी. (न्यूनतम) से 2,000 एम.टी. (अधिकतम) प्रति माह कंडेनसेट के क्रय हेतु बोलियाँ आमंत्रित करने के लिए निविदा जारी किए गए जिस पर तीन पक्षों ने अपने दरों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव बोली प्रतिभूति प्रस्तुत न करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था। एच1 बोलीदाता {एल्कॉन पेट्रो प्राइवेट लिमिटेड (एपीपीएल)} ने 300 मीट्रिक टन कंडेनसेट के क्रय के लिए बोली प्रस्तुत की। एच 2 बोलीदाता {मैसर्स ईस्टर्न केमिकल इंडस्ट्री (ईसीआई)} ने 550 मीट्रिक टन के क्रय के लिए बोली प्रस्तुत की। ओआईएल ने एच 2 बोलीदाता (ईसीआई) के साथ एच 1 बोलीदाता द्वारा उद्धृत अपनी दर से मेल खाने के लिए बातचीत की, जो अगस्त 2019 पर सहमत हुए।

ओआईएल ने दोनों पक्षों से (सितंबर 2019) अपनी मासिक उठाने की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया। हालांकि, इसके उत्तर में, मैसर्स ईसीआई (एच2) ने (सितंबर 2019) से अनुरोध किया कि वे अपनी लिफ्टिंग मात्रा को 550 मीट्रिक टन की उद्धृत मात्रा की तुलना में घटाकर 300 मीट्रिक टन प्रति माह करने पर विचार करें।

लेखापरीक्षा में पाया गया दोनों बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत मात्रा (300 एम.टी. और 550 एम.टी.) निविदा में विनिर्दिष्ट न्यूनतम मात्रा (300 एम.टी.) के समान/अधिक होने के बावजूद ओआईएल ने (फरवरी 2020) निविदा को यह कारण देकर रद्द कर दिया कि कंडेनसेट के बहुत अधिक मासिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए अल्प मात्रा उपयुक्त नहीं होगी। ओआईएल ने सीवीओ (नवंबर 2019) और कॉरपोरेट बिजनेस कमेटी (सीबीसी)

की सलाह का हवाला देते हुए पीएसयू को कंडेनसेट बेचने की संभावना तलाशने का फैसला किया, जो काफी समय बीत जाने के बावजूद (दिसंबर 2021) भी अंतिम रूप नहीं ले सका। इस प्रकार, कंडेनसेट की पर्याप्त मात्रा और इच्छुक बोलीदाताओं की उपलब्धता के बावजूद, ओआईएल ने निविदा को रद्द कर दिया जो वाणिज्यिक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। ओआईएल ने अंततः इसे कच्चे तेल के साथ मिश्रित किया और अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया क्योंकि इससे केवल सम्मिश्रण के परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमत प्राप्त की, जो कंडेनसेट की कीमतों से बहुत कम थी। वैध बोलीदाताओं की पेशकश को स्वीकार करके, ओआईएल जनवरी 2020 से अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान ₹24 करोड़³³ (अनुलग्नक 1) का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त कर सकती थी।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में कहा कि:

- मैसर्स ईसीआई ने प्रति माह 550 मीट्रिक टन के उठाव की प्रतिबद्ध मात्रा के साथ अपनी बोली प्रस्तुत की थी। तथापि, तकनीकी बोली खोलने के बाद मैसर्स ईसीआई ने निविदा में संशोधन की मांग की थी और ओआईएल से अपनी मूल रूप से उद्धृत लिफ्टिंग मात्रा को 550 मीट्रिक टन से घटाकर 300 मीट्रिक टन करने पर जोर दिया था। यह उनकी बोली के मूल पैरामीटर में निविदा पश्चात संशोधन होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।
- निविदा में अन्य स्वीकृत बोलीदाता एपीपीएल था, जिसने कुल 2,000 एम.टी. प्रति माह के उपलब्ध निविदा मात्रा में से केवल 300 एम.टी प्रति माह उठाव का प्रस्ताव दिया था। इसलिए सीवीओ और सीबीसी की सलाह की पृष्ठभूमि में केवल गैर-पीएसयू को 300 मीट्रिक टन की मामूली मात्रा के लिए निविदा देने पर विचार नहीं किया गया।
- निविदा रद्द होने के बाद ओआईएल ने प्रतिष्ठित ग्राहक आधार बनाने के लिए आईओसीएल, एनआरएल और बीसीपीएल के साथ मामला उठाया था। इसके बाद, एनआरएल और आईओसीएल ने कंडेनसेट क्रय करने से इनकार कर दिया। बीसीपीएल के साथ बातचीत अभी भी प्रक्रिया में थी।

³³ रुढ़िवादी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, गणना न्यूनतम गारंटीकृत उत्थान मात्रा के आधार पर की गई है जो एनआईटी के प्रावधानों के अनुसार अनुबंधित मात्रा (600 मीट्रिक टन) का 80 प्रतिशत है जो 480 मीट्रिक टन है।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन का तर्क स्वीकार्य नहीं है:

- ओआईएल ने स्वयं बोलीदाताओं से उद्धृत उठाव मात्रा से अधिक मासिक उठाव मात्रा बढ़ाने हेतु निविदा उपरांत वार्ता आरम्भ की थी। इस तरह की बातचीत के उत्तर में, ईसीआई ने कंडेनसेट की उठाने की मात्रा को प्रति माह 300 मीट्रिक टन तक कम करने का अनुरोध किया। इस प्रकार, ओआईएल द्वारा ईसीआई के साथ की गई निविदा पश्चात बातचीत का लाभ नहीं उठाया जा सका, जो एच1 बोलीदाता के मूल्य से मेल खाने के लिए सहमत हो गया था क्योंकि ओआईएल ने सीमित ग्राहक आधार और बोली दस्तावेज में निर्धारित लिफ्टिंग की न्यूनतम मात्रा (300 मीट्रिक टन) की पृष्ठभूमि में ईसीआई के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया था।
- सीबीसी और सीवीओ ने ओआईएल को कंडेनसेट को किसी निजी पार्टी को बेचने से नहीं रोका, इसने केवल पीएसयू को कंडेनसेट की विक्रय की संभावना तलाशने का सुझाव दिया ताकि एक प्रतिष्ठित ग्राहक आधार बनाया जा सके।
- 300 एम.टी. प्रति माह न्यूनतम मात्रा हेतु निविदा को अनुमेय करने के प्रावधान के बावजूद, ओआईएल ने 300 एम.टी. प्रत्येक के इच्छुक बोलीदाताओं के प्रस्ताव को "अल्प मात्रा" का कारण उद्धृत करते हुये स्वीकृत नहीं किया गया। इस प्रकार, ओआईएल कम से कम 600 मीट्रिक टन प्रति माह के लिए कंडेनसेट की विक्रय से राजस्व प्राप्त करने में विफल रही।

इस प्रकार, ओआईएल दिसंबर 2021 तक किसी भी पीएसयू के साथ किसी भी अनुबंध को अंतिम रूप देने में विफल रही। ओआईएल के लिए यह वाणिज्यिक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय हो सकता था कि वह इच्छुक पक्षों को प्रति माह कम से कम 600 मीट्रिक टन कंडेनसेट विक्रय करे और साथ ही, प्रति माह 1,400 मीट्रिक टन की शेष कंडेनसेट के निपटान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बातचीत करने की संभावना का पता लगाना जारी रखे। ओआईएल, अंततः, निविदा प्रक्रिया के दौरान अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में विफल रही।

इस मामले की सूचना जनवरी 2022 में मंत्रालय को दी गई थी; उनके उत्तर (अगस्त 2022) प्रतीक्षित है।

अध्याय III: विद्युत मंत्रालय

दामोदर घाटी निगम

3.1 वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के कारण हानि

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने बेरमो खानों के लिए वैध खनन पट्टा लिए बिना अधिभार को हटाने और कोयले के परिवहन के लिए एक संविदाकार को काम सौंप दिया, जिसके परिणामस्वरूप डीवीसी को ₹7.78 करोड़ की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, खनन पट्टे का नवीकरण नहीं होने के कारण अयस्कों के प्रेषण के लिए अनिवार्य ऑनलाइन चालान उत्पन्न करने में डीवीसी की विफलता के कारण डीवीसी के स्टॉकयार्ड में ₹17.95 करोड़ का कोयला जमा हो गया।

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने भूमिगत कोयला खनन के लिए 35 वर्षों की अवधि के लिए जनवरी 1951 में भारत सरकार से बेरमो माइंस, झारखंड (तत्कालीन बिहार) का खनन पट्टा प्राप्त किया। जनवरी 1986 में, बेरमो खानों के खनन पट्टे को 31 दिसंबर 2015 तक नवीनीकृत किया गया था। चूंकि बेरमो खानों का खनन पट्टा 31 दिसंबर 2015 को समाप्त हो रहा था, इसलिए डीवीसी ने 1 जनवरी 2016 से खनन पट्टे के विस्तार के लिए जिला खनन कार्यालय, बोकारो में आवेदन (3 दिसंबर 2014) किया। डीवीसी को उसी दिन सूचित किया गया था कि आवेदन आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों¹ के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसे 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

इस तथ्य को जानते हुए भी कि अनुमोदित खनन योजना खनन पट्टे के नवीकरण के लिए एक पूर्व-अपेक्षित थी, डीवीसी ने नवंबर 2015 में ही खनन योजना तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की, अर्थात् जिला खनन कार्यालय, बोकारो द्वारा आवश्यक आवश्यकता के बारे में सूचित किए जाने के 10 महीने बाद और खनन पट्टे की समाप्ति से सिर्फ एक महीने पहले। हालांकि, डीवीसी के पास वैध खनन पट्टा नहीं था, लेकिन इसने (सितंबर 2016) ₹14.11 करोड़ की लागत से बेरमो खानों से मैसर्स बीकेबी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट

¹ अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण स्वीकृति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड से प्रचालन के लिए सहमति, तकनीकी व्यक्तियों की सूची, निदेशक मंडल की सूची, निर्धारित जांच सूची में पट्टा धारक क्षेत्र की जानकारी, पिछले पांच वर्षों के उत्पादन और प्रेषण के आंकड़ों का विवरण और डीवीसी की पट्टा अवधि के दौरान सामाजिक कल्याण पर व्यय रिपोर्ट।

लिमिटेड (संविदाकार) को कोयले के अधिभार को हटाने और कोयले की ढुलाई के लिए भारी अर्थ मूविंग मशीनरी की तैनाती का काम सौंपा। डीवीसी ने अंततः अप्रैल 2017 में स्वीकृति के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को बेरमो खानों के लिए खनन योजना और अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस बीच, डीवीसी ने खनन पट्टा समाप्त होने (31 दिसंबर 2015) के बाद भी और जिला खनन कार्यालय में वैध नवीकरण आवेदन दायर किए बिना (अगस्त 2017 तक) खनन जारी रखा।

उपायुक्त सह मजिस्ट्रेट कार्यालय, बोकारो ने झारखंड सरकार द्वारा जारी नोटिस (मार्च 2014) के आधार पर 1 नवंबर 2016 से अयस्क भेजने के लिए ऑनलाइन चालान अनिवार्य कर दिया था। ये ऑनलाइन चालान डीवीसी द्वारा जनरेट नहीं किए जा सके क्योंकि उसके पास अनुमोदित खनन योजना नहीं थी। इसलिए डीवीसी ने ऑनलाइन चालान के अभाव में कोयले की ढुलाई न होने का हवाला देते हुए (अगस्त 2017) खनन कार्य रोक दिया। परिणामस्वरूप, संविदाकार जनवरी 2017 से जुलाई 2017 तक ₹17.95 करोड़ मूल्य का 59,850.10 मीट्रिक टन कोयला नहीं भेज सका, जो डीवीसी के स्टॉकयार्ड में ढेर रहा। इस बीच निगम ने संविदाकार को अधिभार हटाने के लिए ₹7.78 करोड़ का भुगतान किया। भारत सरकार ने निम्नलिखित कारणों से डीवीसी के पक्ष में खनन पट्टे का नवीनीकरण नहीं करने और इसे सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया (मई 2018):

- विभिन्न तकनीकी कारणों और खनन, संसाधनों और स्वीकृति में विशेषज्ञता की कमी के कारण 2017 से खदान बंद थी।
- डीवीसी से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को बेरमो खानों के हस्तांतरण से कोयला उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाया जा सकेगा क्योंकि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास विशेषज्ञता है और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयले की विक्रय डीवीसी की खपत से अधिक है।
- सचिव (विद्युत) ने टिप्पणी की कि मौजूदा दिशानिर्देशों² के तहत, डीवीसी को खनन पट्टे का नवीकरण नहीं किया जा सकता है।

² कोयला खान अधिनियम 2015 के अध्याय II के खंड संख्या 5 का उल्लेख करते हुए, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार पावर कंपनी को अनुसूची/खानों को आवंटित कर सकती है। बेरमो खान अनुसूची-1 खानों की सूची में नहीं थी और इसलिए डीवीसी के पक्ष में इसका नवीकरण नहीं किया जा सका।

हालांकि, इसे फरवरी 2022 तक डीवीसी द्वारा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को नहीं सौंपा गया था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- खनन कार्यालय में वैध खनन पट्टा नवीकरण आवेदन के बिना खनन पट्टे की समाप्ति के बाद भी डीवीसी द्वारा निरंतर खनन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन था।
- जिला खनन अधिकारी, बोकारो द्वारा दिसंबर 2014 में ही डीवीसी को सूचित किया गया था कि खनन योजना पट्टे के नवीकरण के लिए एक पूर्व-आवश्यकता थी जो जनवरी 2016 में देय थी। डीवीसी को यह भी जानकारी थी कि झारखंड सरकार ने नोटिस (मार्च 2014) जारी किया था कि अयस्कों और खनिजों के प्रेषण की अनुमति ऑनलाइन ट्रांजिट चालान होने के बाद ही दी जाएगी और यह खनन पट्टे के अभाव में ऑनलाइन ट्रांजिट चालान उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं होगा। इसके बावजूद डीवीसी ने नवंबर 2015 में अर्थात् करीब 20 महीने की विलंब के बाद खनन योजना तैयार करने की कार्रवाई शुरू की। इससे डीवीसी प्रबंधन की ओर से गंभीरता की कमी का संकेत मिलता है।
- खनन पट्टे के नवीकरण और ऑनलाइन ट्रांजिट चालान प्राप्त करने में समस्याओं को जानने के बावजूद, डीवीसी द्वारा संविदाकार को ₹14.11 करोड़ की लागत से बेरमो माइंस से कोयले के अधिभार हटाने और परिवहन के लिए संविदा देना विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था।
- इसके अतिरिक्त, डीवीसी ने बिना किसी लाभ के अधिभार हटाने के लिए संविदाकार को ₹7.78 करोड़ का भुगतान किया।

इस प्रकार, डीवीसी के स्टॉकयार्ड में पड़े ₹17.95 करोड़ मूल्य के 59,850.10 मीट्रिक टन कोयले के हानि के साथ अधिभार हटाने के लिए ₹7.78 करोड़ का हानि दो कारणों से था अर्थात्, खनन पट्टे का नवीकरण नहीं होना और परिणामस्वरूप ऑनलाइन ट्रांजिट चालान नहीं मिलना। दोनों चीजें नहीं हो सकीं क्योंकि डीवीसी के पास अनुमोदित खनन योजना, खान बंद करने की योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति आदि जैसे अपेक्षित दस्तावेज नहीं थे।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए, प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2021/अप्रैल 2022) कि जैसा की सितंबर 2021 में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड डीवीसी के थर्मल पावर स्टेशनों को सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार बेरमो खानों के

कोयले की आपूर्ति करेगा और इसलिए, अधिभार हटाने के लिए ₹7.78 करोड़ का व्यय वसूल किया जाएगा।

हालांकि, बैठक के कार्यवृत्त (सितंबर 2021) में, यह उल्लेख किया गया था कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड बरमो खानों को सोंपने के बदले डीवीसी को प्रति वर्ष 2.5 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का फर्म लिंकेज सुनिश्चित करेगा। लेकिन उपरोक्त बैठक के कार्यवृत्त में अधिभार हटाने की लागत के रूप में ₹7.78 करोड़ की वसूली के बारे में कोई संकेत नहीं था। अतः प्रबंधन का यह तर्क कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लि से ₹778 करोड़ की अधिभार हटाने की लागत वसूल की गई थी, बैठक के कार्यवृत्त के अनुरूप नहीं है।

इस प्रकार, वैध खनन पट्टा के बिना बरमो खानों के लिए खनन अनुबंध देने और परिणामस्वरूप ऑनलाइन ट्रांजिट चालान की कोई संभावना नहीं होने के परिणामस्वरूप ₹17.95 करोड़ मूल्य के 59,850.10 मीट्रिक टन कोयले के हानि के साथ अधिभार हटाने की लागत के रूप में ₹7.78 करोड़ का हानि हुआ।

नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

3.2 ₹85.35 करोड़ का परिहार्य व्यय

नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने इसकी विद्युत उत्पादन इकाइयों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय का निर्धारण करने में असमर्थता और ट्रांसमिशन लाइन के साथ सिंक्रनाइज़ेशन में परियोजना को पूरा करने में विफलता के कारण कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को निष्क्रिय पारिषण शुल्क के भुगतान के कारण ₹85.35 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

एनटीपीसी लिमिटेड और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने सितंबर 2008 में नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया, जिसमें दोनों की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड³ जून 2018 में एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। इसका नाम 17 फरवरी 2019 से नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (कंपनी) कर दिया गया। संयुक्त उद्यम का गठन कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की 3x660 मेगावाट क्षमता की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए किया गया था। यूनिट 1 को

³ 17 फरवरी 2019 से इसका नाम बदलकर नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड कर दिया गया।

अप्रैल 2017 तक चालू किया जाना था और यूनिट 2 और 3 को उसके बाद छह महीने के अंतराल पर चालू किया जाना था।

नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने (18 मार्च 2016) एक कार्यान्वयन समझौता किया, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन को 30 अप्रैल 2019 तक चालू किया जाना था। हालांकि, कंपनी ने (मार्च 2016) पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से अनुरोध किया कि वह सितंबर 2017 तक पहली इकाई (30 सितंबर 2017 को चालू होने के लिए निर्धारित) के साथ मेल⁴ खाने वाली एक ट्रांसमिशन लाइन चालू करे। कार्यान्वयन समझौते के अनुसार, यदि उत्पादन स्टेशन की संबंधित इकाइयां समझौते के अनुसार एसोसिएटेड ट्रांसमिशन प्रणाली की निर्धारित कमीशनिंग तिथि तक चालू नहीं होती हैं (एसोसिएटेड ट्रांसमिशन प्रणाली की कमीशनिंग शेड्यूल 30 अप्रैल 2019 थी), तो जेनरेटिंग कंपनी ट्रांसमिशन शुल्क वहन करेगी यदि ट्रांसमिशन प्रणाली को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वाणिज्यिक संचालन के तहत घोषित किया जाता है जब तक कि जेनरेटिंग स्टेशन मान्यता प्राप्त नहीं हो जाता है।

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्त) विनियमन, 2014 के तहत 2014-19 की अवधि के लिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए कमीशन की तिथि से 31 मार्च 2019 तक ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी के समक्ष एक याचिका दायर की। सीईआरसी ने 22 अप्रैल 2019 के अपने आदेश में कहा कि चूंकि ट्रांसमिशन संपत्ति पहले ही 12 मई 2018 को आ चुकी है, इसलिए तत्काल संपत्ति के लिए अनुमत ट्रांसमिशन शुल्क नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी द्वारा 12 मई 2018 से पहली इकाई के चालू होने की तिथि तक वहन किया जाएगा। तत्पश्चात् पारेषण प्रभारों की बिलिंग, संग्रहण और संवितरण टैरिफ विनियम, 2014 के विनियम 43 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा और 2010 के शेयरिंग विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जाएगा। इस प्रकार, नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी को इकाइयों के पूरा होने के अनुपात में तीनों इकाइयों के पूरा होने तक पारेषण प्रभार वहन करना था अर्थात्, पहली

⁴ *लाभाधियों को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए विद्युत उत्पादन स्टेशन और पारेषण लाइनों को सिंक्रनाइज्ड तरीके से पूरा किया जाना अपेक्षित है। पारेषण लाइन के शीघ्र पूरा होने अर्थात् विद्युत उत्पादन स्टेशन के पूरा होने से पहले पारेषण लाइन निष्क्रिय हो जाएगी जिसके लिए पारेषण प्रभार विद्युत कंपनी द्वारा वहन किया जाना था।*

इकाई के पूरा होने तक पूर्ण पारेषण प्रभार, दूसरी इकाई के पूरा होने तक दो-तिहाई पारेषण प्रभार और तीसरी इकाई के पूरा होने तक एक-तिहाई पारेषण प्रभार।

सीईआरसी के आदेश के मद्देनजर, नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी ने पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मई 2018 से अगस्त 2019 तक (6 सितंबर 2019 को यूनिट 1 के चालू होने तक), सितंबर 2019 से जुलाई 2021 तक ट्रांसमिशन शुल्क का दो तिहाई (23 जुलाई 2021 को यूनिट 2 की कमीशनिंग) और अगस्त 2021 से मार्च 2022 तक एक तिहाई ट्रांसमिशन शुल्क का भुगतान किया (6 मार्च 2022 को यूनिट 3 की कमीशनिंग)। कंपनी ने जनवरी 2022 तक पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ट्रांसमिशन शुल्क के रूप में ₹106.06 करोड़ का भुगतान किया।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- ट्रांसमिशन लाइन को 30 अप्रैल 2019 तक चालू करने के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से सितंबर 2017 तक काम पूरा करने का अनुरोध किया। पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मई 2018 में ट्रांसमिशन लाइन पूरी कर ली थी, लेकिन नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लाइन का उपयोग नहीं कर सकी क्योंकि यूनिट 1 तब तक चालू नहीं हुई थी। इसलिए, एक उत्पादक कंपनी होने के नाते इसे कार्यान्वयन समझौते के अनुसार पारेषण शुल्क वहन करना पड़ा।
- पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से पारेषण लाइन को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध करने से पहले कंपनी के प्रबंधन को सुविधाओं के वास्तविक समापन का वास्तविक निर्धारण करना चाहिए था। गलत निर्धारण और ट्रांसमिशन लाइन के साथ सिंक्रनाइज़ेशन में परियोजना को पूरा करने में विफलता के कारण पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹85.35 करोड़⁵ के निष्क्रिय ट्रांसमिशन शुल्क का भुगतान किया गया।
- नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति की बैठकों के माध्यम से पावरग्रिड कॉर्पोरेशन को परियोजना की प्रगति के बारे में सूचित करती रही है। तथापि, यह नोट किया गया कि भूमि अधिग्रहण में विलंब और यूनिट-1 के पूरा होने

⁵ कंपनी द्वारा भुगतान किया गया पारेषण शुल्क ₹106.06 करोड़ रुपये था। कार्यान्वयन समझौते में योजना के अनुसार यूनिट 1 और 2 के चालू होने के बाद छह महीने के लिए भुगतान किए गए ट्रांसमिशन शुल्क के रूप में ₹20.71 करोड़ की कटौती करके ₹85.35 करोड़ रुपये की गणना की गई है।

में विलंब की सूचना पावरग्रिड कारपोरेशन को नहीं दी गई थी। यह भी नोट किया गया कि जून 2017 में आयोजित बैठक में भी, यूनिट 1 के लिए संभावित पूर्णता तिथि अगस्त 2017 (सितंबर 2017 के निर्धारित समापन के विपरीत) बताई गई थी। परिणामस्वरूप, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ने ट्रांसमिशन लाइन को पूरा (12 मई 2018) किया, हालांकि अनुरोधित तिथि (सितंबर 2017) से विलंब हुआ, लेकिन मूल निर्धारित समय (अप्रैल 2019) से पहले और कंपनी को इस खाते पर निष्क्रिय ट्रांसमिशन शुल्क का भुगतान करना पड़ा।

इस प्रकार, नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को निष्क्रिय पारेषण प्रभारों के भुगतान के कारण ₹85.35 करोड़ का परिहार्य व्यय किया, क्योंकि वह अपनी विद्युत उत्पादन इकाइयों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय का निर्धारण करने में असमर्थता और ट्रांसमिशन लाइन के साथ सिंक्रनाइज़ेशन में परियोजना को पूरा करने में विफलता के कारण थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि (i) उन्होंने यूनिट को समय पर पूरा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन संयंत्र क्षेत्र में भूमि की अनुपलब्धता, बार-बार बंद/हड़ताल और बरसात के मौसम में अत्यधिक बारिश जैसे नियंत्रण से परे कारणों से इसमें विलंब हुआ और (ii) पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भुगतान की गई राशि लाभार्थियों से वसूली योग्य है।

कंपनी के प्रबंधन के उत्तर को निम्नलिखित दृष्टि से देखा जा सकता है:

i. प्रबंधन के उत्तर में उल्लिखित अधिकांश बाधाओं का प्रभाव कार्यान्वयन समझौते की तिथि (मार्च 2016) से पहले था और इस प्रकार ट्रांसमिशन लाइनों को जल्द पूरा करने के लिए पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से अनुरोध करने से पहले प्रबंधन को पता था। भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों ने मार्च 2016 तक परियोजना को प्रभावित किया। वर्ष 2010-2016 के दौरान नक्सलियों द्वारा लगातार बंद बुलाया गया था। मार्च 2016 में कार्यान्वयन समझौते के बाद, केवल 19 दिनों के लिए बंद के कारण परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई थी। भारी बारिश ने सितंबर और अक्टूबर 2016 में केवल दो महीने के लिए परियोजना की प्रगति को प्रभावित किया।

ii. सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2019 के विनियमन 6 के अनुसार, जहां जनरेटिंग स्टेशन ने संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली के वाणिज्यिक संचालन की तिथि तक वाणिज्यिक संचालन हासिल नहीं किया है, तब तक उत्पादक कंपनी संबंधित ट्रांसमिशन प्रणाली के

ट्रांसमिशन शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी जब तक कि जनरेटिंग स्टेशन या उसकी इकाई वाणिज्यिक संचालन प्राप्त नहीं कर लेती है। इसलिए पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भुगतान किए गए पारेषण प्रभार लाभार्थियों से वसूलने योग्य नहीं थे।

इस प्रकार, नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को निष्क्रिय पारेषण शुल्क का भुगतान किया, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के साथ बिजली संयंत्र की कमीशनिंग का सिंक्रनाइज़ेशन नहीं किया गया था।

इस मामले की सूचना फरवरी 2022 में मंत्रालय को दी गई थी; उनके उत्तर (अगस्त 2022) प्रतीक्षित है।

एनएचपीसी लिमिटेड

3.3 एनएचपीसी, मुजफ्फरपुर को ₹13.09 करोड़ कि हानि

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्राप्त शुल्क पर सेवा कर के भुगतान में विलंब के कारण एनएचपीसी लिमिटेड को ₹13.09 करोड़ का हानि हुआ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क विहीन बस्तियों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से जोड़ना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार ने बिहार राज्य में पीएमजीएसवाई कार्य के लिए राष्ट्रीय निष्पादन एजेंसियों के रूप में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नियुक्त किया।

एनएचपीसी को निष्पादन एजेंसी के रूप में चयन किया गया था और पीएमजीएसवाई के तहत बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण/उन्नयन के लिए एनएचपीसी लिमिटेड (एनएचपीसी), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के बीच (31 अगस्त 2004) एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया था। एनएचपीसी पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों में निर्धारित अपने प्रभार वाले जिलों के लिए एक निष्पादन एजेंसी के रूप में आवश्यक सभी कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार था और ग्रामीण विकास

मंत्रालय द्वारा वहन किए जाने वाले सौंपे गए कार्यों (निर्माण और पांच वर्ष के रखरखाव) की कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की दर से शुल्क प्राप्त करने का हकदार था। शुल्क विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत, सभी प्रशासनिक और परियोजना प्रबंधन व्यय को कवर करने के लिए था।

समझौते के खंड 10 के अनुसार, परियोजना के निष्पादन के संबंध में एनएचपीसी या इसके संविदाकार पर लगाए गए कर और शुल्क और एनएचपीसी के परामर्श शुल्क पर सेवा कर परियोजना लागत का अभिन्न अंग होगा और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एनएचपीसी को प्रतिपूर्ति की जाएगी। तथापि, एनएचपीसी अथवा उसके संविदाकार की ओर से करों और शुल्कों के संबंध में लापरवाही/विलंब के कारण शास्ति अथवा दर वृद्धि को परियोजना लागत में समायोजित नहीं किया जाएगा और यह एनएचपीसी को देय नहीं होगा।

एनएचपीसी को वर्ष 2008-09 से 2014-15 के दौरान उपर्युक्त कार्य के लिए ₹127.98 करोड़ रुपए का शुल्क प्राप्त हुआ। तथापि, उपर्युक्त शुल्क पर सेवा कर कंपनी द्वारा इस धारणा पर समय पर जमा नहीं किया गया था कि बिहार में सड़क परियोजनाओं के निर्माण और अनुरक्षण के लिए निष्पादन एजेंसी के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (25बी)⁶ और 105 (जेडजेडजेडजेडए)⁷ के मद्देनजर सेवा कर से मुक्त थीं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त, पटना ने सेवा कर का भुगतान न करने पर कंपनी को मांग-सह-कारण बताओ नोटिस जारी किया। चूंकि सेवा कर निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं किया गया था, इसलिए तालिका 3.1 में विस्तृत रूप से ₹13.09 करोड़ का ब्याज और जुर्माना भी लगाया गया था।

⁶ वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 (25 बी) 'वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण' को परिभाषित करती है।

⁷ वित्त अधिनियम 1994 की धारा 105 (जेडजेडजेडजेडए) में कहा गया है कि कर योग्य सेवा का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन के संबंध में किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा, सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे, परिवहन टर्मिनलों के संबंध में कार्य अनुबंध को छोड़कर।

तालिका 3.1: भुगतान किए गए ब्याज और दंड का विवरण

(राशि: ₹ करोड़ में)

मांग-सह-कारण बताओ नोटिस जारी करने की तिथि	अवधि	कुल राशि	एनएचपीसी द्वारा जमा की गई राशि	भुगतान की तिथि	एनएचपीसी द्वारा चुकाया गया ब्याज और जुर्माना
10.10.2013	2008-09 से 2011-12	10.31	18.23	06.08.2014	7.92
18.09.2017	2012-13 से 2014-15	3.84	9.01	06.02.2019	5.17
28.09.2020	अप्रैल 2015 से जून 2017	0.67	भुगतान नहीं दिया		--
कुल		14.82	27.24		13.09

एनएचपीसी ने सेवा कर के भुगतान में विलंब के कारण ब्याज और जुर्माने के रूप में ₹13.09 करोड़ (₹7.92 करोड़ और ₹5.17 करोड़) का भुगतान किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सितंबर 2017 में एनएचपीसी को ₹7.92 करोड़ का भुगतान किया, लेकिन एनएचपीसी द्वारा ब्याज और जुर्माने के रूप में भुगतान किए गए ₹5.17 करोड़ उनके द्वारा वापस नहीं किए गए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- एनएचपीसी ने परियोजना के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता प्रदान की और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (25 बी) और 105 (जेडजेडजेडजेडजेड) ने सड़क निर्माण परियोजनाओं में परामर्श के काम को छूट नहीं दी। इसलिए, एनएचपीसी ने जिस आधार पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया, वह उचित नहीं था क्योंकि एनएचपीसी ने सड़क का निर्माण स्वयं नहीं किया बल्कि अपनी सेवाएं प्रदान की थी, जिसके लिए उसे शुल्क प्राप्त हुआ था, जिस पर वह सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ₹7.92 करोड़ की प्रतिपूर्ति त्रिपक्षीय समझौते के खंड 10 का उल्लंघन है। राष्ट्रीय निष्पादन एजेंसियों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे पर (14 जून 2021) चर्चा की गई और मंत्रालय ने एनएचपीसी को किए गए ओवर पेमेंट (₹7.92 करोड़) को अभी तक जारी की जाने वाली राशि से वसूलने का फैसला किया।
- इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी ने सितंबर 2020 में मांग के अनुसार ₹0.67 करोड़ (अप्रैल 2015 से जून 2017 तक की अवधि के लिए देय सेवा कर) का भुगतान नहीं किया।

इस राशि पर ब्याज और जुर्माने के भुगतान की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, निर्धारित समय के भीतर सेवा कर का भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप 2008-09 और 2014-15 के बीच की अवधि के लिए ₹13.09 करोड़ के ब्याज और जुर्माने का परिहार्य भुगतान किया गया

एनएचपीसी प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि:

- i. एनएचपीसी ने सेवा कर विभाग की मांग से असहमति जताते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी), कोलकाता के समक्ष अपील (2014) दायर की।
- ii. एनएचपीसी को टर्नकी आधार पर परियोजना निष्पादित करनी थी और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सलाह और परामर्श प्रदान करना नहीं था। 20 जून 2012 को जारी अधिसूचना संख्या⁸ 25/2012 के तहत बिना किसी प्रतिबंध के आम जनता द्वारा उपयोग के लिए सड़क के निर्माण और रखरखाव को विशेष रूप से सेवा कर से छूट दी गई थी।
- iii. ग्रामीण विकास मंत्रालय से ब्याज और जुर्माने के रूप में ₹7.92 करोड़ की प्राप्ति को त्रिपक्षीय समझौते के खंड 10 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।
- iv. विद्युत मंत्रालय ने एनएचपीसी प्रबंधन के उत्तर का समर्थन (मार्च 2022) किया कि 14 जून 2021 को आयोजित ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैठक के बारे में एनएचपीसी को कोई जानकारी नहीं दी गई थी और एनएचपीसी को सुनवाई के अवसर के बिना एकतरफा निर्णय प्राकृतिक न्याय के हित में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी ने कानूनी राय ली थी जिसमें यह राय दी गई थी कि एनएचपीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा सड़कों के निर्माण से संबंधित समग्र सेवा थी और इसे सेवा कर से पूरी तरह से छूट दी गई थी।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए एनएचपीसी प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर स्वीकृत नहीं है:

- i. सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष एनएचपीसी द्वारा दायर अपील (2014) को 5 दिसंबर 2014 को स्थगन आदेश की स्वीकृति की तिथि से सात वर्ष से अधिक समय

⁸ अधिसूचना संख्या 25/2012 दिनांक 20 जून, 2012 की क्रम संख्या 13 में निम्नलिखित सेवाओं को छूट दी गई है- 'आम जनता द्वारा उपयोग के लिए सड़क परिवहन के लिए सड़क, पुल, सुरंग या टर्मिनल के निर्माण, निर्माण, कमीशनिंग, स्थापना, पूर्णता, फिटिंग, मरम्मत, रखरखाव, नवीकरण या परिवर्तन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं'

बीत जाने के बाद भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, स्थगन प्रदान करते समय, सीईएसटीएटी, कोलकाता ने नोट किया था कि चूंकि कंपनी ने पर्याप्त राशि जमा की थी, शेष राशि की पूर्व-जमा राशि और इसकी वसूली पर रोक लगा दी गई थी। इस प्रकार, स्थगन से यह संकेत नहीं मिलता है कि सीईएसटीएटी, कोलकाता ने प्रबंधन के इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया कि सेवा कर देय नहीं था। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी द्वारा 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए सेवा कर की मांग के विरुद्ध एक और अपील (2019) दायर की गई थी, जिसे अभी भी सीईएसटीएटी, कोलकाता द्वारा सुना जाना बाकी था। इसके अतिरिक्त, मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो इसी तरह की शर्तों पर पीएमजीएसवाई की एक निष्पादन एजेंसी भी थी, द्वारा की गई इसी तरह की अपील को सीईएसटीएटी, कोलकाता द्वारा (अप्रैल 2017) खारिज कर दिया गया था और सेवा कर की मांग की पुष्टि की गई थी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, जिसने भी इसी तरह की व्यवस्था के तहत पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए परामर्श/प्रबंधन की समान परियोजना शुरू की थी, ने सेवा कर का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, ब्याज और जुर्माने के भुगतान से बचने के लिए, एनएचपीसी को देय सेवा कर की राशि जमा करनी चाहिए थी और फिर अपना विरोध दर्ज करना चाहिए था।

ii. सेवा कर अधिसूचना संख्या 25/2012 पर सीईएसटीएटी, कोलकाता ने मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए विचार किया था, जिसका उल्लेख ऊपर क्र.सं. i में किया गया है।

iii. त्रिपक्षीय समझौते के खंड 10 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एनएचपीसी की ओर से करों और शुल्कों के संबंध में लापरवाही/विलंब के कारण दंड को परियोजना लागत में समायोजित नहीं किया जाएगा और यह एनएचपीसी को देय नहीं था और इसलिए लेखापरीक्षा अवलोकन के आधार पर, मंत्रालय ने भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली करने का निर्णय लिया है।

iv. 14 जून 2021 को आयोजित ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैठक में एनएचपीसी सहित राष्ट्रीय निष्पादन एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका कार्यवृत्त एनएचपीसी के पास भी उपलब्ध था और इसलिए यह मंत्रालय का एकतरफा निर्णय नहीं था क्योंकि एनएचपीसी को बैठक में भागीदार के रूप में सुनवाई का उचित अवसर दिया

गया था। इसके अतिरिक्त सितंबर 2007, सितंबर 2009 और अप्रैल 2015 में कानूनी राय ली गई थी, जबकि पीएमजीएसवाई कार्यों के अनुवर्ती समीक्षा बैठक (15 जून 2015) में ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव (ग्रामीण कनेक्टिविटी) ने अवगत कराया था कि पीएमजीएसवाई के तहत एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सेवा कर नियमों की नकारात्मक सूची में शामिल नहीं किया गया था और ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रस्ताव पीएमजीएसवाई एजेंसियों के लिए सेवा कर में छूट के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सहमति नहीं दी गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एजेंसियों को भुगतान किए गए सेवा कर के लिए अपने दावे प्रस्तुत करने और उनसे इसकी प्रतिपूर्ति करने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त, सीईएसटीएटी, कोलकाता ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ इसी तरह के मामले में सेवा कर की मांग (अप्रैल 2017) की पुष्टि की थी। इसलिए, निष्पादन एजेंसियों को भुगतान किए गए शुल्क पर सेवा कर की प्रयोज्यता में कोई अस्पष्टता नहीं थी।

एनएचपीसी को निर्धारित समय के भीतर सेवा कर का भुगतान नहीं करने के कारण 2008-09 और 2014-15 के बीच की अवधि के लिए ₹13.09 करोड़ के ब्याज और जुर्माने के परिहार्य भुगतान के कारण हानि उठाना पड़ी। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2015 से जून 2017 की अवधि के लिए ₹0.67 करोड़ की बकाया राशि पर अतिरिक्त ब्याज और जुर्माने के लिए देनदारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

एनटीपीसी लिमिटेड

3.4 गैस रूपांतरण पर निरर्थक व्यय

एनटीपीसी लिमिटेड ने कायमकुलम में अपनी 'नाफ्था' आधारित राजीव गांधी कंबाइंड साइकिल विद्युत परियोजना को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस या पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस या नाफ्था का उपयोग ईंधन के रूप में करने के लिए बहु-ईंधन आधारित संयंत्र में परिवर्तित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹17.27 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

एनटीपीसी लिमिटेड की राजीव गांधी संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना केरल राज्य के कायमकुलम में स्थित एक नाफ्था आधारित गैस/भाप आधारित पावर स्टेशन (स्टेशन) है।

स्टेशन को मार्च 2000 में 359.58 मेगावाट⁹ की स्थापित क्षमता के साथ चालू किया गया था। इस स्टेशन द्वारा उत्पादित संपूर्ण विद्युत की आपूर्ति केरल राज्य विद्युत बोर्ड और एनटीपीसी के बीच किए गए विद्युत क्रय करार (जनवरी 1995) के अनुसार केरल राज्य विद्युत बोर्ड को की जाती है। विद्युत क्रय करार की प्रारंभिक अवधि वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्ष थी और इसे समय-समय पर आगे बढ़ाया गया था। नाफथा, जो इस स्टेशन के लिए इनपुट ईंधन है, की उच्च लागत को देखते हुए केरल राज्य विद्युत बोर्ड स्टेशन¹⁰ से नियमित रूप से विद्युत प्राप्त नहीं कर रहा था। स्टेशन से विद्युत का उपयोग किए बिना, स्टेशन की उपलब्धता हमेशा बनी रहती थी और परिणामस्वरूप, केरल राज्य विद्युत बोर्ड से नियत प्रभारों के माध्यम से राजस्व प्राप्त किया जा रहा था।

एनटीपीसी और केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने 1 मार्च 2013 से प्रभावी 12 वर्षों (स्टेशन के शेष जीवन) के लिए एक पूरक विद्युत खरीद समझौता (फरवरी 2013) किया। अनुपूरक विद्युत क्रय करार में इस बात पर पारस्परिक सहमति थी कि एनटीपीसी मौजूदा नाफथा ईंधन फायरिंग मोड को बहु-ईंधन फायरिंग मोड (नाफथा/पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस/प्राकृतिक गैस का उपयोग करके) में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ सकती है, जिसके लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड की सहमति प्राप्त की जानी थी। प्रस्तावित परिवर्तन की कार्यान्वयन लागत को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के मानदंडों के अनुसार बढ़े हुए टैरिफ के माध्यम से पूंजीकृत और वसूल किया जाना था।

स्टेशन को वैकल्पिक ईंधन (पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस/प्राकृतिक गैस) की आपूर्ति के लिए एनटीपीसी को केरल राज्य विद्युत बोर्ड की सहमति से गैस आपूर्ति करार/गैस परिवहन करार करना अपेक्षित था। स्टेशन के प्रौद्योगिकी रूपांतरण के लिए अनुमोदन मांगते हुए अपने निदेशक मंडल को प्रस्तुत प्रस्ताव (मार्च 2013) में एनटीपीसी ने उल्लेख किया है कि प्रस्तावित रूपांतरण के कमीशनिंग शेड्यूल से मेल खाने के लिए गैस आपूर्ति समझौते/गैस परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर सुनिश्चित किए जाएंगे। यह देखा गया कि

⁹ 116.6 मेगावाट प्रत्येक की दो गैस टरबाइन और 126.38 मेगावाट की एक भाप टरबाइन। गैस टरबाइन नाफथा द्वारा चलाए जाते हैं और गैस टरबाइन द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट गर्मी का उपयोग स्टीम के उत्पादन के लिए किया जाता है जो कि स्टीम टरबाइन में प्रयोग होती है। स्टीम टरबाइन द्वारा उपयोग के लिए अवशिष्ट गर्मी का उपयोग करने की इस प्रक्रिया को संयुक्त चक्र कहा जाता है।

¹⁰ 85 प्रतिशत के मानकीय प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) की तुलना में, वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए संयंत्र का वास्तविक पीएलएफ क्रमशः 22.37 प्रतिशत, 49.16 प्रतिशत और 30.74 प्रतिशत था।

स्टेशन को गैस आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए, कंपनी ने गेल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ विभिन्न विकल्पों¹¹ पर चर्चा की, लेकिन कोई भी विकल्प निर्धारित नहीं हुआ।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने स्टेशन के प्रौद्योगिकी रूपांतरण के लिए सहमति प्रदान करते हुए (जुलाई 2013) एनटीपीसी को सूचित किया कि उसे गैस की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना अतिरिक्त पूंजीगत व्यय वहन करने में आशंका थी। केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने एनटीपीसी से अनुरोध किया कि वह स्थल पर गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसकी सहमति से गैस आपूर्ति समझौते/गैस परिवहन समझौते को अंतिम रूप दे और यह भी स्पष्ट किया कि स्टेशन द्वारा अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के बाद रूपांतरण के कारण निर्धारित शुल्क में वृद्धि को वहन किया जाएगा।

तथापि, एनटीपीसी ने गैस आपूर्ति करार/गैस परिवहन करार को अंतिम रूप दिए बिना स्टेशन के परिवर्तन के लिए (सितम्बर, 2013) आदेश दिए, यद्यपि उसे इस बात की जानकारी थी कि स्टेशन पर गैस की उपलब्धता के बिना स्टेशन चालू नहीं किया जाएगा। ₹32.27 करोड़ के व्यय से काम (मार्च 2016)¹² पूरा किया गया था, लेकिन गैस की अनुपलब्धता के कारण इसे (मार्च 2022) चालू नहीं किया गया था।

कन्वर्जन पूरा होने तक एनटीपीसी ने वर्ष 2014-19 के लिए बहु-वर्षीय टैरिफ के निर्धारण के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दायर याचिका में संयंत्र की प्रस्तावित रूपांतरण लागत (₹30 करोड़) का दावा (अगस्त 2014) किया। तथापि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने गैस आपूर्ति करार/गैस परिवहन करार के अभाव, भूमिगत/उप-समुद्री पाइपलाइन बिछाने के लिए केरल सरकार की अनुमति की कमी और इसमें शामिल अनेक अनिश्चितताओं के आधार पर (अक्टूबर, 2016) इसकी अनुमति नहीं दी।

इससे व्यथित होकर एनटीपीसी ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील (अपील संख्या 40/2017) दायर की। अपने आदेश (5 अगस्त 2019) में, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने नोट किया कि दोनों पक्षों ने ईंधन फायरिंग प्रणाली को बढ़ाने के लिए संयुक्त निर्णय लिया और गैस आपूर्ति समझौते/गैस परिवहन समझौते के निष्पादन सहित

¹¹ नौकाओं/अंतर्देशीय जलमार्गों और फ्लोटिंग स्टोरेज री-गैसीकरण यूनिट के माध्यम से उप-समुद्री पाइपलाइन बिछाना, भूमिगत पाइपलाइन बिछाना।

¹² पूरा होने की निर्धारित तिथि जनवरी 2015 थी।

जोखिम शमन के लिए सभी संभावित साधनों का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन कोई भी पक्ष अब जिम्मेदारियों और परिणामों से मुक्त नहीं हो सकता। विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि गैस आपूर्ति समझौते/गैस परिवहन समझौते को अंतिम रूप देने/निष्पादित किए जाने तक एनटीपीसी इस मामले में उचित विवेक का उपयोग किए बिना बहु-ईंधन फायरिंग प्रणाली की स्थापना के लिए आगे बढ़ा। विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने राय दी कि ऐसी अजीबोगरीब स्थिति में जब प्रणाली को दावा किए गए व्यय के साथ लागू किया गया है, लेकिन बदले में, लाभार्थी/केरल राज्य विद्युत बोर्ड को कोई लाभ नहीं हुआ है, तो इस तरह के व्यय का बोझ दोनों पक्षों द्वारा 50:50 के अनुपात में समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। चूंकि विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में कानून का पर्याप्त प्रश्न शामिल नहीं था, इसलिए एनटीपीसी ने भारत के उच्चतम न्यायालय में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती नहीं दी। चूंकि अपीलीय न्यायाधिकरण का यह आदेश अगस्त 2019 में सुनाया गया था, एनटीपीसी ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के समक्ष (जनवरी 2020) एक याचिका दायर की, जिसमें विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित की गई रूपांतरण लागत का 50 प्रतिशत (₹15 करोड़) 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए टैरिफ में वसूल करने की अनुमति मांगी गई थी क्योंकि इसे 2014-19 की अवधि के दौरान वसूल नहीं किया जा सका जैसा कि सीईआरसी के समक्ष शुरू में दावा किया गया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनटीपीसी ने स्टेशन के रूपांतरण का कार्य शुरू करने और केरल राज्य विद्युत बोर्ड की आशंकाओं को दूर करने से पहले रूपांतरण शेड्यूल की कमीशनिंग से मेल खाने के लिए किसी भी गैस आपूर्ति समझौते/गैस परिवहन समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया। इसने अपने बोर्ड को दिए गए इस कथन की भी अनदेखी की कि प्रस्तावित रूपांतरण के कमीशनिंग शेड्यूल से मेल खाने के लिए गैस आपूर्ति समझौते/गैस परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के आधार पर टैरिफ के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर करके, यह स्पष्ट है कि कंपनी ने गैस आपूर्ति समझौते/गैस परिवहन समझौते को सुनिश्चित किए बिना परियोजना के साथ आगे बढ़ने की अपनी चूक को स्वीकार किया था। इस अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप, ₹32.27 करोड़ का पूरा व्यय बेकार हो गया है क्योंकि संयंत्र अभी भी नापथा पर चल रहा है और बहु-ईंधन सुविधा का उपयोग करने में असमर्थ है। इसमें से एनटीपीसी द्वारा याचिका आदेश में ₹15 करोड़

की राशि का दावा किया गया है और कंपनी ने ₹17.27 करोड़ (₹32.27 करोड़ कम ₹15 करोड़) का निष्फल व्यय किया है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि इस अवधि के दौरान कंपनी 7.67 प्रतिशत से 8.07 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से धन उधार ले रही थी। अप्रैल 2016 से मार्च 2021 की अवधि के लिए ₹32.27 करोड़ की राशि पर ब्याज लागत ₹11.29 करोड़¹³ बैठती है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के इस उत्तर का समर्थन किया (सितंबर 2021) कि एनटीपीसी ने 4 जुलाई 2013 के अपने पत्र के माध्यम से केरल राज्य विद्युत बोर्ड की सहमति प्राप्त करने के बाद प्रौद्योगिकी रूपांतरण के लिए आगे बढ़ा था। व्यय का बंटवारा विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक विशिष्ट कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश के अनुपालन में किया गया है। एनटीपीसी ने अपनी व्यावसायिक आवश्यकता के अनुरूप वैध व्यय किया, लेकिन केरल राज्य विद्युत बोर्ड के पीछे हटने के कारण यह सफल साबित नहीं हुआ। यह एनटीपीसी द्वारा अपने कायमकुलम संयंत्र के लिए समाधान खोजने के लिए किया गया सामान्य व्यावसायिक व्यय था और इसे निष्फल व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता है।

यह उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि प्रबंधन द्वारा उपर्युक्त उत्तर में उद्धृत 4 जुलाई, 2013 के पत्र में केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने भी गैस उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना अतिरिक्त पूंजीगत व्यय वहन करने में अपनी आशंका व्यक्त की थी और एनटीपीसी से स्थल पर गैस उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसकी सहमति से गैस आपूर्ति करार/गैस परिवहन करार को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया था। केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया था कि स्टेशन के वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के बाद वह रूपांतरण के कारण निर्धारित शुल्क में वृद्धि को वहन करेगा। इसके अलावा, पूंजीगत व्यय का 50 प्रतिशत केवल एनटीपीसी द्वारा टैरिफ के माध्यम से दावा किया जा सकता है और शेष व्यय उसी द्वारा वहन किया जाना है। इसके अलावा, चूंकि संयंत्र का बचा हुआ जीवन काल चार वर्ष से भी कम है, गैस की उपलब्धता के लिए बहुत कम संभावना है, इसलिए एनटीपीसी द्वारा वसूली नहीं किए जा सकने वाले व्यय को केवल निष्फल व्यय के बराबर माना जाता है।

¹³ ब्याज की गणना अप्रैल 2016 से सात प्रतिशत पर की गई क्योंकि कंवर्जन का काम मार्च 2016 में पूरा हुआ था।

इस प्रकार, एनटीपीसी ने गैस की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना अपने पावर स्टेशन को एकल ईंधन (नाफ्था) फायरिंग मोड से बहु-ईंधन फायरिंग मोड (नाफ्था/प्राकृतिक गैस/पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस) में परिवर्तित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप रूपांतरण कार्य पूरा होने के पांच वर्ष बाद भी स्टेशन गैस से परिचालित नहीं हो सका। इसके परिणामस्वरूप ₹17.27 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ और उधार ली गई धनराशि पर ब्याज के रूप में ₹11.29 करोड़ की हानि हुई।

उद्योग क्लस्टर

अध्याय IV: वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग)

जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

4.1 'स्टॉप लॉस' की सीमा का पालन न करने के कारण निवेश का मूल्यहास

इक्विटी निवेशों की अपर्याप्त निगरानी और निर्धारित स्टॉप लॉस सीमाओं के अनुसार स्ट्रिप की गैर-बिक्री के कारण निवेश में मूल्यहास हुआ।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) (निवेश) विनियम, 2000, 2013 तक बाद के संशोधनों और आईआरडीएआई (निवेश) विनियमन 2016 के साथ सामान्य बीमा कंपनियों के निवेश पोर्टफोलियो के पैटर्न को विनियमित करता है। आईआरडीएआई निवेश विनियमों में यह निर्धारित किया गया है कि, प्रत्येक बीमाकर्ता बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक निवेश नीति तैयार करेगा और तरलता, विवेकपूर्ण मानदंडों, एक्सपोजर सीमाओं, स्टॉप लॉस सीमाओं और सभी निवेश जोखिमों के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

भारतीय साधारण बीमा निगम (कंपनी) ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक निवेश नीतियाँ तैयार की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्टॉप लॉस सीमाएं शामिल हैं। स्टॉप लॉस सीमा निर्धारित करने का तर्क इक्विटी पोर्टफोलियो की निरंतर आधार पर निगरानी करके पूंजी की हानि को कम से कम करना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी निवेश से बाहर निकलने हेतु निर्णय लेने के लिए अंतिम दिन तक इंतजार न करे। 31 मार्च 2022 तक कंपनी के निवेश का कुल मूल्य (बही मूल्य) ₹77,348.78 करोड़ था, जिसमें से इक्विटी निवेश का बही मूल्य ₹14,123.09 करोड़ (18 प्रतिशत) था।

वार्षिक निवेश नीतियों में तालिका 4.1 में दर्शाए गए अनुसार स्टॉप लॉस सीमाओं से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं

तालिका 4.1: वार्षिक निवेश नीतियों में प्रावधान

वर्ष	स्टॉप लॉस सीमा के संबंध में प्रावधान
2014-15 और 2015-16	इक्विटी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के प्रत्येक स्ट्रिप में 20 फीसदी स्टॉप लॉस और उसकी विशिष्ट समीक्षा और स्टॉप लॉस विकल्प का इस्तेमाल नहीं करने पर सक्रिय निर्णय दर्ज किए जाने का कारण बताते हैं।

वर्ष	स्टॉप लॉस सीमा के संबंध में प्रावधान
2016-17 और 2017-18	वर्ष के दौरान सभी नई खरीदारी के लिए पहला स्टॉप लॉस ट्रिगर 20 फीसदी और दूसरा स्टॉप लॉस ट्रिगर पिछले दिन के अंतिम मूल्य से 30 फीसदी पर होगा। खरीद की चौथी तिमाही के बाद भी स्टॉक की कीमत में सुधार नहीं दिखने पर बिक्री नोट तैयार किया जाएगा।
2018-19 के बाद	इक्विटी शेयर के लिए समीक्षा प्रक्रिया में दो समीक्षा ट्रिगर निर्धारित किए गए हैं अर्थात सभी नई खरीद के लिए औसत खरीद मूल्य में 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की गिरावट और पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद कंपनियों के लिए औसत बही मूल्य का 20 प्रतिशत। इसके अलावा, ट्रिगर की स्थिति में तिमाही में एक बार समीक्षा नोट तैयार करना।

लेखापरीक्षा ने कंपनी द्वारा स्टॉप लॉस सीमाओं के अनुपालन की जांच की और पाया:

i. अप्रैल 2019 तक इक्विटी पोर्टफोलियो की त्रैमासिक समीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे और इस संबंध में कंपनी ने स्पष्ट किया (फरवरी 2022) कि अप्रैल 2019 से पहले समीक्षा का कोई औपचारिक नोट नहीं था। यह निवेश नीतियों का उल्लंघन था, जो स्पष्ट रूप से स्टॉप लॉस विकल्प/बिक्री नोट/समीक्षा नोट का उपयोग नहीं करने का कारण बताते हुए सक्रिय निर्णय जैसे प्रलेखन प्रदान करता है। ऐसे कई उदाहरण थे जब स्टॉप लॉस विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था और इस संबंध में स्थिति पर नीचे बिंदु iii के तहत चर्चा की गई है।

ii. जुलाई 2019 से अक्टूबर 2021 तक इक्विटी पोर्टफोलियो की त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट (10 रिपोर्ट) से संकेत मिलता है कि समीक्षा में वर्ष के दौरान की गई इक्विटी के साथ-साथ पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद कंपनियों की ताजा खरीद को शामिल किया गया है। पहले से मौजूद इक्विटी को दो प्रकारों में विभाजित किया गया था जैसे, पहला, उन कंपनियों के स्ट्रिप जिनके शेयर का मूल्य औसत बही मूल्य के 20 प्रतिशत से नीचे गिर गया है और, दूसरा, जिन कंपनियों के शेयर की कीमत ₹1 प्रति शेयर थी। हालांकि तिमाही समीक्षाओं में पहले प्रकार (औसत बही मूल्य के 20 प्रतिशत तक की गिरावट) से दूसरे प्रकार (बही मूल्य ₹1 तक गिर गई) तक शेयर की चाल के विश्लेषण का संकेत नहीं दिया गया था। यह प्रासंगिक है क्योंकि कंपनी ने 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान ₹687.24 करोड़¹ की कुल राशि हासिल मूल्य है (शेयर मूल्य कम हो गया था लेकिन ₹1 से

¹ 2014-15: ₹58.81 करोड़; 2015-16: ₹135.28 करोड़; 2016-17: ₹55.64 करोड़; 2017-18: ₹20.32 करोड़; 2018-19: ₹160.35 करोड़; 2019-20: ₹222.82 करोड़ और 2020-21: ₹34.02 करोड़।

ऊपर था) और बट्टे खाते में डाल दिया है (शेयर मूल्य ₹1 तक आ गया), जिसने संबंधित वर्षों में लाभप्रदता को उस हद तक कम कर दिया है।

iii. तिमाही समीक्षा नोटों के अनुसार, ताजा खरीद में स्टॉप लॉस ट्रिगर को सक्रिय नहीं किया, जबकि पहले से मौजूद इक्विटी पोर्टफोलियो में गिरावट देखी गई है। जुलाई 2019 से अक्टूबर 2021 की अवधि के लिए त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्टों से संक्षेप में कंपनी द्वारा मूल्यहास स्क्रिप (पूर्ण और आंशिक निकास दोनों) की बिक्री के बारे में विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2: मूल्यहास स्क्रिप की बिक्री की त्रैमासिक समीक्षा

(₹ करोड़ में)

त्रैमासिक समीक्षा तिथि	जिन कंपनियों के शेयर की कीमत औसत बुक कीमत के 20 फीसदी से नीचे आ गई है अर्थात स्टॉप लॉस सीमा ट्रिगर की गई थी।					जिन कंपनियों के शेयर की कीमत ₹1 प्रति शेयर थी			
	कंपनियों की संख्या	औसत बुक मूल्य	बाजार मूल्य	जिन कंपनियों में स्क्रिप बेचे गए		कंपनियों की संख्या	बाजार मूल्य	जिन कंपनियों में स्क्रिप बेचे गए	
				कंपनियों की संख्या	निकास का प्रतिशत			कंपनियों की संख्या [#]	निकास का प्रतिशत
22.07.2019	78	743.61	138.50	5*	6	187	75.47	9	5
14.10.2019	87	811.93	166.29	20	23	187	75.47	10	5
23.01.2020	93	965.51	153.50	17	18	186	58.75	11	6
22.04.2020	98	950.31	128.62	13	13	186	41.48	11	6
24.07.2020	80	760.73	172.78	--	--	193	48.23	18	9
16.10.2020	75	740.68	182.67	38	51	190	55.43	22	12
11.01.2021	82	638.57	146.58	31	38	183	75.95	28	15
21.04.2021	81	647.22	161.56	37	46	172	73.66	10	6
12.07.2021	51	512.57	153.32	33	65	190	70.14	4	2
07.10.2021	49	512.73	163.71	13	27	189	52.47	6	3

*: पिछले तीन वर्षों के दौरान निकासी

#: जुलाई 2019 से जनवरी 2021 तक पिछले तीन वर्षों/कुछ वर्षों के दौरान निकासी हुई। अप्रैल 2021, जुलाई 2021 और अक्टूबर 2021 में निकासी वर्ष के दौरान हुई थी।

उपर्युक्त तालिका से यह पाया जा सकता है कि दो तिमाहियों को छोड़कर, शेयर की बिक्री पहले प्रकार के तहत 50 प्रतिशत से कम थी (शेयर कीमत औसत बही मूल्य के 20 प्रतिशत से नीचे गिरता है) और केवल दूसरे प्रकार के तहत 3 से 15 प्रतिशत (शेयर कीमत ₹1 तक कम हो गया)। इससे संकेत मिलता है कि स्टॉप लॉस सीमा शुरू होने के बावजूद कंपनी ज्यादातर स्क्रिप से बाहर नहीं निकली। तिमाही समीक्षा रिपोर्ट में स्क्रिप से बाहर

निकलने/बेचने में असमर्थता के लिए उद्धृत कारण यह था कि आज की तिथि में स्क्रिप में कम कारोबार और कम तरल था, क्योंकि बाजार कीमत औसत बही मूल्य की तुलना में बहुत कम था। हालांकि, शेयर का 'कम कारोबार' कैसे किया गया, यह बताने के लिए बाजार डेटा का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था, हालांकि सेबी ने 'कम कारोबार' वाली प्रतिभूतियों² के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

iv. कंपनी के इक्विटी पोर्टफोलियो में ₹4,541.89 करोड़ के बही मूल्य के साथ 123 स्क्रिप थे, जो 31 मार्च 2020 तक घटकर ₹1,701.28 करोड़ (20 प्रतिशत से 99.87 प्रतिशत तक मूल्यहास) हो गए। 31 मार्च 2020 तक 123 स्क्रिप में से ₹216.28 करोड़ के बही मूल्य वाले 20 स्क्रिप की कीमत बही मूल्य के 90 फीसदी से अधिक की गिरावट आई थी। लेखापरीक्षा ने 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए कंपनी और स्टॉक बाजार (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज/नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) डेटा द्वारा निर्धारित स्टॉप लॉस मापदंडों के संबंध में इन 20 स्क्रिप³ (तीन स्क्रिप सहित जहां शेयर की कीमत ₹1/ नाममात्र राशि के मूल्य पर निर्धारित की गई थी) का विश्लेषण किया, यह जांचने के लिए कि क्या कंपनी के लिए अत्यधिक मूल्यहास वाले स्क्रिप की बिक्री संभव थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन स्क्रिप का स्टॉक एक्सचेंजों पर कम कारोबार नहीं हुआ और यदि कम्पनी ने इन स्क्रिपों को औसत मूल्य से कम, यहाँ तक कि बाजार मूल्य पर भी बेचा होता तो, कंपनी वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹134.89 करोड़, ₹66.22 करोड़, ₹28.03 करोड़, ₹8.49 करोड़ और ₹9.19 करोड़ की न्यूनतम अनुमानित राशि अर्जित कर सकती थी (अनुलग्नक II)।

मूल्यहास स्क्रिप की गैर-बिक्री के परिणामस्वरूप पूंजी/ब्याज की और हानि हुई है। इसके अलावा, यदि स्टॉप लॉस/समीक्षा मापदंड के अनुसार कंपनी द्वारा बाहर निकलने का अवसर प्राप्त किया गया होता, तो हानि को कम किया जा सकता था और वसूली गई राशि का अन्य लाभदायक इक्विटी में निवेश किया जा सकता था।

² प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए सेबी के दिशानिर्देश (18 सितंबर 2000 और 28 मार्च 2001) कम कारोबार वाली इक्विटी को परिभाषित करते हैं क्योंकि "जब एक महीने में इक्विटी और /या इक्विटी से संबंधित प्रतिभूति में ट्रेडिंग ₹5 लाख से कम होती है और कुल मात्रा 50,000 शेयरों से कम होती है, तो प्रतिभूति को कम कारोबार वाली प्रतिभूति माना जाएगा और तदनुसार मूल्य निर्धारित होगा। यह निर्धारित करने के लिए कि किसी प्रतिभूति का कम कारोबार होता है या नहीं, भारत में सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार की जाने वाली मात्रा को ध्यान में रखा जा सकता है।

³ ₹216.28 करोड़ की बही मूल्य के साथ 31 मार्च 2020 को घटकर ₹9.70 करोड़ हो गया।

प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2021) कि ये स्ट्रिप पिछले कई दशकों से खरीदे गए हैं और बाहर निकलने का मौका दिए बिना बहुत कम कीमत/कम मात्रा में व्यापार किए गए थे प्रबंधन ने आगे कहा कि कंपनी के पास अपने सभी निवेश निर्णयों के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण है और यह भी कहा कि मार्च 2020 में कोविड महामारी के कारण बाजार में गिरावट के बाद, स्टॉक बाजारों में उछाल आया है और कंपनी लाभप्रदता के साथ 2020-21 में 24 स्ट्रिप से बाहर निकलने में सक्षम थी।

प्रबंधन के उत्तर को निम्नलिखित के विरुद्ध देखा जाना है:

- कंपनी द्वारा बिक्री के अवसर का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया था, हालांकि इन मामलों में स्टॉप लॉस मानदंडों को ट्रिगर किया गया था और स्ट्रिप बाजारों पर भी पर्याप्त रूप से स्टॉक बाजारों में कारोबार किया गया था, जैसा कि **अनुलग्नक II** के विश्लेषण में पता चला है। 2019-20 में स्टॉक बाजार में गिरावट के बावजूद, कंपनी को वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमशः ₹8.49 करोड़ और ₹9.19 करोड़ की प्राप्ति हो सकती थी।

- लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए 20 स्ट्रिप, कंपनी द्वारा 2020-21 में किए गए 24 निकास का हिस्सा नहीं थे। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि 24 निकासी लाभ पर की गई थी, इन शेयर का औसत बही मूल्य पहले से ही पिछले वर्षों में शेयर को बढ़े खाते में डालकर नाममात्र राशि/ ₹1 तक कम कर दिया गया था, जिससे उन वर्षों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इसलिए इस तरह की बिक्री के लिए लाभप्रदता पर विचार करना बेकार है।

- इस उत्तर के संबंध में कि कंपनी का निवेश के निर्णयों का दीर्घकालिक दृष्टिकोण था, इस तरह के दीर्घकालिक दृष्टिकोण इक्विटी पोर्टफोलियो की नियमित निगरानी को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं ताकि उचित समय पर वसूली/वृद्धि की कोई संभावना न हो।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा निर्धारित स्टॉप लॉस और समीक्षा प्रक्रिया के अनुसार ₹216.28 करोड़ के अत्यधिक मूल्यहास वाले इक्विटी पोर्टफोलियो को बेचने के लिए प्रबंधन द्वारा विवेकपूर्ण और समय पर कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप धन अवरुद्ध हो गया है, बही मूल्य में और गिरावट आई है और वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान न्यूनतम क्रमशः ₹134.89 करोड़, ₹66.22 करोड़, ₹28.03 करोड़, ₹8.49 करोड़ और ₹9.19 करोड़, कमाने का अवसर खो दिया है।

इस मामले की सूचना मार्च 2022 में मंत्रालय को दी गई थी; उनके उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2022)।

सिफारिश संख्या 8: कंपनी की निवेश नीति में दिए गए स्टॉप लॉस मापदंडों के अनुसार, कंपनी मूल्यहास को रोकने और पूंजी बढ़ाना/वृद्धि और तरलता सुनिश्चित करने के लिए इक्विटी पोर्टफोलियो की विस्तृत समीक्षा/विश्लेषण कर सकती है, जिसमें स्क्रिप पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है, जहां मूल्यहास 20 प्रतिशत से अधिक है और अन्य स्क्रिप भी भविष्य में, जब भी मूल्यहास औसत बही मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाता है।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

4.2 माल और सेवा कर के प्रति इनपुट टैक्स क्रेडिट की हानि

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-1 ने इनपुट सेवा बीजकों को माल और सेवा कर (जीएसटी) पोर्टल के साथ नहीं मिलाया। परिणामस्वरूप, यह पात्र जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सका और 2017-18 से 2020-21 के दौरान ₹97.44 करोड़ की हानि हुई।

केंद्रीय माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 (अधिनियम) की धारा 16 (1) के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं और अधिनियम की धारा 49 में निर्दिष्ट तरीके से, माल या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जो अपने व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ने में उपयोग किए जाते हैं या उपयोग किए जाने का इरादा रखते हैं और उक्त राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर⁴ में जमा की जाएगी। इस क्रेडिट का उपयोग अधिनियम की धारा 49 (4) में निर्दिष्ट जीएसटी देयता के लिए भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 16 (4) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए किसी भी बीजक या डेबिट नोट के संबंध में वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितंबर महीने के लिए धारा 39 के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि या वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार नहीं होगा।

⁴ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर प्रत्येक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति के लिए सामान्य जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर है।

अधिनियम के तहत निर्धारित निम्नलिखित तीन रिटर्न इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के संदर्भ में प्रासंगिक हैं जैसा कि तालिका 4.3 में विस्तृत है।

तालिका 4.3: इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए रिटर्न के प्रकार

रिटर्न का नाम	रिटर्न का विवरण
फॉर्म जीएसटीआर-1	एक महीने के दौरान सभी जावक आपूर्ति (बिक्री) का बीजक-वार विवरण शामिल होता है।
फॉर्म जीएसटीआर-2ए	<ul style="list-style-type: none"> एक महीने के दौरान सभी आवक आपूर्ति (खरीद) का बीजक-वार विवरण शामिल होता है। यह फॉर्म आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल फॉर्म जीएसटीआर-1 के आधार पर जीएसटी पोर्टल पर ऑटो-पॉपुलेटेड हो जाता है। यह फॉर्म बिक्री/सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्ट जीएसटी संख्या के प्रति तैयार होता है।
फॉर्म जीएसटीआर-3बी	जावक आपूर्ति, आवक आपूर्ति (आउटपुट सेवाएं तैयार करने के लिए प्राप्त खरीद या सेवाएं), पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट (आवक आपूर्ति पर भुगतान किया गया जीएसटी) और इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाकर कुल जीएसटी की शुद्ध देयता का मासिक विवरण शामिल होता है।

उपर्युक्त रिटर्न के विवरण से यह स्पष्ट अनिवार्य है कि जब कोई करयोग्य व्यक्ति जीएसटी देयता के भुगतान के लिए और इनपुट सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3 बी दाखिल करता है, तो फॉर्म जीएसटीआर-3 बी में प्राप्त क्रेडिट को फॉर्म जीएसटीआर-2 ए में दिखाए गए क्रेडिट के साथ मिलान किया जाना चाहिए जो प्राप्तकर्ता द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त सेवाओं पर उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट को दर्शाता है।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) का दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-1 जीएसटी के भुगतान, लागू जीएसटी रिटर्न दाखिल करने, अन्य जीएसटी अनुपालन के साथ-साथ दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-III, जो स्वयं मोटर टाई-अप व्यवसाय (हीरो मोटर्स के लिए अखिल भारतीय टाई-अप व्यवसाय सहित) के लिए एक नोडल कार्यालय है, सहित दिल्ली में परिचालन करने वाले कंपनी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के उद्देश्य से नामित नोडल कार्यालय है।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी का दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-1 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले चार वर्षों के लिए ₹97.44 करोड़ के पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सका (अनुलग्नक III)। 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय

कार्यालय द्वारा दाखिल प्रासंगिक रिकॉर्ड और रिटर्न के साथ-साथ लेखांकन व आईटी प्रणालियों की लेखापरीक्षा जांच से इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपरोक्त हानि के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित कमियों और खामियों का खुलासा हुआ:

i. दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-I के संबंध में, मोटर दावों के नकदरहित निपटान से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (नामत: इंटरप्राइज आर्किटेक्चर सोल्यूशन फॉर इंश्योरेंस) में दावा मॉड्यूल की समीक्षा से पता चला कि इसमें बीजक विवरण जैसे बीजक संख्या, जीएसटी संख्या, जीएसटी राशि और सेवा के आधार मूल्य का पृथक्करण आदि आवश्यक फील्ड्स का अभाव था। परिणामस्वरूप, प्राप्त की गई पूरी इनपुट सेवाओं को सेवा के आधार मूल्य और जीएसटी भाग में अलग किए बिना लेखाओं में बुक किया जा रहा था। इससे केन्द्रीय कार्यालय द्वारा दाखिल फॉर्म जीएसटीआर-3 बी में दावा किए गए और जीएसटी पोर्टल में परिलक्षित फॉर्म जीएसटीआर-2 ए में दिखाया गये इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच पर्याप्त अंतर को सुलझाने में बाधा आई। इस प्रकार, नकदरहित निपटान के तहत दावों के भुगतान पर भुगतान किए गए जीएसटी के प्रति पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुपलब्ध रहा।

ii. इसी तरह, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-III के संबंध में, मोटर सम्बद्ध कारोबार के लिए परिचलित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली अर्थात ऑनलाइन दावा मॉड्यूल पोर्टल की जांच से पता चला कि इसमें बीजक विवरण जैसे बीजक संख्या, जीएसटी संख्या, जीएसटी राशि और सेवा के आधार मूल्य का पृथक्करण आदि के लिए आवश्यक मर्दानों का अभाव है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य इनपुट सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है। हालांकि, फरवरी 2018 और अगस्त 2019 के बीच पोर्टल में आवश्यक सत्यापन शामिल⁵ किए गए थे। इस प्रकार, आवश्यक सत्यापनों को शामिल करने से पहले की अवधि के लिए दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-III द्वारा दावों के भुगतान पर भुगतान किए गए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुपलब्ध रहा।

iii. कंपनी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त इनपुट सेवाओं के बीजक-वार विवरण के साथ मासिक इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था, जिससे नोडल कार्यालय के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र बीजकों को अलग करने के लिए बाधा उत्पन्न हो गई थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए मासिक इनपुट

⁵ मोटर टाई-अप कारोबार के संबंध में, मारुति, होंडा और हीरो के विवरणों के आवश्यक सत्यापन क्रमशः 14 फरवरी 2018, 3 अक्टूबर 2018 और 1 अगस्त 2019 से शामिल किए गए थे।

टैक्स क्रेडिट रजिस्टर अगस्त 2019 में सूचना प्रौद्योगिकी विक्रेता द्वारा दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-1 को दिया गया था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3 बी के साथ मिलान के बाद मासिक इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर अगस्त/सितंबर 2020 में प्रस्तुत किया गया था। परिणामस्वरूप, जीएसटी पोर्टल पर परिलक्षित फॉर्म जीएसटीआर -2 ए के साथ बीजक-वार मिलान संभव नहीं था और फॉर्म जीएसटीआर-2 ए और फॉर्म जीएसटीआर-3 बी के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच वर्षों से अंतर रहा। हालांकि, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों ने वर्ष 2020-21 से मासिक इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर का रखरखाव शुरू कर दिया है।

इस प्रकार, कंपनी का दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-1 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान ₹97.44 करोड़ के पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सका।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2021) कि इस मामले को पहले ही उनके तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के साथ उठाया जा चुका है, जिन्होंने पुष्टि की थी कि नकदरहित मोटर दावों के संबंध में कार्यक्षमता विकास अग्रिम चरण में है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा और भविष्य में प्रासंगिक सुधारात्मक कार्रवाई का ध्यान रखने के लिए जीएसटी इनपुट क्रेडिट प्रबंधन नीति भी लागू की गई है। यह आश्वासन दिया गया कि कंपनी प्रणाली में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि भविष्य में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की हानि को कम किया जा सके।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2022) कि जीएसटी का अभिग्रहण करने और लाभ उठाने की कार्यक्षमता शुरुआती वर्षों में उपलब्ध नहीं थी, जिससे अधिक बेमेलता हुई। कंपनी की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां परिवर्तनकालीन दौर से गुजर रही थीं और पिछले कुछ वर्षों में ही स्थिति में सुधार हुआ है। जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच अंतर को और कम करने तथा चालू वर्ष में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

इस प्रकार, प्रणालीगत कमियों के कारण, नोडल कार्यालय के रूप में कंपनी का दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-1 जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म जीएसटीआर-2 ए में परिलक्षित वास्तविक उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट से कम लाभ उठा सका, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले चार वर्षों के दौरान ₹97.44 करोड़ की हानि हुई।

सिफारिश संख्या 9: कंपनी जीएसटी से संबंधित सभी डेटा दर्ज करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में आवश्यक कार्यक्षमता शुरू करने में तेजी लाए ताकि फॉर्म जीएसटीआर-3 बी में दावा किए गए और फॉर्म जीएसटीआर -2 ए में परिलक्षित इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच के अंतर को कम किया जा सके, जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और दी ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

4.3 मोटर बीमा प्रीमियम का कम प्रभार

मोटर बीमा पॉलिसी के जोखिम अंकन/जारी करते समय 'माल वाहक वाहनों' को 'विविध वाहन' के रूप में अनुचित वर्गीकरण के परिणामस्वरूप कम दरों पर मोटर बीमा प्रीमियम का संग्रह हुआ है, जिससे मोटर बीमा प्रीमियम में ₹14.05 करोड़ (दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ₹5.03 करोड़ और दी ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ₹9.02 करोड़) की कमी आई है।

मोटर वाहन अधिनियम⁶, 1988 में चोट, तृतीय पक्ष की मृत्यु या उनकी संपत्ति को हानि से संबंधित तृतीय पक्ष के जोखिमों के प्रति मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य बीमा का प्रावधान है। मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इश्योरेंस कवर पर लागू प्रीमियम की दरें आईआरडीएआई⁷ द्वारा वार्षिक अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित की गई थीं। तृतीय पक्ष बीमा के अलावा, मोटर वाहनों को 'स्वयं की हानि' के प्रति भी बीमा किया जाता है, जो वैकल्पिक है और तृतीय पक्ष कवर के साथ संयोजन के रूप में दिया जाता है। 'ओन डैमेज' के लिए कवरेज का मूल्य निर्धारण 2007 में टैरिफ-रहित किया गया था। धारा 4 के तहत भारत मोटर टैरिफ, वाहन के बीमित घोषित मूल्य (बीमित राशि), जोन⁸, वाहन की आयु और वाहन का सकल वजन/लाइसेंस प्राप्त वहन क्षमता के आधार पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए टैरिफ निर्धारित करता है। वाणिज्यिक वाहनों को माल ढोने वाले वाहनों (सार्वजनिक/निजी) (टाइप ए), ट्रेलरों (टाइप बी), यात्रियों को किराए या पारितोषिक पर ले

⁶ अध्याय 11 के तहत धारा 145 से 164।

⁷ भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) अधिनियम, 1999 की धारा 14 (2) (आई) के तहत निहित शक्ति के आधार पर।

⁸ जोन ए - चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, जोन बी- अन्य सभी राज्यों की राजधानियां और जोन सी- शेष भारत ।

जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन (टाइप सी), विविध और विशेष प्रकार के वाहनों (टाइप डी) और अन्य वाहनों में वर्गीकृत किया गया है।

लेखापरीक्षा में दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) और दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल) द्वारा मोटर बीमा प्रीमियम वसूले जाने की जांच की गई। एनआईएसीएल में, 2014-15 से 2019-20 तक छह साल की अवधि के लिए पांच क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत 10 परिचालन कार्यालयों द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की जांच की गई, जबकि ओआईसीएल के मामले में, तीन साल की अवधि (2016-17 से 2018-19) के लिए वाहन डेटाबेस⁹ के साथ बीमित वाहनों के विवरण की समग्रता में प्रतिपरीक्षण करके कंपनी के लिए डेटा विश्लेषण किया गया।

लेखापरीक्षा में दोनों कंपनियों द्वारा मोटर बीमा प्रीमियम वसूलने में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

4.3.1 एनआईएसीएल

मोटर तृतीय पक्ष प्रीमियम दरें प्रति वर्ष 1 अप्रैल से विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रभावी थीं, जिसमें सार्वजनिक और निजी माल वाहक वाहन (टाइप 'ए') अन्य श्रेणियों के तहत वर्गीकृत की तुलना में अधिक प्रीमियम होता है। 10 परिचालन कार्यालयों में 42,333 मोटर बीमा पॉलिसियों (टाइप 'डी') में से 4,863 पॉलिसियों (11.48 प्रतिशत) का चयन लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,433 पॉलिसियों में जहां टाइप 'डी' वाहनों पर लागू बीमा प्रीमियम लिया गया था; इन वाहनों से संबंधित वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) में माल वाहक वाहन के रूप में पंजीकृत किया गया था। चूंकि टाइप 'ए' वाहनों का प्रीमियम टाइप 'डी' वाहनों के लिए प्रीमियम से अधिक था, इसलिए एनआईएसीएल द्वारा जोखिम अंकन के समय वाहनों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप तृतीय पक्ष प्रीमियम में ₹2.96 करोड़ और स्वयं की हानि के प्रीमियम में ₹2.07 करोड़ की कमी आई है। परिचालन कार्यालय-वार ब्यौरा तालिका 4.4 में दिया गया है।

⁹ 'वाहन' एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वाहन पंजीकरण के स्वचालन और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहनों के राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है।

तालिका 4.4: प्रीमियम के कम प्रभार का विवरण

क्षेत्रीय कार्यालय	डिवीजनल कार्यालय (डीओ)/शाखा कार्यालय (बीओ)/क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ)	टाईप 'डी' मोटर पॉलिसियों की कुल संख्या	नमूना जांच की गई पॉलिसियों की संख्या (प्रतिशत)	उन पॉलिसियों की संख्या जहां कम प्रभार पाया गया था*	प्रीमियम का कम प्रभार (₹ करोड़ में)		
					स्वयं की हानि	तृतीय पक्ष	कुल
मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय-II	बांद्रा डीओ	1,227	613 (50)	101	0.14	0.30	0.44
	साकीनाका डीओ	925	462(50)	26	0.044	0.078	0.12
	बोरीवली डीओ	562	281(50)	46	0.064	0.15	0.21
	विले पार्ले बीओ	206	105(51)	53	0.06	0.17	0.23
दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-II	मेरठ डीओ-II	673	109(16)	109	0.057	0.26	0.32
दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-I	बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग डीओ	52	15(29)	10	0	0.0012	0.0012
	कनॉट हाउस डीओ	380	113(30)	113	0.012	0.22	0.23
	दिल्ली बीओ	465	393(85)	393	0.74	1.21	1.95
अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय	मेहसाणा डीओ	1,035	497(48)	163	0.045	0.28	0.33
चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय	चेन्नई आरओ	36,808	2,275(06)	419	0.91	0.29	1.20
कुल		42333	4863 (11.48)	1433	2.07	2.96	5.03

* जहां भी आरसी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी, वहां वाहन विवरणों की वाहन डेटा के साथ प्रति-जांच की गई थी।

भारतीय मोटर टैरिफ की धारा 5 और 6 के अनुसार, बीमा कंपनियों को पॉलिसी जारी करने से पहले 'प्रस्ताव फॉर्म' के भाग के रूप में वाहन के शीर्षक का प्रमाण एकत्र करना आवश्यक था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनआईएसीएल ने दलाल के पेशकश के आधार पर मोटर बीमा पॉलिसियों को जारी/नवीनीकृत किया। हालांकि कुछ मामलों में आरसी एकत्र की गई थी, लेकिन जोखिम अंकन पूरी तरह से दलाल के पेशकश के आधार पर की गई थी। इस प्रकार, जोखिम अंकन के दौरान उचित कर्मठता की कमी के परिणामस्वरूप मोटर बीमा प्रीमियम में ₹5.03 करोड़ की कमी आई है।

एनआईएसीएल ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में छह परिचालन कार्यालयों¹⁰ में ₹2.96 करोड़ के मोटर प्रीमियम के कम प्रभार को स्वीकार किया और ₹43.20 लाख की वसूली की

¹⁰ बोरीवली डी.ओ., विले पार्ले बी.ओ., मुंबई लाइफ बिल्डिंग डी.ओ., कनॉट हाउस डी.ओ., दिल्ली बी.ओ. मेहसाणा डी.ओ.

सूचना दी। अन्य चार परिचालन कार्यालयों¹¹ के संबंध में, एनआईएसीएल ने बताया कि आरसी की प्रति स्पष्ट नहीं थी/उपलब्ध नहीं थी और इसलिए वे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों को सत्यापित करने में सक्षम नहीं थे।

चार परिचालन कार्यालयों द्वारा सत्यापन न किए जाने के कारण के रूप में मोटर वाहनों की आरसी प्रतियों की अनुपस्थिति का हवाला देना उचित नहीं है क्योंकि नीति जारी करने से पहले प्रस्ताव फॉर्म के साथ आरसी एकत्र करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा छह परिचालन कार्यालयों ने इसी तरह के मामलों में प्रीमियम के कम संग्रह को स्वीकार किया।

4.3.2 ओआईसीएल

2016-17 से 2018-19 के दौरान 23,79,450 पॉलिसी (14,11,746 माल वाहक वाहन) जारी की गईं। इसके प्रति 19,50,167 पॉलिसियां (11,59,676 माल वाहक वाहन) वाहन डेटाबेस (81.96 प्रतिशत पॉलिसियों) से मेल¹² खा रही थीं। मिलान किए गए आंकड़ों में से, लेखापरीक्षा ने आगे के विश्लेषण के लिए 10,59,755 पॉलिसियों (5,91,936 माल वाहक वाहन) को लिया।

यह देखा गया कि:

क) 5,175 पॉलिसियों (3,400 वाहनों) में जहां 'माल वाहक वाहनों' के लिए टाइप 'ए' की दरों के अनुसार प्रीमियम लिया जाना चाहिए था, वहां टाइप 'डी' 'विविध और विशेष प्रकार के वाहनों' की दरों के अनुसार लिया गया था।

ख) उपर्युक्त 5,175 पॉलिसियों (3,400 वाहनों) में से 2,577 पॉलिसियां (1,703 वाहन) एक कंपनी (मैसर्स दिल्ली बड़ौदा रोड कैरियर लिमिटेड) को जारी की गई थीं, जो वाहक कारोबार का संचालन कर रही थी और माल वाहक वाहनों के लिए तीसरे पक्ष के प्रीमियम के लिए ₹8.59 करोड़ का वसूला जाना आवश्यक था। इसके प्रति केवल ₹1.37 करोड़ का तृतीय पक्ष प्रीमियम लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹7.22 करोड़ का प्रीमियम कम वसूला गया। इस मामले में मिलीभगत और धोखाधड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसकी जांच की आवश्यकता है।

¹¹ बांद्रा डी.ओ., साकीनाका डी.ओ., मेरठ डी.ओ. // और चेन्नई आर.ओ.।

¹² ओआईसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में गलत/अमान्य वाहन संख्या, वाहन संख्याओं के प्रति खाली क्षेत्रों आदि के मामले भी शामिल थे, जिनका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के साथ मिलान नहीं किया जा सका और लेखापरीक्षा में इसकी जांच नहीं की जा सकी।

ग) अन्य को जारी की गई शेष 2,598 पॉलिसियों (1,701 वाहनों) में ₹3.12 करोड़ तृतीय पक्ष प्रीमियम के रूप में वसूला जाना आवश्यक था। इसके प्रतिकूल केवल ₹1.32 करोड़ का तृतीय पक्ष प्रीमियम लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.80 करोड़ का कम प्रीमियम वसूला गया।

ओआईसीएल ने अपने उत्तर (जुलाई 2021) में मेसर्स दिल्ली बड़ौदा रोड कैरियर लिमिटेड को जारी 2,577 मोटर पॉलिसियों में ₹7.22 करोड़ के कम संग्रहण को स्वीकार किया। अन्य को जारी की गई 2,598 पॉलिसियों के संबंध में, ओआईसीएल ने केवल 16 पॉलिसियों के संबंध में ₹2 लाख का कम संग्रह स्वीकार किया। ओआईसीएल ने बताया कि शेष 2,582 पॉलिसियों के मामले में, वाहन या तो यात्री वाहक वाहन थे या विविध प्रकार के वाहन थे और तदनुसार प्रीमियम लिया गया है। ओआईसीएल ने आगे सूचित किया कि, उन्होंने मार्च 2021 में विविध और विशेष श्रेणी के वाहनों के तहत वाहनों के जोखिम अंकन के लिए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए अपने सभी परिचालन कार्यालयों को सलाह दोहराई है।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि मोटर वाहनों के गलत वर्गीकरण के मामले ओआईसीएल की ओर से प्रभावी निगरानी और जिम्मेदारी के अभाव का संकेत देते हैं। 2,582 पॉलिसियों के बारे में, हालांकि प्रबंधन ने बताया है कि ये यात्री ले जाने वाले वाहन थे, वाहन के बैकएंड डेटा के संदर्भ में आगे के विश्लेषण से पता चला है कि कम से कम 236 मामले थे जहां वाहनों के पास 'माल परमिट' था, जो यह दर्शाता है कि वे वास्तव में माल ढोने वाले वाहन थे जहां टाइप 'ए' प्रीमियम लागू था। इसलिए, ओआईसीएल को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रत्येक मामलों को फिर से सत्यापित करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार उचित परिश्रम और जोखिम अंकन प्रथाओं की कमी के कारण मोटर बीमा प्रीमियम की कम वसूली हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹14.05 करोड़ (एनआईसीएल में ₹5.03 करोड़ और ओआईसीएल में ₹9.02 करोड़) की हानि हुई।

इस मामले की सूचना अप्रैल 2022 में मंत्रालय को दी गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2022)।

सिफारिश संख्या 10: एनआईसीएल और ओआईसीएल उन मामलों में मोटर बीमा प्रीमियम के कम संग्रह के मामलों को सत्यापित कर सकते हैं जो उनके द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं। दोनों कंपनियां आंतरिक नियंत्रण को मजबूत कर सकती हैं और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सकती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मामले दोबारा न हों।

सिफारिश संख्या 11: एनआईएसीएल के मामले में, मोटर बीमा पॉलिसियों की परीक्षण जांच के दौरान प्रीमियम की कम चार्जिंग देखी गई थी। एनआईएसीएल इसी तरह के अन्य मामलों की पहचान करने और कार्रवाई करने के लिए मोटर बीमा पॉलिसियों की विस्तृत जांच कर सकता है।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

4.4 निवेश नीति के अनुसार इक्विटी शेयरों की निकासी में विफलता के कारण परिहार्य हानि

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपनी निवेश नीति में निर्दिष्ट सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों की निकासी में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹7.53 करोड़ तक की निवेश हानि को कम करने का अवसर खो दिया।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसी) की वार्षिक निवेश नीति 2015-16 में इक्विटी शेयरों के लिए निकासी नीति निर्धारित की गई है। नीति में एक निकास रणनीति निर्धारित की गई है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सक्रिय रूप से कारोबार करने वाले शेयरों का विभिन्न कारकों जैसे वसूली की संभावना, वित्तीय मापदंडों पर विचार करते हुए व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किया जाएगा, जिन पर आमतौर पर बिक्री के समय विचार किया जाता है, और प्रबंधन को सही समय पर अधिकतम संभव मूल्य प्राप्त करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए।

यूआईआईसी ने जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के 37,91,842 इक्विटी शेयरों में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से ₹102 प्रति शेयर की दर से ₹38.68 करोड़ का निवेश किया। इसके बाद यूआईआईसी ने (मई 2013) ₹35.05 प्रति शेयर की दर से अतिरिक्त 5,71,000 इक्विटी शेयर खरीदे। इस प्रकार, यूआईआईसी ने जेआईएल के 43,62,842 इक्विटी शेयरों में ₹93.24 प्रति शेयर के औसत लागत मूल्य पर कुल ₹40.68 करोड़ का निवेश किया।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि

- i. जेआईएल के लाभ और शेयर की कीमतों में 2011-12 से अर्थात् आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के बाद दूसरे वर्ष से गिरावट आनी शुरू हो गई। जेआईएल का शेयर मूल्य कभी भी यूआईआईसी द्वारा किए गए ₹102 प्रति शेयर के प्रारंभिक लागत मूल्य (मई 2010) के बराबर नहीं था।

ii. जेआईएल घाटे में चल रही थी और निवेश और वित्त गतिविधियों से ऋणात्मक नकदी प्रवाह था, जिसके परिणामस्वरूप 2015-16 के बाद से प्रति शेयर आय ऋणात्मक हो गई थी।

iii. सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट (2015-16) में बताया कि जेआईएल ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रमशः ₹300 करोड़ और ₹193 करोड़ के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है। भुगतान में चूक लगातार बढ़ती रही और जो ₹5,091.18 करोड़¹³ (मार्च 2019) तक रही। इसके बाद जेआईएल की इक्विटी पूंजी भी पूरी तरह से नष्ट हो गई (मार्च 2020)।

iv. अगस्त 2017 में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसरण में जेआईएल दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत (मार्च 2022) कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही थी।

v. यूआईआईसी ने जनवरी 2020 में जेआईएल के इक्विटी शेयरों का मूल्य उनके बहीखाते में ₹0.52 करोड़¹⁴ तक अवलेखित किया। इस प्रकार, यूआईआईसी ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने वित्तीय विवरणों में ₹40.16 करोड़ की हानि लेखाबद्ध की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2017 के दौरान जेआईएल में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के बारे में जेआईएल की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 (नवंबर 2017) में खुलासा करने के बाद भी यूआईआईसी ने निवेश में अपनी हानि को कम करने के लिए जेआईएल के शेयरों का निपटान नहीं किया। यूआईआईसी दिसंबर 2017 में ही मासिक औसत शेयर मूल्य पर जेआईएल के शेयरों का निपटान करके अपनी हानि को ₹7.53 करोड़¹⁵ तक बचा सकता था।

इस प्रकार, बाहर निकलने की रणनीति विकल्प के साथ वार्षिक निवेश नीति निर्धारित होने के बावजूद, यूआईआईसी जेआईएल के लगातार बिगड़ते वित्तीय प्रदर्शन के मद्देनजर निवेश से बाहर निकलने और जेआईएल के इक्विटी शेयरों में अपनी निवेश हानि को ₹7.53 करोड़ तक कम करने में विफल रहा।

¹³ मूलधन - ₹1,318.95 करोड़; ब्याज - ₹3,772.23 करोड़।

¹⁴ 30.09.2019 को ₹1.20/शेयर X 43,62,842 ।

¹⁵ ₹18.47 (दिसंबर 2017 का औसत बीएसई मूल्य) - ₹1.20 (30.09.2019 का शेयर मूल्य जो निवेश को लेखा पुस्तको में कम करने के लिए प्रयोग किया गया था) = ₹17.27 X 43,62,842 शेयर।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि निकास रणनीति उन मामलों पर लागू नहीं होती है जहां, आंतरिक मूल्य¹⁶ बाजार मूल्य से अधिक है। चूंकि 30 सितंबर 2017 को जेआईएल के इक्विटी शेयरों का आंतरिक मूल्य बाजार मूल्य से अधिक था, इसलिए स्टॉक से बाहर निकलने पर विचार नहीं किया गया था। मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन करते हुए (जून 2022) कहा कि लगातार दो तिमाहियों में कंपनी के शेयर मूल्य में लगातार कोई गिरावट नहीं आई थी।

मंत्रालय/प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जेआईएल के सक्रिय रूप से कारोबार वाले शेयरों में निवेश से बाहर निकलने के लिए अन्य महत्वपूर्ण कारकों अर्थात् लगातार बिगड़ते वित्तीय निष्पादन, लाभप्रदता में गिरावट, और उसके बाद निरंतर हानि, नकारात्मक प्रति शेयर आय और जेआईएल शेयर के बाजार मूल्य में गिरावट पर विचार करने के बजाय आंतरिक मूल्य को निर्णायक कारक मानते हुए हानि उठाना विवेकपूर्ण नहीं था। इसके अतिरिक्त औसत तिमाही कीमत के आधार पर सितंबर 2017 से जेआईएल के शेयर मूल्य में लगातार गिरावट देखने को मिली थी।

इस प्रकार, जेआईएल के इक्विटी शेयरों के समय पर निपटान में उचित परिश्रम करने में यूआईआईसी की विफलता के परिणामस्वरूप निवेश हानि को ₹7.53 करोड़ तक कम करने का अवसर खो दिया।

सिफारिश संख्या 12: कंपनी इक्विटी शेयरों से बाहर निकलने के विकल्प पर विचार करने के लिए ध्यान में रखने वाले कारकों में एक कारक के रूप में लगातार नकारात्मक प्रति शेयर आय को शामिल करने के लिए अपनी निकास नीति की समीक्षा कर सकती है।

¹⁶ यूआईआईसी निवेश विभाग के अनुसार, बाजार की भाषा में आंतरिक मूल्य परिसंपत्ति के वास्तविक मूल्य/ मूल्य को संदर्भित करता है और परिसंपत्ति आधारित मूल्यांकन दृष्टिकोण के तहत यह कंपनी परिसंपत्तियों से कंपनी की देनदारियों का योग घटाकर प्राप्त किया जाता है।

अध्याय V: स्टील मंत्रालय

एमएसटीसी लिमिटेड

5.1 अविवेकपूर्ण वित्तपोषण के परिणामस्वरूप ₹26.87 करोड़ की हानि हुई

एमएसटीसी लिमिटेड ने सामग्री के बार-बार असंतोषजनक उठाने के पैटर्न, बकाया देय राशि के अनियमित भुगतान और खराब वित्तीय मापदंडों के बावजूद ग्लोबल कोक लिमिटेड का वित्तपोषण जारी रखा। एमएसटीसी लिमिटेड गिरवी रखी गई सामग्री की जोखिम बिक्री करने, कॉर्पोरेट गारंटी लागू करने और अनुकूल माध्यस्थ्य अधिनिर्णय के कार्यान्वयन के माध्यम से बकाया राशि की वसूली के लिए उचित कदम उठाने में भी विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹26.87 करोड़ की हानि हुई।

एमएसटीसी लिमिटेड (कंपनी) ने (दिसंबर 2009) फैंसिलिटेटर मोड¹ के तहत हार्ड कोकिंग कोयले के क्रय के वित्तपोषण के लिए ग्लोबल कोक लिमिटेड, (पार्टी) के साथ समझौता ज्ञापन किया। समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी को पार्टी के अनुरोध पर, पार्टी द्वारा क्रय किए जाने वाले कोयले के मूल्य के लिए विक्रेता पर एक साख पत्र खोला जाता है। यद्यपि सामग्री का स्वामित्व पार्टी के पास है, इस प्रकार क्रय की गई सामग्री कंपनी के पास गिरवी रहेगी। पार्टी को नकद दो और माल लो के आधार पर सामग्री उठाने की अनुमति दी जाएगी। कंपनी के पास जनवरी 2013 में अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति के आधार पर नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए एक रेटिंग प्रणाली है, जिसमें कहा गया है कि 25 अंक से कम हासिल करने वाले ग्राहक का चयन नहीं किया जाएगा। समझौते के अनुसार, कंपनी चोरी, ठगी आदि के विरुद्ध गिरवी रखी गई सामग्री के लिए कॉर्पोरेट गारंटी, व्यक्तिगत गारंटी, सुरक्षा जमा और बीमा सुरक्षित करेगी, जिसमें लाभार्थी अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए एमएसटीसी होगा।

उपरोक्त समझौता ज्ञापन दिसंबर 2011 में समाप्त हो गया था, और गिरवी रखी गई सामग्री को समाप्त करने के लिए कंपनी द्वारा इसे 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दिया गया

¹ 'फैंसिलिटेटर' मोड में जहां अंतिम खरीदारों के पास सीधे आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति का अनुबंध होता है, एमएसटीसी केवल आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए खरीदारों की ओर से लेटर ऑफ क्रेडिट खोलकर वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है।

था। गिरवी रखी गई सामग्री के परिसमापन में केवल मामूली सुधार देखते हुए भी, कंपनी ने (जुलाई 2013) 1 अप्रैल 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिए इसे नवीनीकृत करने का निर्णय लिया और क्रेडिट एक्सपोजर सीमा को भी ₹40 करोड़ से बढ़ाकर ₹60 करोड़ कर दिया गया। इस तरह का नवीकरण इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद किया गया था कि पार्टी के पास खराब वित्तीय मापदंड² थे और क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रेडिट रेटिंग (अप्रैल 2012) को डाउनग्रेड किया गया था। इसके बाद, कंपनी ने दिसंबर 2014 और जनवरी 2015 में फिर से मार्च 2015 तक समझौता ज्ञापन का विस्तार करके पार्टी को वित्त पोषित किया। हालांकि, पार्टी मई 2015 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास गई।

कंपनी ने (जून 2015) ₹31.37 करोड़ के अपने बकाया की वसूली के लिए पार्टी की गिरवी रखी गई सामग्री की जोखिम बिक्री के लिए जाने का फैसला किया क्योंकि पार्टी भुगतान करने, सामग्री उठाने में अनियमित थी और पार्टी औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास गई। हालांकि, कंपनी जोखिम बिक्री के साथ आगे नहीं बढ़ी क्योंकि पार्टी ने (जुलाई 2015) कंपनी से जुलाई 2019 तक अपने बकाया का भुगतान करने के प्रस्ताव के साथ उत्पादन बढ़ाने की अपनी योजना का हवाला देते हुए जोखिम बिक्री को रोकने का अनुरोध किया। पार्टी ने बीमा कंपनी द्वारा घाटे के अपने दावे से इनकार करने और कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया की विफलता का हवाला देते हुए अपने स्टॉक की स्थिति को समाप्त करने के लिए कोई एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की।

इसके अतिरिक्त, पूर्वोपाय के रूप में, कंपनी ने गिरवी रखी गई सामग्री की जोखिम बिक्री के लिए अनुमति लेने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पक्षकार बनाने के साथ-साथ अपने बकाया की वसूली के लिए पार्टी के विरुद्ध (अगस्त 2015) मध्यस्थता कार्यवाही का आह्वान किया। मध्यस्थ ने कंपनी के पक्ष में (नवंबर 2017) मामला सुनाया और पार्टी को ब्याज और लागत सहित ₹28.72 करोड़³ का भुगतान करने का निर्देश दिया।

² पार्टी के खराब वित्तीय मापदंडों को तरलता अनुपात, मूल्यहास और कर से पहले लाभ में गिरावट, कर से पहले लाभ में गिरावट, उच्च ऋण इक्विटी अनुपात और कम वर्तमान अनुपात जैसे महत्वपूर्ण अनुपातों द्वारा प्रतिकूल होने का संकेत दिया गया था।

³ 2 जनवरी 2016 से अवार्ड की तिथि तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज और उसके बाद की अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वास्तविक वसूली तक ₹6.60 लाख की लागत का निर्धारण किया गया है।

लेकिन पार्टी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता की धारा⁴ 10 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, कोलकाता से संपर्क किया और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने अंततः पार्टी के परिसमापन के लिए (मई 2018) आदेश दिया। कंपनी को अंततः (सितंबर 2019) ₹35.80 करोड़⁵ के अपने कुल दावे के विरुद्ध गिरवी रखी गई सामग्री के निपटान से आय के रूप में परिसमापक से केवल ₹1.35 करोड़ प्राप्त हुए। कंपनी ने पार्टी से ₹26.87 करोड़ के बकाया को अपनी लेखा पुस्तकों में डूबी रकम के रूप में मान्यता दी, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसे गैर-वसूली योग्य मानते हुए लेखा पुस्तको में डाल दिया गया था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी की निम्नलिखित कार्रवाइयां उसके वित्तीय हित में नहीं थीं:

- पार्टी की खराब वित्तीय स्थिति को जानने के बावजूद मौजूदा समझौता ज्ञापन का विस्तार करना। कंपनी को क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पार्टी की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करने की भी जानकारी थी, जो खराब ऋण चुकाने की योग्यता का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, पार्टी द्वारा सुरक्षित क्रेडिट पॉइंट (21 अंक) ग्राहक को लेटर ऑफ क्रेडिट देने के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित मानदंड (25 अंक) से कम था।
- यह जानते हुए भी कि पार्टी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी और यह मई 2015 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास गया था, पार्टी के अनुरोध पर जोखिम बिक्री नोटिस (जून 2015) का कार्यान्वयन नहीं करना।
- जोखिम बिक्री के गैर-कार्यान्वयन के एक महीने के बाद पार्टी के विरुद्ध मध्यस्थता कार्यवाही का आह्वान करने के परिणामस्वरूप पार्टी को अतिरिक्त समय दिया गया और परिणामस्वरूप तत्काल कार्रवाई से राहत मिली।
- कंपनी द्वारा मध्यस्थ के अवार्ड (नवंबर 2017) को लागू करने का कोई प्रयास नहीं करना, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि पार्टी को ब्याज और लागत के साथ

⁴ आईबीसी, 2016 की धारा 10 के तहत एक कॉर्पोरेट आवेदक द्वारा ऋण का भुगतान करने में असमर्थता का आरोप लगाते हुए एक कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू की जाती है।

⁵ परिसमापक का दावा मध्यस्थता अवार्ड अर्थात् लागू ब्याज के साथ ₹28.72 करोड़ पर आधारित था।

₹28.72 करोड़ का भुगतान करना चाहिए। कंपनी की इस निष्क्रियता ने पार्टी को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (मई 2018) का दरवाजा खटखटाने का समय दिया।

- कंपनी ने बकाया राशि की वसूली के लिए पार्टी से समय पर प्राप्त ₹66.34 करोड़ की कॉर्पोरेट गारंटी का उपयोग नहीं किया और अंत में, यह प्रभावी नहीं हो सका क्योंकि पार्टी ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था।

इस प्रकार, पार्टी की खराब वित्तीय स्थिति से अवगत होने के बावजूद पार्टी की क्रेडिट एक्सपोजर सीमा को बढ़ाने के साथ-साथ आयातित कोयले की अपनी क्रय को वित्त पोषित करने का कंपनी का निर्णय विवेकपूर्ण और यथार्थवादी नहीं था। कंपनी ने गिरवी रखी गई सामग्री की जोखिम बिक्री, कॉर्पोरेट गारंटी के आह्वान और अनुकूल मध्यस्थता अवार्ड के कार्यान्वयन के माध्यम से पार्टी से बकाया वसूलने के लिए उचित कदम नहीं उठाए, जिससे अंततः ₹26.87 करोड़ की हानि हुई।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रबंधन/मंत्रालय ने (जनवरी 2022/जून 2022) कहा कि एक्सपोजर को धीरे-धीरे कम करने की दृष्टि से उच्च सिक्योरिटी डिपॉजिट (यानी 15 से 20 प्रतिशत तक) और मार्क-अप के साथ क्रय जारी रखा गया था। इसके अतिरिक्त, समझौते को फिर से वैध बनाना जरूरी था क्योंकि पार्टी के परिसर में गिरवी रखा गया स्टॉक पड़ा था।

प्रबंधन/मंत्रालय का उपर्युक्त तर्क स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सामग्री के असंतोषजनक उत्थान और खराब वित्तीय मापदंडों के साथ बकाया देय राशियों के अनियमित भुगतान को देखते हुए प्रबंधन का उच्च सिक्योरिटी डिपॉजिट और मार्क-अप के साथ पार्टी को वित्तपोषित करना जारी रखने का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था। इसके बावजूद, कंपनी ने समय-समय पर समझौते को फिर से वैध बनाया और अपने वित्तीय और वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए बकाया देय राशि की वसूली के लिए गिरवी रखी गई सामग्री की जोखिम बिक्री शुरू करने के बजाय पार्टी को वित्तपोषित करना जारी रखा। इसके अतिरिक्त, उत्तर मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने में विलंब के मुद्दे पर स्थिर था, जिसने अंततः पार्टी को अपने दम पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में जाने के लिए पर्याप्त समय और गुंजाइश दी।

इस प्रकार, गिरवी रखी गई सामग्री की जोखिम बिक्री, कॉर्पोरेट गारंटी के आह्वान और अनुकूल मध्यस्थता अधिनिर्णय के कार्यान्वयन के माध्यम से पार्टी से बकाया वसूलने के लिए उचित कदम नहीं उठाने के कारण, कंपनी को ₹26.87 करोड़ की हानि हुई।

सिफारिश संख्या 13: लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि कंपनी को चूक का विश्लेषण करना चाहिए (जैसे जोखिम बिक्री निर्णय और मध्यस्थता अधिनिर्णय का गैर-कार्यान्वयन और समय पर कॉर्पोरेट गारंटी को गैर-लागू करना), जो पार्टी के साथ व्यवसाय में हुआ और संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करें।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

5.2 परियोजना प्रबंधन में कमियों के कारण हानि

सेल/बोकारो इस्पात संयंत्र में हॉट मेटल डिसल्फराइजेशन स्टेशन परियोजना को पूरा नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹33.34 करोड़ के ब्याज की हानि और संविदाकार को भुगतान किए गए ₹15.21 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के साथ ₹67.82 करोड़ की निधि अवरुद्ध हो गई।

सेल की आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के एक भाग के रूप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)/बोकारो स्टील संयंत्र में स्टील मेल्टिंग शॉप-II में हॉट मेटल डिसल्फराइजेशन स्टेशन की स्थापना के लिए एक परियोजना (जुलाई, 2008) अनुमोदित की गई थी। परियोजना का उद्देश्य लोहे से सल्फर सामग्री को कम करना था, जिसे स्टील में अवांछनीय माना जाता है क्योंकि यह स्टील के प्लास्टिक गुणों को खराब करता है। हॉट मेटल डिसल्फराइजेशन स्टेशन का कार्य मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (संविदाकार) और मैसर्स डेनियली कोरस बीवी के कंसोर्टियम को अक्टूबर 2008 में ₹51.21 करोड़ और 1,696,979 यूरो के अनुबंध मूल्य पर सौंपा गया था। इस परियोजना को अप्रैल 2010 तक पूरा किया जाना था। सेल ने 31 मार्च 2015 तक परियोजना पर ₹53.55 करोड़ खर्च किए (जिसके बाद केवल मध्यस्थता अधिनिर्णय भुगतान और कुछ माइलस्टोन भुगतान किए गए) और जुलाई 2021 तक लागत बढ़कर ₹67.82 करोड़ हो गई।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- हॉट मेटल डिसल्फराइजेशन स्टेशन परियोजना के लिए सामग्री की आपूर्ति और उपकरणों का निर्माण क्रमशः अक्टूबर 2012 में पूरा किया गया था (31 महीने की विलंब

के साथ, मार्च 2010 तक पूरा होने की तिथि निर्धारित) और सितंबर 2014 (54 महीने की विलंब के साथ, पूरा होने की निर्धारित तिथि सितंबर 2014 है)। प्रारंभिक स्वीकृति टेस्ट 30 अप्रैल 2015 और 1 मई 2015 के बीच आयोजित की गई थी (60 महीने की विलंब के साथ, ट्रायल रन और कमीशनिंग के लिए निर्धारित तिथि अप्रैल 2010 थी)। प्रारंभिक स्वीकृति प्रमाण पत्र हालांकि 26 फरवरी 2016 को जारी किया गया था जो 31 दिसंबर 2015 से प्रभावी था। परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि से 11 वर्ष से अधिक समय पूर्ण हो जाने के बाद भी परियोजना का कमीशनिंग और निष्पादन गारंटी परीक्षण अभी तक नहीं किया जा सका है। कमीशनिंग और निष्पादन गारंटी परीक्षण में विलंब का मुख्य कारण विभिन्न अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सुविधाओं जैसे सिविल और संरचनात्मक कार्य, क्रेन और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, दुर्दम्य कार्य, उपयोगिताओं, ग्रिप गैस के लिए डक्ट कार्य आदि के साथ संबद्ध उपकरणों का पूरा न होना था, जिसे सेल द्वारा किया जाना था। प्रबंधन ने संविदाकार को 16 एक्सटेंशन (31 दिसंबर 2018 तक) दिए, जिसने परियोजना के पूरा होने की तिथि 16 अप्रैल 2010 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2018 कर दी।

ii) अनुबंध पूरा होने में विलंब जिसका संबंध संविदाकार से नहीं लगाया जा सकता, संविदाकार ने समय बढ़ाने, मूल्य भिन्नता और अनुबंध में भिन्नता के लिए दावे (30 मार्च 2016) प्रस्तुत किए। चूंकि बोकारो स्टील प्लांट ने बकाया राशि का भुगतान करने और दावे का निपटान करने के लिए संविदाकार के बार-बार अनुरोधों का उत्तर नहीं दिया, इसलिए संविदाकार ने सुलह (मई 2016) का आह्वान किया और उसके बाद विवाद को सुलझाने के लिए 5 अगस्त 2016 को सुलह का आह्वान किया। संविदाकार के दावे में अन्य बातों के साथ-साथ 2545 दिनों के समय का विस्तार अर्थात् फरवरी 2017 तक (30 अक्टूबर 2016 तक विलंब की घटनाओं के लिए) और ब्याज, अनुबंध अवधि से परे मूल्य भिन्नता और अतिरिक्त कार्यों के लिए मूल्य में भिन्नता के साथ लम्बी अवधि की लागत के लिए ₹20.23 करोड़ का विस्तार शामिल है। मध्यस्थ ने निर्णय लिया (10 सितंबर 2018) कि संविदाकार द्वारा दावा किए गए 2,545 दिनों की कुल विलंब में से, 1,869 दिनों (30 जून 2009 से 12 अगस्त 2014) का विलंब केवल बोकारो स्टील प्लांट के कारण थी। सेल द्वारा किए गए सभी काउंटर दावों और अनुरोधों को खारिज करते हुए, संविदाकार को अनुबंध में किए गए अतिरिक्त कार्य की लागत के लिए ₹1.68 करोड़ और ब्याज के साथ ₹11.23 करोड़ और लम्बी अवधि की लागत के रूप में ब्याज

दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट ने पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में संविदाकार को ₹15.21 करोड़⁶ का भुगतान (9 मार्च 2019) किया।

iii) इसके अतिरिक्त, यूनितों की लम्बी स्थापना और प्रचालन न होने के कारण, संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए और लगाए गए उपस्करणों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए मरम्मत/नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। अनुबंध की शर्तों के खंड 30.2 के अनुसार, दोष देयता अवधि कमीशन की तिथि से 12 महीने या प्रारंभिक स्वीकृति से 18 महीने, जो भी पहले हो, थी। प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि को ध्यान में रखते हुए दोष देयता अवधि 30 जून 2017 को समाप्त हो गई। संविदाकार ने (जुलाई 2017) सूचित किया कि उपकरण की गारंटी/वारंटी समाप्त हो गई है और नवीनीकरण/मरम्मत कार्य के लिए ₹16 करोड़ का संविदा दर प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, बोकारो स्टील प्लांट ने अनुमान को उच्च स्तर पर ध्यान में रखते हुए (मई 2019) नवीनीकरण कार्य को आंतरिक करने का फैसला किया। सहायता संघ ने बाद में उपकरणों के प्रतिस्थापन और नवीनीकरण के लिए ₹57.75 करोड़ की मूल्य बोली (दिसंबर 2021) प्रस्तुत की। नवीनीकरण का काम अभी पूरा नहीं हुआ था और जिस परियोजना पर सेल ने ₹67.82 करोड़ खर्च किए थे, वह अधूरा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेल द्वारा संविदाकार को सिविल फ्रंट⁷ प्रदान करने में विलंब, संबद्ध अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पैकेजों को पूरा करने में विलंब के कारण, परियोजना में बुरी तरह से विलंब हुई। लंबे समय तक और इकाइयों का संचालन न होने के कारण, संयंत्र को चालू करने के लिए 7 से 11 साल पहले स्थापित उपकरणों को नवीनीकृत करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, परियोजना प्रबंधन की कमी के कारण सेल/बोकारो स्टील संयंत्र में हॉट मेटल डिसल्फराइजेशन स्टेशन परियोजना पूरी नहीं हो सकी, जिसके परिणामस्वरूप ₹67.82 करोड़ की निधि अवरुद्ध हो गई। इसके अतिरिक्त, उपकरणों के नवीनीकरण की लागत ₹57.75 करोड़ होने का अनुमान है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि (i) हॉट मेटल डिसल्फराइजेशन स्टेशन सुविधाओं से जुड़े सभी पैकेजों के लिए अनुबंधों को पूरा होने की तिथि से प्रदान किया गया था।

⁶ ₹11.23 करोड़ की लंबी लागत + ₹2 करोड़ प्री और पोस्ट अवार्ड ब्याज; अतिरिक्त काम की लागत ₹1.68 करोड़ + ₹0.30 करोड़ प्री और पोस्ट अवार्ड ब्याज।

⁷ परियोजना के लिए साइट।

तथापि, समय बीतने के साथ परियोजना के संबद्ध पैकेजों के बीच कार्य के वास्तविक निष्पादन में विसंगति होने लगी और (ii) तकनीकी अध्ययन और स्थापित उपकरणों और संरचनाओं के मूल्यांकन के बाद सहायता संघ ने पाया कि कई उपकरणों को प्रतिस्थापन और नवीनीकरण की आवश्यकता है। मंत्रालय ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए (जून 2022) कि बोकारो स्टील संयंत्र में समग्र परियोजना प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है, कहा कि कार्यकारी निदेशकों की एक समिति ने परियोजना प्रबंधन में सुधार के लिए सुझावों की एक सूची भी संकलित की थी जो वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन थी।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबद्ध पैकेजों में विलंब मुख्यरूप से प्रबंधन द्वारा अग्र भाग उपलब्ध कराने में विलंब के कारण हुआ था। प्रबंधन को परियोजना के संबद्ध पैकेजों के बीच बेमेल को रोकने के लिए परियोजना गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए थी। परियोजना के चालू होने में विलंब के कारण, 7 से 8 साल पहले स्थापित उपकरणों को नवीनीकरण और प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार, सेल/बोकारो स्टील संयंत्र ने अपने त्रुटिपूर्ण परियोजना प्रबंधन के कारण ₹67.82 करोड़ की धनराशि को अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण हॉट मेटल डिसल्फराइजेशन स्टेशन परियोजना पूरी नहीं हुई और परिणामस्वरूप ₹33.34 करोड़⁸ (दिसंबर 2021 तक) के ब्याज की हानि हुई। संविदाकार को भुगतान की गई लंबी अवधि की लागत के कारण ₹15.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी किया गया। इसके अतिरिक्त, 7-8 साल पहले स्थापित उपकरणों को ₹57.75 करोड़ की अनुमानित लागत (उपकरण स्थापित करने पर शुरू में खर्च की गई लागत का 85.15 प्रतिशत) पर नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। स्टील में अवांछनीय माने जाने वाले लोहे से सल्फर की मात्रा को कम करने की परियोजना का उद्देश्य भी अप्राप्य है।

सिफारिश संख्या 14: प्रबंधन परियोजना के प्रत्येक चरण में विलंब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने पर विचार कर सकता है और परियोजनाओं के संबद्ध पैकेजों के बीच बेमेल को रोकने के लिए परियोजनाओं की बेहतर योजना सुनिश्चित कर सकता है।

⁸ एसबीआई की कैश क्रेडिट दर पर भुगतान किए गए ब्याज के आधार पर गणना

5.3 राउरकेला स्टील संयंत्र में स्थापित गैस धारक के निष्क्रिय होने से हानि

राउरकेला स्टील संयंत्र के आगामी आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम की दृष्टि में नए कोक ओवन गैस धारक की आवश्यकता का निर्धारण करने में विफलता के कारण ₹99.37 करोड़ की लागत से स्थापित गैस धारक केवल 27 महीने के उपयोग और नौ साल से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने के बाद निरर्थक हो गया।

वर्ष 1960 के दौरान सेल/राउरकेला स्टील संयंत्र में स्थापित मौजूदा गैस धारकों⁹ ने 18 वर्षों के अपने उपयोगी जीवन को समाप्त कर लिया था। सेल बोर्ड ने गैस ग्रिड में पर्याप्त दबाव बनाए रखने, अधिशेष गैस उत्पादन का भंडारण करने और आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने के लिए समान क्षमता के मौजूदा गैस धारक के प्रतिस्थापन के रूप में 1,00,000 घन मीटर कोक ओवन गैस धारक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (अक्टूबर, 2006) प्रदान किया। सेल बोर्ड ने जुलाई, 2007 में ₹110.55 करोड़ की सांकेतिक लागत से उपर्युक्त परियोजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान किया था।

राउरकेला स्टील संयंत्र ने एमबी इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, क्लेटन वाकर गैस धारक डिवीजन, यूके और मैसर्स मिको, कोलकाता के कंसोर्टियम को ₹99.37 करोड़ की लागत से 1,00,000 क्यूबिक मीटर मैन (ऑयल) टाइप कोक ओवन गैस धारक के निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर (जुलाई 2007) जारी किया।



चित्र 5.1: कोक ओवन गैस धारक

गैस धारक को अगस्त 2010 में चालू किया गया था और यह 7 नवंबर 2012 तक परिचालन में था। 7 नवंबर 2012 को एक घटना¹⁰ हुई जिसके कारण उपकरण तब से परिचालन में नहीं थे। राउरकेला स्टील संयंत्र के कोयला और रसायन विभाग ने गैस धारक की मरम्मत के लिए एक प्रस्ताव (जनवरी 2015) शुरू किया था, लेकिन राउरकेला स्टील संयंत्र द्वारा प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया

⁹ गैस धारक स्टील संयंत्र की सभी उपभोक्ता इकाइयों को कोक ओवन गैस की निरंतर आपूर्ति का भंडारण और अनुरक्षण करते हैं तथा कोक ओवन गैस उत्पादन/वितरण/खपत में उतार-चढ़ाव का भी ध्यान रखते हैं।

¹⁰ इस घटना से कोक ओवन गैस धारक के पिस्टन को हानि पहुँची

गया था। गैस धारक के लिए कार्य योजना का सुझाव देने के लिए सात साल से अधिक समय के बाद एक बहु-अनुशासनात्मक समिति (जून 2020) का गठन किया गया था। समिति ने गैस धारक के संशोधन के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की सिफारिश (सितंबर 2020) की। तथापि, राउरकेला स्टील संयंत्र द्वारा गैस धारकों के पुनरुद्धार का कार्य नहीं किया गया था क्योंकि राउरकेला स्टील संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के बाद कोक ओवन गैस की स्थिति में सुधार को देखते हुए कोक ओवन गैस नेटवर्क के लिए गैस धारक की आवश्यकता नहीं थी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- i. जब 1,00,000 घन मीटर कोक ओवन गैस धारक, की संस्थापना का प्रस्ताव सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था, तो बोर्ड को (अक्टूबर, 2006) सूचित किया गया था कि आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के पश्चात् कोक ओवन गैस उत्पादन 62,000 न्यूटन घन मीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 78,000 न्यूटन घन मीटर प्रति घंटा करने की परिकल्पना की गई थी। इस आवश्यकता की दृष्टि से, बोर्ड ने पर्याप्त भंडारण क्षमता के लिए 1,00,000 घन मीटर की क्षमता वाले नए गैस धारक के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (अक्टूबर, 2006) प्रदान किया।
- ii. गैस ग्रिड में पर्याप्त दबाव बनाए रखने के लिए गैस धारक की आवश्यकता होती है। यह उत्पादन और खपत में अस्थायी भिन्नता का प्रबंधन करने के लिए एक बफर प्रदान करता है। यदि गैस उत्पादन में सुधार होता है, तो गैस आपूर्ति की स्थिरता में भी सुधार होता है और ऐसे परिदृश्य में अस्थायी विविधताओं का प्रबंधन करने के लिए गैस धारक की आवश्यकता नहीं होती है।
- iii. राउरकेला स्टील संयंत्र की आधुनिकीकरण और विस्तार योजना (मई, 2007) के चरण-I अनुमोदन में 57 ओवन के साथ कोक ओवन बैटरी 6 की परिकल्पना की गई थी और तकनीकी विनिर्देशों का मसौदा जुलाई, 2007 में गैस धारक के अनुमोदन के लगभग उसी समय जारी किया गया था। आधुनिकीकरण के बाद राउरकेला स्टील संयंत्र की क्षमता बढ़कर 90,000 न्यूटन घन मीटर¹¹ प्रति घंटा कोक ओवन गैस का उत्पादन हो जाता, जो

¹¹ कोक ओवन बैटरी 6, आधुनिकीकरण के बाद 29,546 न्यूटन क्यूबिक मीटर प्रति घंटे कोक ओवन गैस उत्पन्न करने में सक्षम थी। यह, जब मौजूदा कोक ओवन गैस उत्पादन (62,000 न्यूटन क्यूबिक मीटर

78,000 न्यूटन घन मीटर प्रति घंटे की परिकल्पित आवश्यकता से अधिक था। गैस की इस तरह की बेहतर निरंतर आपूर्ति के कारण, गैस धारक निरर्थक हो जाएगा। यह भी पाया गया है कि आधुनिकीकरण के बाद कोक ओवन गैस का औसत वास्तविक उत्पादन 88,000 न्यूटन क्यूबिक मीटर प्रति घंटा से अधिक रहा है।

iv. जुलाई, 2007 में गैस धारक की संस्थापना के लिए कार्य सौंपे जाने से पूर्व प्रबंधन द्वारा आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के पूरा होने के बाद गैस धारक की आवश्यकता और कोक ओवन गैस की स्थिति में सुधार का समुचित विश्लेषण नहीं किया गया था। नवंबर 2012 में गैस धारक के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रबंधन ने घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की और इसके पुनरुद्धार के लिए 2013-20 के बीच विभिन्न समितियों का गठन किया। गैस धारक अब निरर्थक हो गया क्योंकि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने गैस धारक के संशोधन के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए बहु-अनुशासनात्मक समिति की सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की। गैस धारक तब से निष्क्रिय है और उसकी मरम्मत नहीं की गई और न ही पुनः परिचालित किया गया था।

v. सेल प्रबंधन ने मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों में परिसंपत्ति के मूल्य के लिए प्रावधान किया है।

इस प्रकार, प्रबंधन द्वारा अपने आगामी आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए नए कोक ओवन गैस धारक की आवश्यकता का निर्धारण करने में विफलता के कारण ₹99.37 करोड़ की लागत से स्थापित गैस धारक निरर्थक हो गया। गैस धारक पर किया गया व्यय निष्फल था क्योंकि गैस धारक 2012 में हुई एक घटना के बाद नौ साल से अधिक समय से निष्क्रिय था और प्रबंधन ने इसके उपयोग के 27 महीने बाद ही इसे पुनः परिचालित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि:

i. मई 2007 में राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के चरण-1 अनुमोदन में, केवल प्रमुख संयंत्रों की रूपरेखा को शामिल किया गया, और बाद में विस्तृत तकनीकी विनिर्देश और अन्य तकनीकी पहलुओं को तैयार किया गया था। पुराने गैस

प्रति घंटे) के साथ जोड़ा जाता है, तो 90,000 न्यूटन क्यूबिक मीटर प्रति घंटे कोक ओवन गैस का उत्पादन होगा।

नेटवर्क की स्थिरता पर आधुनिकीकृत इकाई से उत्पन्न गैस के परिचालन डेटा और संभावित सकारात्मक प्रभाव के बारे में गैस धारक का आदेश देते समय ज्ञात नहीं था।

ii. गैस उत्पादन में सुधार के कारण, गैस धारक की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी। गैस धारक के पुनरुद्धार, परिचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त व्यय की आवश्यकता थी।

iii. इस प्रकार, इस अवधि में बदलती परिचालन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप गैस धारक निरर्थक हो गए।

प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि ₹99.37 करोड़ की लागत से निर्मित नया गैस होल्डर 27 महीने के उपयोग के बाद ही निरर्थक हो गया था। इसके अलावा, प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जा सकता है कि

i. समग्र परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (अक्टूबर, 2006) तैयार की गई थी जिसमें 40 ओवन के साथ कोक ओवन बैटरी 6 की परिकल्पना की गई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार योजना (मई 2007) के चरण-1 अनुमोदन में 57 ओवन के साथ कोक ओवन बैटरी 6 की परिकल्पना की गई थी। तकनीकी विनिर्देशों का मसौदा जुलाई 2007 में जारी किया गया था और कोक ओवन बैटरी 6 के परिकल्पित मापदंडों के अनुसार प्रति घंटा कोक ओवन गैस उत्पादन 29,546 न्यूटन क्यूबिक मीटर प्रति घंटा होगा। कोक ओवन गैस का कुल उत्पादन 90,000 न्यूटन क्यूबिक मीटर प्रति घंटा से अधिक होगा जो आधुनिकीकरण के बाद परिकल्पित कोक ओवन गैस उत्पादन (78,000 न्यूटन क्यूबिक मीटर प्रति घंटा) से अधिक था। इसलिए प्रबंधन यह रुख नहीं अपना सकता कि गैस धारक का आदेश देने के समय ये ब्यौरे उसके पास उपलब्ध नहीं थे। हालांकि प्रबंधन ने जुलाई 2007 में गैस धारक के लिए आदेश देने से पहले इस पर विचार नहीं किया।

ii. प्रबंधन का जवाब उपकरण की आवश्यकता के बारे में अनुचित मूल्यांकन पर लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि करता है।

iii. प्रबंधन द्वारा उद्धृत बदलती परिचालन परिस्थितियां, कोक ओवन बैटरी 6 की स्थापना के कारण कोक ओवन गैस उत्पादन में वृद्धि है। चूंकि गैस धारक के लिए आदेश देते समय कोक ओवन बैटरी 6 के परिकल्पित मापदंडों के बारे में प्रबंधन को पता था, इसलिए इसे एक नए गैस धारक की आवश्यकता की गंभीर रूप से जांच करनी चाहिए थी।

आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम के तहत नए गैस धारक के लिए आदेश दिए जाने और 57 ओवन के साथ नई कोक ओवन बैटरी 6 के बारे में निर्णय की परिकल्पना एक-दूसरे के साथ हुई थी, इसलिए नए कोक ओवन बैटरी 6 के संचालन के साथ गैस उत्पादन में सुधार का निर्धारण करने में प्रबंधन की असमर्थता और तथ्य यह है कि अब एक नए गैस धारक की आवश्यकता नहीं होगी, समझ से परे है। इस प्रकार, कोक ओवन गैस की पर्याप्त उपलब्धता के आलोक में नए कोक ओवन गैस धारक की आवश्यकता का निर्धारण करने में प्रबंधन की विफलता, जिससे गैस धारक की आवश्यकता समाप्त हो गई, इसके आगामी आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम के कारण ₹99.37 करोड़ निर्धारण की लागत से स्थापित गैस धारक केवल 27 महीनों के उपयोग और नौ साल से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने के बाद निरर्थक हो गया।

इस मामले की सूचना मार्च 2022 में मंत्रालय को दी गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2022)।

सिफारिश संख्या 15: प्रबंधन यह सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य में किसी भी अन्य आगामी जोड़, संशोधन या प्रतिस्थापन परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी नए उपकरण की आवश्यकता का विस्तार से विश्लेषण किया जाए।

इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर

अध्याय VI: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड

6.1 प्रतिपूर्ति प्रभारों का परिहार्य भुगतान

चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने निर्धारित सीमा के भीतर हार्मोनिक्स को बनाए रखने के लिए उपकरण स्थापित करने में देरी के कारण तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उदग्रहित प्रतिपूर्ति प्रभारों के रूप में ₹7.34 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 में परिकल्पना की गई थी कि कनेक्शन बिंदु पर ट्रांसमिशन प्रणाली से विद्युत धारा की निकासी के लिए कुल हार्मोनिक्स विरूपण¹ आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (टीएनईआरसी) द्वारा निर्धारित तमिलनाडु विद्युत आपूर्ति संहिता में हार्मोनिक्स डंपिंग के लिए अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किए गए हैं। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा स्थापित कोई उपकरण हार्मोनिक्स उत्पन्न करता है तो उपभोक्ता लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली में हार्मोनिक्स के डंपिंग से बचने के लिए पर्याप्त हार्मोनिक दमन इकाइयां प्रदान करेगा। यदि उपभोक्ता ऐसी इकाइयां प्रदान करने में विफल रहता है तो वह ऐसी दरों पर प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो टीएनईआरसी समय-समय पर घोषित करे।

चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने हाईटेंशन (एचटी III) बिजली उपभोक्ता होने के नाते क्रमशः जुलाई 2013 और सितंबर 2015 में कोयम्बेडु रिसीविंग सब-स्टेशन और अलंदूर रिसीविंग सब-स्टेशन पर दो सर्विस कनेक्शन प्राप्त किए थे। दोनों उप-स्टेशनों को टीएनईआरसी/सीईए द्वारा निर्धारित आठ प्रतिशत के भीतर हार्मोनिक्स स्तर बनाए रखने की आवश्यकता थी। हालांकि, तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम (टीएएनजीईडीसीओ) द्वारा फरवरी 2017 में कोयम्बेडु रिसीविंग सब-स्टेशन और जनवरी 2018 में अलंदूर

¹ हार्मोनिक विरूपण विद्युत वितरण प्रणाली के भीतर आवृत्तियों में परिवर्तन के कारण सामान्य वोल्टेज और विद्युत धारा की विविधताएं हैं। वोल्टेज या विद्युत धारा तरंग रूप के विरूपण का एक उपाय (जो आदर्श रूप से साइनसोइडल होगा) और मौलिक के परिमाण के प्रतिशत के रूप में व्यक्त सभी वोल्टेज या वर्तमान हार्मोनिक्स के वर्गों के योग का वर्गमूल है।

रिसीविंग सब-स्टेशन पर हार्मोनिक्स को मापने के लिए किए गए परीक्षणों में, यह पाया कि वास्तविक हार्मोनिक्स स्तर क्रमशः 27.97 प्रतिशत और 14.10 प्रतिशत था, जो उप-स्टेशनों पर आठ प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक था। इसलिए, टीएएनजीईडीसीओ ने मई 2017 से सितंबर² 2020 तक और अप्रैल 2018 से अप्रैल 2021 तक क्रमशः कोयम्बेडु रिसीविंग सब-स्टेशन और अलंदूर रिसीविंग सब-स्टेशन पर आठ प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर हार्मोनिक्स स्तर को नहीं बनाए रखने के लिए ₹24.39 करोड़³ का प्रतिपूर्ति प्रभार लगाया और इसका भुगतान सीएमआरएल द्वारा किया गया। इसके बाद, सीएमआरएल ने निर्धारित सीमा के भीतर हार्मोनिक्स को बनाए रखने के लिए क्रमशः फरवरी 2021 और अप्रैल 2021 में ₹5.20 करोड़ (करों को छोड़कर) की कुल लागत से कोयम्बेडु रिसीविंग सब-स्टेशन और अलंदूर रिसीविंग सब-स्टेशन में डायनेमिक पावर कमपेंसेशन सिस्टम को स्थापित किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अप्रैल 2021) कि टीएएनजीईडीसीओ द्वारा किए गए हार्मोनिक्स परीक्षणों के बाद सीएमआरएल द्वारा समय पर डायनेमिक पावर कमपेंसेशन सिस्टम स्थापित करने में विफलता के परिणामस्वरूप परिहार्य प्रतिपूर्ति प्रभार का भुगतान किया गया।

इस प्रकार, डायनेमिक पावर कमपेंसेशन सिस्टम की स्थापना में देरी के परिणामस्वरूप वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया और साथ ही टीएएनजीईडीसीओ को परिहार्य प्रतिपूर्ति प्रभारों का भुगतान किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जून 2021) कि चूंकि शुरुआती चरण के दौरान प्रणाली में लोड गतिशील प्रकृति का था, इसलिए हार्मोनिक्स को बनाए रखने के लिए उचित प्रतिक्रियाशील विद्युत प्रतिपूर्ति इकाई की रूपरेखा तैयार करना संभव नहीं था और इसलिए फरवरी 2019 में फेज- I के अंतिम चरण के चालू होने के बाद प्रतिपूर्ति प्रणाली तैयार की गई थी। मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन करते हुए (जनवरी 2022) कहा कि लोड पैटर्न और हार्मोनिक्स जैसे मापदंडों की निगरानी और विश्लेषण फेज- I के चालू होने के बाद छह महीने की अवधि के लिए किया गया था ताकि आवश्यक प्रणाली की इष्टतम क्षमता का

² टीएएनजीईडीसीओ द्वारा अक्टूबर 2020 में कोयम्बेडु रिसीविंग सब-स्टेशन पर एक परीक्षण किया गया था और दर्ज किए गए हार्मोनिक्स निर्धारित सीमा के भीतर थे, इसलिए सितंबर 2020 के बाद कोई प्रतिपूर्ति प्रभार उदग्रहित नहीं किया गया था।

³ कोयम्बेडु रिसीविंग सब-स्टेशन ₹10.91 करोड़ और अलंदूर रिसीविंग सब-स्टेशन ₹13.48 करोड़।

पता लगाया जा सके। डायनेमिक पावर कमपेंसेशन सिस्टम के प्रावधान के लिए 9 मार्च 2020 को कार्य सौंपे जाने का पत्र जारी किया गया था। मार्च 2020 के दौरान, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण "अप्रत्याशित स्थिति" की स्थिति उत्पन्न हुई और डायनेमिक पावर कमपेंसेशन सिस्टम के चालू होने में देरी हुई।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि फेज- I खंड (34.51 किमी) का अधिकांश हिस्सा मई 2018 में चालू किया गया था और फेज- I खंड का आखिरी और अंतिम विस्तार यानी महालेखाकार-चिकित्सा सेवा निदेशालय (एजी-डीएमएस) से वाशरमेनपेट (9.95 किमी) फरवरी 2019 में चालू किया गया था। चूंकि मई 2018 में कुल लंबाई का 77.62 प्रतिशत चालू किया गया था, इसलिए सीएमआरएल को फेज- I खंड के अधिकांश हिस्से के चालू होने के तुरंत बाद डायनेमिक पावर कमपेंसेशन सिस्टम की स्थापना प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी ताकि नवंबर/दिसंबर 2019 तक इसे पूरा कर लिया जाता (मंत्रालय के उत्तर के अनुसार अध्ययन के लिए छह महीने और डायनेमिक पावर कमपेंसेशन सिस्टम के प्रावधान के लिए 12 महीने की निष्पादन अवधि पर विचार करते हुए)। इसके बजाय, स्थापना प्रक्रिया में देरी हुई, और फेज- I के चालू होने के दो साल बाद डायनेमिक पावर कमपेंसेशन सिस्टम को स्थापित किया गया।

इस प्रकार, डायनेमिक पावर कमपेंसेशन सिस्टम की स्थापना के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में देरी के परिणामस्वरूप वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया और साथ ही टीएएनजीईडीसीओ को ₹7.34 करोड़⁴ के परिहार्य प्रतिपूर्ति प्रभार का भुगतान किया गया।

⁴ कोयम्बेडु सब-स्टेशन ₹1.83 करोड़ (दिसंबर 2019 से सितंबर 2020) और अलंदूर रिसीविंग सब-स्टेशन ₹5.51 करोड़ (दिसंबर 2019 से अप्रैल 2021)।

अध्याय VII: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

7.1 रियायतग्राही से ₹693.24 करोड़ की क्षति की वसूली करने में एनएचएआई की असमर्थता

एनएचएआई, एस्करो करार नहीं करने के कारण परियोजना राजमार्ग की मरम्मत और रखरखाव करने में विफलता के लिए रियायतग्राही पर लगाए गए ₹693.24 करोड़ की क्षति की वसूली करने में असमर्थ था।

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के सतारा-कागल खंड¹ में मौजूदा 2-लेन सड़क को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को प्राधिकृत किया (फरवरी 1999)। यह परियोजना एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। एनएचएआई की परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) कोल्हापुर द्वारा परियोजना की निगरानी की जाती है (5 मई 2017 से)।

एनएचएआई ने बीओटी² आधार पर सतारा-कागल खंड राजमार्ग के डिजाइन, इंजीनियरिंग, रखरखाव और टोल संग्रह के लिए 15 मार्च 2001 को महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (एमएसआरडीसी)³ के साथ करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमएसआरडीसी ने परियोजना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (नवम्बर, 2001) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तपोषण के साधन, राजस्व का बंटवारा, पक्षकारों का अंशदान आदि शामिल हैं। एनएचएआई ने बीओटी आधार पर चलाई जाने वाली परियोजना के लिए रियायतग्राही के रूप में एमएसआरडीसी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पारस्परिक शर्तें निर्धारित करने के लिए, एनएचएआई और एमएसआरडीसी ने एक रियायत करार किया (4 जनवरी 2002)।

¹ राष्ट्रीय राजमार्ग 4 का सतारा-कागल खंड 592.240 किमी से 725.000 किमी तक डीपीआर के अनुसार 132.760 किमी का खंड है और तीन जिलों अर्थात् सांगली, कोल्हापुर और सतारा से होकर गुजरता है।

² निर्माण परिचालन और हस्तांतरण

³ महाराष्ट्र राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

परियोजना के लिए सहमत रियायत-अवधि नियत तिथि⁴ से 20 वर्ष थी। रियायत करार के पक्षकारों ने 3 मई 2002 को नियत तिथि के रूप में निर्धारित किया। रियायत की अवधि 24 जून 2022 को समाप्त हो गई।

परियोजना के लिए अनंतिम वाणिज्यिक परिचालन तिथि (पीसीओडी)⁵ दो चरणों में घोषित की गई थी। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, एमएसआरडीसी सड़क-उपयोगकर्ताओं से टोल-संग्रह शुरू कर सकता था। पहला और दूसरा पीसीओडी क्रमशः 22 मई 2005 और 24 मई 2006 था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- i. एस्करो खाते से संबंधित रियायत करार का खंड 25 प्रावधान करता है कि एमएसआरडीसी को एस्करो बैंक खाता खोलना और स्थापित करना चाहिए। परियोजना के निर्माण के लिए एमएसआरडीसी द्वारा जुटाई गई सारी धनराशि उस एस्करो बैंक खाते में जमा की जानी थी। परियोजना के परिचालन के दौरान एमएसआरडीसी द्वारा एकत्र किए गए सभी टोल को एस्करो खाते⁶ में भी जमा किया जाना था। परियोजना पर एनएचएआई द्वारा एकत्र की गई फीस, यदि कोई हों और सभी संबंधित संवितरण भी एस्करो बैंक खाते से/में जमा किए जाने थे। इसके अलावा, एमएसआरडीसी को रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार किए गए एस्करो करार के माध्यम से एस्करो बैंक को अपरिवर्तनीय दिशा निर्देश देना था।
- ii. एस्करो करार की पार्टियाँ एमएसआरडीसी, ऋणदाता, एस्करो बैंकर और एनएचएआई होनी चाहिए। एस्करो बैंक खाते से स्वीकार्य संवितरणों में से एक 'एनएचएआई को रियायतग्राही द्वारा देय और देय भुगतान और क्षति' थी।

⁴ नियत तिथि को उस तिथि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर रियायत करार के खंड 22 के अनुसार वित्तीय समापन प्राप्त किया जाता है और रियायत अवधि ऐसी नियत तिथि से शुरू होती है।

⁵ स्वतंत्र परामर्शदाता रियायतग्राही के अनुरोध पर पीसीओडी के लिए एक अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करता है, यदि रियायत करार के खंड 16.3 में निर्दिष्ट किसी भी खंड के संबंध में परीक्षण सफल होते हैं और इस तरह के खंड को कानूनी, सुरक्षित और मज़बूती से वाणिज्यिक संचालन में रखा जा सकता है, हालांकि कुछ कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। शेष कार्यों को 'पंच सूची' में शामिल किया जाएगा, जिसे रियायतग्राही को इस तरह के अनंतिम प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 120 दिनों के भीतर पूरा करना होगा।

⁶ इस परियोजना में एनएचएआई के हितों की रक्षा की गई होती यदि एस्करो करार किया गया होता-एनएचएआई रियायतग्राही से अधिशेष प्राप्त करने का हकदार था और रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही पर लगाई गई क्षति की वसूली का भी हकदार था।

iii. पीआईयू कोल्हापुर ने कहा कि एमएसआरडीसी द्वारा एक एस्करो खाता⁷ अनुरक्षित था, लेकिन एनएचएआई परियोजना की शुरुआत से एस्करो करार की पार्टी नहीं था। इससे यह साबित हुआ कि रियायत करार के अनुसार एमएसआरडीसी, ऋणदाताओं/एस्करो एजेंट (एस्करो बैंक) और एनएचएआई द्वारा और उनके बीच एक नियमित एस्करो करार नहीं किया गया था। एस्करो बैंक एमएसआरडीसी और एनएचएआई द्वारा जमा किए गए धन का न्यासी होगा। एस्करो करार के अभाव में एनएचएआई का एमएसआरडीसी के बैंक खाते में आने वाले धन पर कोई नियंत्रण नहीं था, जिसमें उसने परियोजना से एकत्र किए गए टोल जमा किए थे।

iv. रियायत करार के खंड 18.12 और 18.13 के अनुसार यदि रियायतग्राही परियोजना राजमार्ग का अनुरक्षण और/अथवा मरम्मत नहीं करता है और एनएचएआई का नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उपचारात्मक कार्य शुरू करने में विफल रहता है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य कर सकता है। यदि एनएचएआई इस विकल्प का उपयोग नहीं करता है, तो वह अपनी चूक के लिए रियायतग्राही से क्षति की वसूली करेगा।

v. परियोजना के लिए स्वतंत्र अभियंता ने बताया कि एमएसआरडीसी रियायत करार की शर्तों और एमएसआरडीसी से वसूली जाने वाली प्रस्तावित हानि के अनुसार परियोजना राजमार्ग का रखरखाव करने में विफल⁸ रहा। स्वतंत्र अभियंता द्वारा गणना की गई हानि समय बीतने के साथ बढ़ती रही, जहां भी निरंतर गैर-अनुपालन की सूचना दी गई थी और 31 अगस्त 2021 तक हानि ₹693.24 करोड़ थी। हालांकि एनएचएआई ने एमएसआरडीसी पर हानि अधिरोपित की, क्योंकि वैध एस्करो करार मौजूद नहीं था, एनएचएआई एमएसआरडीसी से किसी भी हानि की वसूली करने में असमर्थ था।

इस प्रकार, रियायत करार की शर्तों को लागू करने में एनएचएआई की विफलता, विशेष रूप से एस्करो करार करने में इसकी विफलता के परिणामस्वरूप स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्रस्तावित हानि की वसूली करने में असमर्थता हुई।

⁷ रियायत करार एस्करो बैंक खाते को एक ऐसे खाते के रूप में परिभाषित करता है जिसे रियायतग्राही को बैंक में खोलना और बनाए रखना चाहिए जिसमें पूंजीगत और राजस्व प्राप्तियों और व्यय के कारण नकदी के सभी अंतर्वाह और बहिर्वाह, जैसा भी मामला हो, रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार जमा और डेबिट किया जाना चाहिए।

⁸ 2012 के बाद से, स्वतंत्र अभियंता (आईई) ने परियोजना राजमार्ग के दूसरे आवधिक नवीकरण को पूरा करने के लिए ओ एंड एम आवश्यकताओं की कमियाँ और गैर-अनुपालन के लिए क्षतियों की सूचना दी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2022) में निम्नलिखित कहा:

i. यद्यपि बीओटी रियायत करार के लिए यह अपेक्षित है कि विवादों को करार में निर्धारित तंत्र के माध्यम से सुलझाया जाना था, तथापि एनएचएआई रियायत करार की समाप्ति के पश्चात् भी सुलह⁹ के माध्यम से इसकी वसूली की संभावना तलाश रहा था क्योंकि रियायत करार के खंड 32.8 में कहा गया है कि किसी भी पार्टी के अधिकार और दायित्व करार की समाप्ति पर बच जाएंगे।

ii. एस्करो करार के मसौदे को हस्ताक्षरित रियायत करार की अनुसूची क्यू में शामिल किया गया था। साथ ही एमएसआरडीसी या बैंकर ने एस्करो करार के अस्तित्व में नहीं होने के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया।

iii. प्राथमिकता के क्रमानुसार, एनएचएआई द्वारा उद्ग्रहीत हानि की वसूली की प्राथमिकता बहुत कम थी। एमएसआरडीसी ने एनएचएआई को सूचित किया कि परियोजना घाटे में चल रही थी और एनएचएआई के साथ साझा करने के लिए अधिशेष उत्पन्न नहीं कर रही है। एनएचएआई ने एमएसआरडीसी को कोविड, बाढ़, विमुद्रीकरण आदि जैसे विभिन्न कारकों के लिए 53 दिनों का विस्तार (अप्रैल 2022) प्रदान करते हुए एनएचएआई के अलग-अलग बैंक खाते में विस्तारित अवधि के दौरान एकत्र किए गए टोल को जमा करने का निर्देश दिया था।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का उत्तर निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है:

i. एनएचएआई ने केवल एमएसआरडीसी को केवल पत्र भेजकर देय राशि की मांग की थी। एस्करो करार के अभाव में, एनएचएआई एमएसआरडीसी पर लगाई गई हानि की वसूली नहीं कर सका, जैसा कि स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यदि रियायतग्राही को लगता कि आईई निष्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा था, तो वह स्वतंत्र अभियंता की सेवा समाप्ति करने के लिए एनएचएआई (खंड 20.6) को अनुरोध कर

⁹ एनएचएआई ने (जून 2017) नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कानूनी/मध्यस्थता मार्ग की तुलना में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को प्रोत्साहित किया गया। पार्टियों ने जून 2022 में सुलह समिति का गठन किया है।

सकता था। एमएसआरडीसी ने ऐसा नहीं किया। एमएसआरडीसी ने एनएचएआई को स्वतंत्र अभियंता की फीस की प्रतिपूर्ति¹⁰ करना जारी रखा जो एनएचएआई भुगतान कर रहा था।

ii. कानूनी रूप से बाध्यकारी एस्क्रो करार के अभाव में, और जून 2022 में रियायत अवधि समाप्त होने के कारण, एनएचएआई के पास अपनी देय राशि की वसूली के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। ऐसे में एनएचएआई की देय राशि की वसूली संदिग्ध प्रतीत होती है।

iii. यह उत्तर कि एस्क्रो करार का मसौदा रियायत करार का हिस्सा था, और एमएसआरडीसी या बैंकर ने एस्क्रो करार के गैर-अस्तित्व के बारे में कोई विवाद नहीं उठाया, लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है। हस्ताक्षरित एस्क्रो करार के बिना, एस्क्रो बैंकर, एस्क्रो बैंक खाते से वसूली के लिए एनएचएआई के अनुरोध पर विचार करने के लिए अनुबंधित रूप से बाध्य नहीं था। साथ ही, इस मामले में केवल एनएचएआई था, एमएसआरडीसी या बैंकर नहीं, जिसे एस्क्रो करार के अभाव में हानि उठानी पड़ी।

iv. एस्क्रो बैंक खाते से निकासी में कम प्राथमिकता वाले एनएचएआई द्वारा उद्ग्रहीत हानि इस मामले में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि एनएचएआई ने एस्क्रो करार नहीं किया था।

रियायत अवधि को 53 दिनों (24 जून 2022 तक) बढ़ाते हुए एनएचएआई ने एमएसआरडीसी को विस्तारित अवधि में एकत्र किए गए टोल को एनएचएआई के एक अलग बैंक खाते में जमा करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2022)। हालांकि, एमएसआरडीसी ने विस्तारित अवधि में एकत्र किए गए ₹40.81 करोड़ के टोल को एनएचएआई के बैंक खाते में जमा नहीं किया। इससे इस मामले में एनएचएआई की कमजोर स्थिति साबित हुई।

इस प्रकार, एस्क्रो करार की कमी और रियायत करार की शर्तों को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप रियायतग्राही से देय राशि की वसूली करने में असमर्थता के कारण एनएचएआई द्वारा ₹693.24 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

¹⁰ एनएचएआई ने मई 2021 तक स्वतंत्र अभियंता की फीस का भुगतान किया, जिसमें से एमएसआरडीसी ने जनवरी 2021 तक फीस की प्रतिपूर्ति की। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी मुंबई ने स्वतंत्र अभियंता के समय को दिसंबर 2021 तक बढ़ाने (नवंबर 2021) को मंजूरी दी। स्वतंत्र अभियंता ने अभी भी अपनी सेवाएं जारी रखी (जून 2022)।

7.2 टोल राजस्व की हानि

एनएचएआई द्वारा टोल प्लाजा के लिए फीस अधिसूचना के प्रस्ताव पर कार्रवाई में देरी और राजमार्ग खंडों के पैकेजों की समय पर पूर्णता सुनिश्चित में अपर्याप्त तुल्यकालन के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को ₹39.92 करोड़ की हानि हुई।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) मोड पर तीन पैकेजों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-73 के उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा-पंचकूला खंड को चार लेन का बनाने का कार्य दो ठेकेदारों¹¹ को सौंपा और इस खंड पर दो टोल प्लाजा प्रस्तावित किए गए थे जैसा कि तालिका 7.1 में दिया गया है:

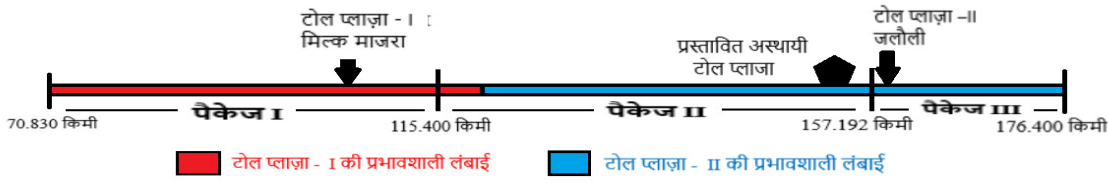
तालिका 7.1: एनएच-73 पर खंड और टोल प्लाजा के निर्माण का सारांश

पैकेज नाम	मार्ग शृंखला	प्रारंभ होने की तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	टोल प्लाजा (टीपी) पर टोल संग्रह	टोल रोड की लंबाई
पैकेज I	किमी 70.830 से किमी 115.400 (44.570 किमी)	18.11.2015	17.05.2018	टोल प्लाजा - 1 मिल्क माजरा (98.750 किमी पर)	कुल 48.192 किलोमीटर (अर्थात, किमी 70.830 से किमी 119.022 तक) (पैकेज I के 44.570 किमी और पैकेज II के 3.622 किमी)
पैकेज II	किमी 115.400 से किमी 157.192 (41.792 किमी)	18.10.2015	17.04.2018	टोल प्लाजा - 2 जलौली (158.579 किमी पर)	कुल 57.378 किलोमीटर (अर्थात, किमी 119.022 से किमी 176.400 तक) (पैकेज II का 38.170 किमी और पैकेज III का 19.208 किमी)
पैकेज III	किमी 157.192 से किमी 176.400 (19.208 किमी)	05.11.2016	04.11.2018		

परियोजना और टोल प्लाजा की आरेखीय प्रस्तुति निम्नानुसार है:

¹¹ मेसर्स सद्दाव इंजीनियरिंग लिमिटेड (करार की तिथि: जून 2015) और मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (करार की तिथि: अगस्त 2016)।

चित्र 7.1: परियोजना और टोल प्लाजा की आरेखीय प्रस्तुति



सचिव (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) की अध्यक्षता में व्यय आयोजित वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक (7 अप्रैल, 2015) के दौरान टोल प्लाजा-2 के स्थान पर विचार-विमर्श किया गया। चूंकि टोल प्लाजा-2 का स्थान पैकेज-III में प्रस्तावित किया गया था, इसलिए सचिव (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) ने टोल प्लाजा को पैकेज-III से पैकेज-II में स्थानांतरित करने की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया, क्योंकि पैकेज-III को वन्यजीव स्वीकृति के अभाव में फिलहाल स्थगित कर दिया गया था।

प्रत्युत्तर में एनएचएआई ने कहा कि पैकेज-III की बोली प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होनी थी और पैकेज-III के अंतर्गत पैकेज-II से सटे टोल प्लाजा और राजमार्ग खंड के निर्माण को एक वर्ष के भीतर पूरा करने के संबंध में एक शर्त को बोली दस्तावेजों में शामिल किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, पैकेज-III की बोली प्रक्रिया में विलंब होने की स्थिति में राजस्व की हानि से बचने के लिए, एनएचएआई ने 150.000 किमी अर्थात् पैकेज-II के खंड के भीतर एक अस्थायी टोल प्लाजा का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। इसे पैकेज-III टोल प्लाजा के निर्माण में विलंब की स्थिति में ही प्रयोग किया जाना था और इसे पैकेज-II के साथ-साथ पूरा किया जाना था। बैठक में ईएफसी द्वारा एनएचएआई के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

पैकेज-I और II के पूरा होने पर प्राधिकरण अभियंता (ईई) ने क्रमशः 13 जून 2018 और 28 मई 2018 को अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीसी) जारी करने की सिफारिश की। हालांकि, पैकेज-I और II के संबंध में ठेकेदारों को क्रमशः 19 अक्टूबर 2018 (15 जुलाई 2018 से प्रभावी) और 11 सितंबर 2018 (10 जून 2018 से प्रभावी) को पूर्णता प्रमाण पत्र (सीसी) (पिछली तिथि से प्रभावी) जारी किया गया था।

पैकेज-III के संबंध में, भूमि सम्बंधी कारणों से परियोजना में अत्यधिक देरी हुई और पीसीसी 3 मार्च 2020 (26 फरवरी 2020 से प्रभावी) को जारी किया गया और सीसी

31 जुलाई 2020 (30 जून 2020 से प्रभावी) को जारी की गई थी, जिसमें निर्धारित पूर्णता की तिथि से पीसीसी जारी होने तक 15 महीने से अधिक की देरी हुई थी।

इस बीच, एनएचएआई द्वारा दोनों टोल प्लाजा अर्थात पैकेज-I, II और III की पूरी लंबाई के लिए मसौदा शुल्क अधिसूचना को अनुमोदन के लिए 25 मई 2018 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) को भेजा गया था। मसौदा शुल्क अधिसूचना को पैकेज I और II की निर्धारित पूर्णता तिथि के बाद अग्रेषित किया गया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 80 दिनों के बाद अर्थात 13 अगस्त 2018 को दोनों टोल प्लाजा की स्थिति मांगी। एनएचएआई ने उत्तर दिया (30 अगस्त 2018) कि पैकेज-I और II पूरा हो गया था, जबकि पैकेज III की प्रगति 70 प्रतिशत थी। चूंकि पैकेज-III पूरा नहीं हुआ था, इसलिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा-I के लिए टोल अधिसूचना को मंजूरी (18 सितंबर 2018) दे दी और काम पूरा होने के बाद टोल प्लाजा-2 के लिए मसौदा शुल्क अधिसूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

टोल प्लाजा-1 पर टोल संग्रह के लिए राजपत्र अधिसूचना 26 अक्टूबर 2018 को जारी की गई थी और टोल संग्रह 30 अक्टूबर 2018 से शुरू हुआ था। टोल प्लाजा-2 पर टोल संग्रह के लिए राजपत्र अधिसूचना 18 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी और 3 मार्च 2020 को पैकेज-III के लिए पीसीसी जारी होने के बाद 4 मार्च 2020 से टोल संग्रह शुरू हुआ था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

i. एनएचएआई ने मसौदा शुल्क अधिसूचना (25 मई 2018) के लिए प्रस्ताव भेजने में देरी की क्योंकि इसे पैकेज I और II की निर्धारित पूर्णता तिथि अर्थात क्रमशः 17 मई 2018 और 17 अप्रैल 2018 के बाद भेजा गया था। इसके अलावा, दोनों टोल प्लाजा के लिए मसौदा शुल्क अधिसूचना का प्रस्ताव भेजने का निर्णय अविवेकपूर्ण था क्योंकि पैकेज III (जो टोल प्लाजा -2 के तहत शामिल किया गया था) केवल 70 प्रतिशत पूरा हुआ था। इसके परिणामस्वरूप अवांछित पत्राचार हुआ और टोल प्लाजा-1 के लिए भी फीस अधिसूचना को संसाधित करने में देरी हुई, जिसमें पैकेज I और II के पहले से ही पूर्ण खंड शामिल थे।

एनएचएआई ने पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने में लगभग चार महीने की देरी की और इसे पिछली तिथियों के साथ जारी किया, इस प्रकार अपने स्वयं के परिपत्र का उल्लंघन किया जिसमें पूर्णता प्रमाण पत्र की पिछली निर्धारण तिथि को प्रतिबंधित किया गया था।

इस प्रकार एनएचएआई के टोल प्लाजा-1 के साथ अधूरे खंड (पैकेज-III) पर टोल प्लाजा-2 के लिए मसौदा फीस अधिसूचना भेजने के अविवेकपूर्ण निर्णय और मसौदा फीस अधिसूचना के प्रस्ताव पर कार्रवाई के लिए एनएचएआई और मंत्रालय की ओर से देरी के परिणामस्वरूप टोल प्लाजा-1 के तहत 29 अक्टूबर 2018 तक खंड का टोल नहीं लिया गया और ₹7.20 करोड़¹² के टोल राजस्व की हानि हुई, जिसे एकत्र किया जा सकता था पैकेज के पूरा होने की वास्तविक तिथि के 45 दिनों के भीतर टोलिंग शुरू हो गई होती।

ii. लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि टोल प्लाजा-2 के अंतर्गत आने वाले खंड की लंबाई 57.378 किलोमीटर है, जिसमें पैकेज-II का 38.170 किलोमीटर (67 प्रतिशत) और पैकेज-III का 19.208 किलोमीटर (33 प्रतिशत) शामिल है। हालांकि, पैकेज-II और पैकेज-III की निर्धारित पूर्णता तिथियाँ अर्थात् क्रमशः 17 अप्रैल 2018 और 4 नवंबर 2018 के बीच छह महीने से अधिक का अंतर था। यदि दोनों पैकेज समय पर अर्थात् पूर्णता की अपनी-अपनी निर्धारित तिथि के अनुसार पूरे हो जाते तो भी पैकेज-II की 91 प्रतिशत लंबाई (अर्थात् टोल प्लाजा-2 की लंबाई का 67 प्रतिशत) छह महीने से अधिक की अवधि तक बिना टोल के बनी रहती।

इसके अतिरिक्त, ईएफसी के निदेशों/अनुमोदन के विपरीत पैकेज-II पर न तो अस्थायी टोल प्लाजा का निर्माण किया गया था और न ही पैकेज-II के समीपवर्ती पैकेज-III राजमार्ग खंड और टोल प्लाजा के निर्माण को शीघ्र पूरा करने की शर्त को पैकेज-III के बोली दस्तावेजों में जोड़ा गया था।

यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के निर्देशों (10 नवंबर 2014) और एनएचएआई के परिपत्र (14 नवंबर 2014) का अननुपालन भी था, जिसमें कहा गया था कि जिन हिस्सों में निर्माण पूरा हो गया है, वहां टोल करने के लिए अस्थायी व्यवस्था की जा सकती है। चूंकि पैकेज-III निर्धारित पूर्ण तिथि से 15 महीने से अधिक की देरी के साथ पूरा हुआ था, इसलिए पैकेज-II की 91 प्रतिशत लंबाई (अर्थात् 41.792 किमी में से 38.17 किमी) इसके पूरा होने की तिथि के बाद 20 महीने से अधिक की कुल अवधि तक टोल रहित रही। यह एनएचएआई की नियोजन प्रक्रिया में खामियों को दर्शाता देती हैं।

¹² ₹0.118 करोड़ प्रति दिन (टीपी 1 के लिए वास्तविक संग्रह) x 61 दिन (29 अगस्त 2018 से 29 अक्टूबर 2018 तक विलंबित अवधि/दिन)

इस प्रकार, एनएचएआई इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि पैकेज-II और III के दो निकटवर्ती खंडों के निर्माण की विवेकपूर्ण योजना बनाने और तालमेल करने में विफल रहा, कि ऐसा करने में विफलता से पूर्ण खंड के टोल न होने के कारण टोल राजस्व की हानि होगी। इसके परिणामस्वरूप, पैकेज-II के पूर्ण खंड पर टोल की वसूली न होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राजकोष को ₹32.72 करोड़¹³ के राजस्व की हानि हुई। प्रबंधन ने अपने उत्तर (21 मई 2021) में कहा कि:

- राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के एक ही खंड पर और उसी दिशा में कोई अन्य टोल प्लाजा 60 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा। प्रबंधन ने यह भी कहा कि टोल प्लाजा-2 के तहत 119.022 किमी से 157.192 किमी तक टोलिंग खंड को टोल प्लाजा-1 पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए नहीं बदला जा सकता है क्योंकि उस स्थिति में टोल प्लाजा-1 पर टोलिंग 87 किलोमीटर और टोल प्लाजा-2 के लिए केवल 19 किलोमीटर रह जाती, जो कि शुल्क नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध होता।
- इसके अलावा, प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पीसीसी/सीसी जारी करने और शुल्क अधिसूचना जारी करने में देरी हुई, पीसीसी/सीसी और शुल्क अधिसूचना जारी करने के लिए घटनाओं का कालक्रम प्रस्तुत किया।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि अस्थायी टोल प्लाजा¹⁴ के मौजूदा उदाहरण थे, एनएचएआई पैकेज-II के पूर्ण खंड पर अस्थायी टोल प्लाजा के अनुमोदित प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा, यह पैकेज-II खंड में अस्थायी टोल प्लाजा की शर्त को शामिल करने या पैकेज-III के बोली-दस्तावेजों में पैकेज-III, के समीपवर्ती पैकेज-II के राजमार्ग खंड को जल्द पूरा करने के लिए ईएफसी के निर्देशों (अप्रैल 2015) का पालन करने में भी विफल रहा।

इसके अतिरिक्त, जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 का संबंध है, प्रबंधन ने इसका केवल एक भाग उद्धृत किया है। नियमों

¹³ {₹32.46 करोड़ (टीपी 2 का वार्षिक संभावित संग्रह) x 38.17 किमी / 57.378 किमी} x 553 दिन (29 अगस्त 2018 से 3 मार्च 2020 तक विलंबित अवधि/दिन) / 365 दिन।

¹⁴ मध्य प्रदेश में एनएच-7 पर अलोनिया टोल प्लाजा और पंजाब में एनएच-1ए (नया एनएच-44) पर हरसा मानसर टोल प्लाजा।

के अनुसार, जहां कार्यकारी प्राधिकारी आवश्यक समझता है, वह लिखित रूप में कारण दर्ज करके रियायतग्राही को 60 किमी की दूरी के भीतर एक और टोल प्लाजा स्थापित या इसकी अनुमति दे सकता है। यहां तक कि वर्तमान टोल प्लाजा (टोल प्लाजा-1 और टोल प्लाजा-2) 59.829 किलोमीटर की दूरी पर अर्थात् 60 किलोमीटर से कम की दूरी पर स्थापित किए गए हैं और इसके लिए अध्यक्ष, एनएचएआई से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। पहले से स्थापित टोल प्लाजा की एक नमूना जांच से पता चला कि टोल प्लाजा 60 किलोमीटर की दूरी के भीतर (यहां तक कि 18 किलोमीटर¹⁵ की दूरी के भीतर) स्थापित किए जा रहे हैं और एनएचएआई 16 किलोमीटर¹⁶ तक की प्रभावी लंबाई के लिए टोलिंग भी कर रहा है।

इस प्रकार अविवेकपूर्ण योजना, परिहार्य विलंब और एनएचएआई द्वारा टोल के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के पैकेज-II की पूरी लंबाई पर विचार न किए जाने के परिणामस्वरूप एनएचएआई/राजकोष को ₹39.92 करोड़ की हानि हुई।

इस मामले की सूचना जनवरी 2022 में मंत्रालय को दी गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2022)।

7.3 संविदात्मक प्रावधानों को लागू न करने के कारण टोल प्रभारों की संदिग्ध वसूली

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/इसका विशेष प्रयोजन वाहन शास्तियों सहित बकाया देय राशियों की वसूली के लिए संविदात्मक प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹21.35 करोड़ की वसूली संदिग्ध है। प्राधिकरण ने एक संविदाकार को प्रयोक्ता फीस संग्रह एजेंसी संविदा भी दी जो पहले से ही अन्य टोल प्लाजा में समय पर भुगतान करने में चूक कर रहा था।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 7 के तहत प्रदान की गई सेवाओं या लाभों¹⁷ के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रयोक्ता फीस एकत्र करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के तहत प्राधिकृत है। एनएचएआई को राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और

¹⁵ राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर किरासेव टोल प्लाजा (किमी 119.100 पर) और कार्बिलू (बेल्लूर क्रॉस) टोल प्लाजा (किमी 101.250 पर) के बीच की दूरी 17.950 किलोमीटर है।

¹⁶ राष्ट्रीय राजमार्ग-75 पर होसकोट टोल प्लाजा की टोल योग्य लंबाई 16.124 किमी है।

¹⁷ इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर घाटों, स्थायी पुलों, अस्थायी पुलों और सुरंगों आदि का उपयोग शामिल है।

संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के तहत प्रयोक्ता फीस की वसूली के प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति के साथ संविदा करने का भी अधिकार है। एनएचएआई द्वारा अन्य कंपनियों के सहयोग से कुछ विशेष प्रयोजन वाहनों का भी गठन किया जाता है।

लेखापरीक्षा में चार मामले सामने आए जहां एनएचएआई/इसके विशेष प्रयोजन वाहन ने एक संविदाकार मैसर्स मोहम्मद उस्मान को प्रयोक्ता फीस संग्रहण एजेंसी की संविदा दी और संविदात्मक प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे, जिससे ₹21.35 करोड़ की संदिग्ध वसूली हुई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

7.3.1 एनएचएआई द्वारा दी गई संविदाएँ

एनएचएआई ने विशाखापत्तनम और राजमुंदरी की परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के तहत लक्ष्मीपुरम, उंगुतुरु और बेलुपाडा टोल प्लाजा के संबंध में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मैसर्स मोहम्मद उस्मान (संविदाकार) को निम्नलिखित प्रयोक्ता फीस संग्रहण एजेंसी संविदाएं प्रदान की, जैसा कि नीचे तालिका 7.2 में विस्तृत है:

तालिका 7.2: प्रयोक्ता फीस संग्रहण एजेंसी संविदाओं का विवरण

टोल प्लाजा का नाम (परियोजना कार्यान्वयन इकाई का नाम)	निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि	संविदा की तिथि	टोल प्लाजा सौंपने की तिथि और संविदा अवधि	संविदाकार द्वारा एनएचएआई को किए जाने वाले प्रेषण की शर्तें
लक्ष्मीपुरम (विशाखापत्तनम)	24.03.2017	09.05.2017	13.05.2017 (1 वर्ष अर्थात 13.05.2018 तक)	₹88.73 लाख का साप्ताहिक प्रेषण
उंगुतुरु (राजमुंदरी)	10.08.2017	16.09.2017	17.09.2017 (1 वर्ष अर्थात 17.09.2018 तक)	₹84.88 लाख का साप्ताहिक प्रेषण
बेलुपाडा (विशाखापत्तनम)	02.02.2018	22.02.2018	23.02.2018 (3 महीने अर्थात 23.05.2018 तक)	₹11.32 लाख का दैनिक प्रेषण

संविदाकार को उपर्युक्त तालिका में दी गई सूचना अनुसार साप्ताहिक/दैनिक विप्रेषण करना अपेक्षित था। तय दिन के बाद सहमत राशि के प्रेषण में देरी के मामले में, एनएचएआई को शुरुआती एक महीने की देरी के लिए 0.2 प्रतिशत प्रतिदिन और एक महीने से अधिक की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत प्रति दिन की दर से शास्ति लगाना था। इसके अलावा, इस तरह की शास्ति को निष्पादन गारंटी से वसूला जा सकता था, जिसे संविदाकार द्वारा ऐसी

वसूली की तिथि से 10 दिनों के भीतर फिर से भरा जाना था, जिसमें विफल रहने पर संविदा समाप्त किया जा सकता था। संविदाकार ने सभी तीन टोल प्लाजा के संबंध में ₹8.96 करोड़¹⁸ की नकद निष्पादन प्रतिभूतियां जमा की और कुल ₹7.37 करोड़¹⁹ की बैंक गारंटी प्रस्तुत की।

तीनों संविदाओं की शुरुआत से ही संविदाकार द्वारा साप्ताहिक/दैनिक विप्रेषण करने में विलंब²⁰ देखा गया और ये विलंब एक से 57 दिनों तक था। एनएचएआई ने देखा कि:

- लक्ष्मीपुरम टोल प्लाजा और बेलुपाडा टोल प्लाजा (2 मई 2018) के मामले में संचित देय राशि निष्पादन प्रतिभूति (नकद निष्पादन प्रतिभूति और बैंक गारंटी) से अधिक²¹ थी।
- उंगुतुरु टोल प्लाजा के मामले में, 30 जुलाई 2018 तक, एनएचएआई ने नकद निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और बैंक गारंटी को भुनाने के बाद संविदाकार से अभी भी ₹7.77 लाख की राशि की वसूली करनी थी।

उपर्युक्त संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार शास्ति की वसूली लगभग 170 प्रतिशत प्रति वर्ष बैठती है। तत्पश्चात, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने संविदा में निर्धारित अवधि के बाद प्रयोक्ता फीस संग्रहण एजेंसियों से देय राशियों पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज लगाने का निर्णय²² लिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- i. विलंबित विप्रेषणों के लिए शास्ति लगाने का प्रावधान होने के बावजूद, ऐसी शास्तियाँ नहीं लगाई गईं और समय पर वसूल नहीं की गईं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है,

¹⁸ नकद निष्पादन प्रतिभूति - लक्ष्मीपुरम टोल प्लाजा - ₹3.68 करोड़; उंगुतुरु टोल प्लाजा - ₹3.69 करोड़; और बेलुपाडा टोल प्लाजा - ₹1.59 करोड़।

¹⁹ बैंक गारंटी - लक्ष्मीपुरम टोल प्लाजा- ₹3.68 करोड़ ; उंगुतुरु टोल प्लाजा - ₹3.69 करोड़; और बेलुपाडा टोल प्लाजा - शून्य।

²⁰ लक्ष्मीपुरा टोल प्लाजा के मामले में - 1 से 57 दिन, बेलुपाडा टोल प्लाजा - 1 से 44 दिन, उंगुतुरु टोल प्लाजा - 1 से 31 दिन

²¹ परियोजना कार्यान्वयन इकाई, विशाखापत्तनम ने 2 मई 2018 को एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किया कि ₹8.97 करोड़ की बकाया देय के मुकाबले, उपलब्ध निष्पादन प्रतिभूति केवल ₹8.95 करोड़ थी, जो ₹0.02 करोड़ की कमी को दर्शाती है। 6 मई 2018 तक यह कमी की राशि ₹1.20 करोड़ तक बढ़ गई।

²² कार्यकारी समिति की 395 वीं बैठक 9 जुलाई 2019 को की गई।

संविदाओं में निष्पादन गारंटी से देय राशियों की वसूली के लिए प्रावधान किया गया था, जिसे तब संविदाकार द्वारा ऐसी वसूली की तिथि से 10 दिनों के भीतर फिर से भरना था, जिसमें विफल रहने पर संविदा समाप्त किया जा सकता था।

ii. एनएचएआई ने उपलब्ध निष्पादन प्रतिभूतियों को समायोजित करने और संविदा में प्रदान की गई शर्तों के अनुसार इसकी भरपाई या संविदा को समाप्त करने के बिना शर्त अधिकार का प्रयोग नहीं किया। इसके बजाय, एनएचएआई ने संविदाकार को 13 मई 2018 (लक्ष्मीपुरम टोल प्लाजा) और 23 मई 2018 (बेलुपाडा टोल प्लाजा) पर संबंधित संविदाओं की समाप्ति के बाद 31 मई 2018 तक टोल फीस एकत्र करना जारी रखने की अनुमति दी। उंगुतुरु टोल प्लाजा के मामले में, हालांकि एनएचएआई ने नकद निष्पादन प्रतिभूति को भुनाया और जुलाई 2018 में संविदाकार की बैंक गारंटी को लागू किया, लेकिन उसने इसकी भरपाई की मांग नहीं की या संविदा को समाप्त नहीं किया। इसके बजाय, एनएचएआई ने संविदाकार को बिना किसी प्रतिभूति के एक और महीने अर्थात् 29 अगस्त 2018 तक टोल का संग्रह जारी रखने की अनुमति दी। उल्लेखनीय है कि संविदाकार ने 6 से 29 अगस्त 2018 की अवधि के लिए एनएचएआई के पास एक भी रुपया जमा नहीं किया था और इस अवधि के लिए प्रेषण में कमी ₹3.08 करोड़ थी।

iii. यदि एनएचएआई ने उपलब्ध निष्पादन प्रतिभूतियों को समायोजित करने के अपने अधिकार का उपयोग तुरंत यह देखते हुए किया होता कि बकाया राशि उपलब्ध निष्पादन प्रतिभूतियों से अधिक थी और संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूतियों की भरपाई न होने की स्थिति में संविदा को समाप्त कर दिया होता, तो इन गैर-प्राप्तियों से बचा जा सकता था।

iv. प्रयोक्ता फीस संग्रह एजेंसी की चयन प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता के पिछले कार्यों में उसके निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कोई उचित प्रणाली नहीं है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि यद्यपि संविदाकार लक्ष्मीपुरम और उंगुतुरु टोल प्लाजा के मामले में प्रेषण के समय पर जमा करने में लगातार चूक में था, जिसके लिए संविदा क्रमशः मई 2017 और सितंबर 2017 में दिए गए थे, संविदाकार को 15 फरवरी 2018 को बेलुपाडा टोल प्लाजा के लिए एक और नई प्रयोक्ता फीस संग्रहण एजेंसी संविदा दी गई थी।

v. उपर्युक्त कमियों के परिणामस्वरूप, 13 मई 2017 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए तीन संविदाओं के संबंध में संविदाकार से देय ₹111.67 करोड़ के टोल प्रेषण और

शास्ति ब्याज के प्रति, संविदाकार द्वारा केवल ₹80.73 करोड़ की राशि प्रेषित की गई। इसके अलावा, एनएचएआई ने नकद निष्पादन प्रतिभूतियों (₹8.96 करोड़²³) को समायोजित किया और इसके पास उपलब्ध बैंक गारंटी (₹7.37 करोड़²⁴) को भुनाया। संविदाकार द्वारा संचालित अन्य टोल प्लाजा के संबंध में जमा की गई राशियों से वसूली करके एनएचएआई मुख्यालय और अन्य परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों से ₹1.83 करोड़²⁵ की राशि भी हस्तांतरित की गई थी और देय राशि के प्रति समायोजित की गई थी। इस प्रकार, संविदाकार से कुल ₹98.89 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी, लेकिन 31 मार्च 2022 तक ₹12.78 करोड़ की कम वसूली हुई जिसे तालिका 7.3 में दिया गया है:

तालिका 7.3: प्रयोक्ता फीस संग्रहण एजेंसी संविदाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

टोल प्लाजा (टीपी)	पूरी संविदा अवधि के लिए कुल देय राशि		प्राप्त की गई कुल राशि **		बकाया राशि		कुल बकाया
	मूलधन	शास्ति ब्याज (31 मार्च 2022 तक)	मूलधन	शास्ति ब्याज	मूलधन	शास्ति ब्याज	
लक्ष्मीपुरम टीपी	49.86	1.71	47.26	0.23	2.60	1.48	4.08
उंगुतुरु टीपी	44.80	1.00	43.18	0.70	1.62	0.30	1.92
बेलुपाडा टीपी	11.51	2.79	7.25	0.27	4.26	2.52	6.78
कुल	106.17	5.50	97.69	1.20	8.48	4.30	12.78

** इसमें संविदाकार से प्रेषण की राशि (₹80.73 करोड़), नकद निष्पादन प्रतिभूति (₹8.96 करोड़), बैंक गारंटी (₹7.37 करोड़) और अन्य परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों से प्राप्त समायोजित राशि (₹1.83 करोड़) शामिल हैं।

²³ नकद निष्पादन प्रतिभूति को 23 जुलाई 2018 को उंगुतुरु टोल प्लाजा के मामले में ₹3.69 करोड़ और 5 नवंबर 2018 को ₹5.27 करोड़ (लक्ष्मीपुरम टोल प्लाजा के मामले में ₹3.68 करोड़ और बेलुपाडा टोल प्लाजा के मामले में ₹1.59 करोड़) के लिए समायोजित किया गया था।

²⁴ बैंक गारंटी 23 मई 2018 को लक्ष्मीपुरम टोल प्लाजा के मामले में ₹3.68 करोड़ और 30 जुलाई 2018 को उंगुतुरु टोल प्लाजा के मामले में ₹3.69 करोड़ के लिए लागू की गई थी।

²⁵ 4 सितंबर 2019 को एनएचएआई मुख्यालय और परियोजना कार्यान्वयन इकाई विशाखापत्तनम से परियोजना कार्यान्वयन इकाई, राजमुंदरी को अन्य टोल प्लाजा से संबंधित मैसर्स मोहम्मद उस्मान से संबंधित धन राशि से ₹1.62 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे, जहां वह प्रयोक्ता फीस संग्रह एजेंसी थे। इसके बाद, 2019-20 के दौरान परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कटनी से परियोजना कार्यान्वयन इकाई, राजमुंदरी को ₹0.21 करोड़ हस्तांतरित किए गए।

इसलिए, संविदात्मक प्रावधानों को लागू नहीं करने, चूककर्ता संविदाकार को नई संविदा (बेलुपाडा टोल प्लाजा) देने और बाद में पर्याप्त प्रतिभूति (उंगुतुरु टोल प्लाजा) के बिना संविदाकार को जारी रखने के परिणामस्वरूप ₹12.78 करोड़ की कम वसूली हुई।

एनएचएआई ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि जब भी संविदाकार साप्ताहिक प्रेषण को प्रेषित करने में विफल रहा, तो ब्याज के साथ देय राशि जमा करने के लिए संविदाकार को कई नोटिस जारी किए गए। परियोजना कार्यान्वयन इकाई, विशाखापत्तनम के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों ने लक्ष्मीपुरम टोल प्लाजा और बेलुपाडा टोल प्लाजा के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार कर दिया क्योंकि मामले सिविल प्रकृति के थे। उंगुतुरु टोल प्लाजा के लिए चेबरूल पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी (मार्च 2019) के आधार पर, पुलिस ने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक आपराधिक मामला दर्ज किया है और यह लंबित है। यह भी कहा गया कि चूंकि संविदाकार ने निपटान सह क्लॉज आउट करार पर हस्ताक्षर करने के एनएचएआई के प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया था, इसलिए एनएचएआई लक्ष्मीपुरम टोल प्लाजा और बेलुपाडा टोल प्लाजा के अन्य मामलों को इकट्ठा करने या कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वसूली सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग अदालती मामले दायर करने की कार्रवाई शुरू कर रहा था।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई के उत्तर का समर्थन करते हुए (नवंबर 2021) कहा कि बकाया राशि की वसूली के लिए संविदाकार के विरुद्ध वसूली मुकदमा दायर करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, परियोजना कार्यान्वयन इकाई विशाखापत्तनम (3 नवंबर 2021) ने कानूनी सलाहकार से वसूली मुकदमा दायर करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। लक्ष्मीपुरम और उंगुतुरु टोल प्लाजा के मामले में संविदाकार को संविदा अवधि से आगे जारी रखने के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि निष्पादन प्रतिभूति (नकद और बैंक गारंटी) के समायोजन के बाद एजेंसी के प्रतिस्थापन के लिए नई बोलियां आमंत्रित की गई थीं। बोली प्रक्रिया/नई एजेंसी की नियुक्ति की अवधि के दौरान, मौजूदा संविदाकार के संविदा को संविदा करार के खंड 2 (ii) के अनुसार बढ़ाया जाना था।

निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं -

- i. यद्यपि संविदाकार शुरू से ही प्रेषण के भुगतान में अनियमित था और 2 मई 2018 (लक्ष्मीपुरम टोल प्लाजा), 17 अप्रैल 2018 (बेलुपाडा टोल प्लाजा) और 20 मार्च 2018 (उंगुतुरु टोल प्लाजा) से देय दैनिक/साप्ताहिक प्रेषण को प्रेषित नहीं किया, फिर भी

एनएचएआई ने न तो संविदाओं को समाप्त किया और न ही संविदाकार द्वारा प्रस्तुत कुल प्रतिभूतियों से अधिक राशि के शास्ति ब्याज सहित प्रेषण में कमी से पहले नकद निष्पादन प्रतिभूतियों और बैंक गारंटी को भुनाया। इसके बजाय, संविदाकार को लक्ष्मीपुरम और बेलुपाडा टोल प्लाजा के मामले में निर्धारित संविदात्मक अवधि से परे टोल प्लाजा परिचालित करने की अनुमति दी गई थी। उंगुतुरु टोल प्लाजा के मामले में भी, संविदाकार को बिना किसी निष्पादन प्रतिभूति प्रदान किए 30 दिनों तक टोल एकत्र करना जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

ii. इसके अलावा, भले ही पुलिस अधिकारियों ने इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया कि मामला सिविल प्रकृति का था और एनएचएआई के कानूनी सलाहकार ने भी जून 2019 की शुरुआत में यही राय दी थी, लेकिन मार्च 2022 में लक्ष्मीपुरम और बेलुपाडा टोल प्लाजा के मामले में वसूली मुकदमा दायर किया गया था और मुकदमा जिला अदालत, विशाखापत्तनम (मार्च 2022) में सत्यापन के अधीन था।

iii. लक्ष्मीपुरम और बेलुपाडा टोल प्लाजा से संबंधित संविदाकार के साथ संबंधित संविदाओं के खंड 2 (ii) में संविदा के अंतर्गत समान प्रेषण और निबंधन एवं शर्तों पर संविदा अवधि बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार का प्रावधान किया गया है। यह एनएचएआई का 'अधिकार' है, 'दायित्व' नहीं। इसके अलावा, संबंधित संविदाओं के पैरा 35 (3) और (4) के अनुसार, एनएचएआई संविदा के प्रावधानों के तहत किसी भी निबंधन और शर्तों के उल्लंघन/गैर-अनुपालन या किसी भी प्रकार के गैर-अनुपालन के लिए संविदा को समाप्त करने का हकदार था। अतः चूंकि संविदाकार ने निर्धारित अवधियों के भीतर देय राशि प्रेषित करने में चूक की थी, इसलिए एनएचएआई को खंड 2 (ii) के संदर्भ में संविदा का विस्तार करने के बजाय खंड 35 (3) और (4) को लागू करना चाहिए था और संविदा को समाप्त करना चाहिए था। इसके अलावा, यह एनएचएआई की जिम्मेदारी थी कि वह समय पर नई बोलियां शुरू करे ताकि संविदा अवधि समाप्त होने के बाद मौजूदा संविदाकार को बदला जा सके।

7.3.2 विशेष प्रयोजन वाहन के लिए एनएचएआई द्वारा दी गई संविदा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और वीओ चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी (तत्कालीन वीओ चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट) द्वारा तमिलनाडू राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग - 138 (एनएच 138, पूर्ववर्ती एनएच - 7ए) के तिरुनेलवेली-तूतीकोरिन खंड पर वीओ चिदंबरनार

पोर्ट प्राधिकरण की चार लेन की उन्नत सड़क कनेक्टिविटी के डिजाइन, इंजीनियरिंग, वित्तपोषण, अधिप्राप्ति, निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के लिए तूतीकोरिन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (टीपीआरसीएल/कंपनी), एक विशेष प्रयोजन वाहन कंपनी का गठन किया गया था (जनवरी 2004)। निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण आधार (बीओटी) पर पत्तन कनेक्टिविटी सड़क के निर्माण, अनुरक्षण और परिचालन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और टीपीआरसीएल के बीच एक रियायतग्राही करार पर हस्ताक्षर किए गए थे (फरवरी, 2004)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएचएआई ने एक वर्ष (24 अक्टूबर 2017 से 23 अक्टूबर 2018 तक) के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के तिरुनेलवेली-तूतीकोरिन खंड के बीच वागाईकुलम टोल प्लाजा के लिए प्रयोक्ता फीस के संग्रह के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एक संविदाकार (मोहम्मद उस्मान) के साथ टीपीआरसीएल की ओर से एक करार किया (अक्टूबर 2017)। संविदा की शर्तों के अनुसार, संविदाकार को प्रति सप्ताह (प्रत्येक मंगलवार) ₹45,60,297 की राशि प्रेषित करना अपेक्षित था जिसे बाद में टोल दरों में वृद्धि के कारण 1 अप्रैल 2018 से संशोधित कर ₹48,39,387 प्रति सप्ताह कर दिया गया था। संविदाकार ने ₹1,98,16,000 (अर्थात एक महीने के सहमत प्रेषण के बराबर) की प्रतिभूति जमा और बैंक गारंटी के रूप में ₹3,96,32,000 की निष्पादन प्रतिभूति प्रदान की (अक्टूबर 2017)। संविदा में परिकल्पना की गई थी कि किस्त के प्रेषण में देरी पर शुरुआती एक महीने के लिए 0.2 प्रतिशत प्रति दिन की दर से और बाद में देरी के लिए 0.5 प्रतिशत प्रति दिन की दर से शास्ति लगाई जाएगी। एनएचएआई के पास संविदाकार द्वारा किस्तों का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में संविदा को समाप्त करने का बिना शर्त अधिकार था। इस प्रकार लगाई शास्ति की वसूली निष्पादन प्रतिभूति से की जा सकती थी जिसे संविदाकार द्वारा ऐसी वसूली की तिथि से 10 दिनों के भीतर भरा जाना था, जिसमें विफल रहने पर संविदा समाप्त किया जा सकता था (खंड 19)। एनएचएआई के पास प्रयोक्ता फीस (खंड 24) के त्वरित संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी समय जांच करने का अधिकार भी सुरक्षित था।

तथापि, यह नोट किया गया कि संविदाकार ने सहमत राशि केवल पहले सप्ताह के लिए नियत तिथि के भीतर टीपीआरसीएल को प्रेषित की और बाद के सभी भुगतानों में देरी हुई। इसके अलावा, जून 2018 और उसके बाद के महीनों के लिए साप्ताहिक प्रयोक्ता फीस

प्रेषण का संविदाकार²⁶ द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। इसलिए, एनएचएआई ने संविदाकार से अगस्त 2018 के पहले सप्ताह तक अप्रदत्त साप्ताहिक प्रेषण के प्रति ₹3,96,32,000 की निष्पादन प्रतिभूति राशि समायोजित की (25 सितंबर 2018)। इसके बाद, एनएचएआई ने संविदा समाप्त कर दी (6 अक्टूबर 2018)। इस प्रकार, साप्ताहिक अवधियों (6 अगस्त 2018 से 6 अक्टूबर 2018 तक) के लिए ₹3.99 करोड़²⁷ की साप्ताहिक प्रेषण बिना किसी निष्पादन सुरक्षा के बकाया रहे। तत्पश्चात्, एनएचएआई ने पुलिस अधीक्षक, तुतिकोरीन के पास संविदाकार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज (मार्च 2019) की। बकाया प्रेषण (₹3.99 करोड़) और समायोजित शस्ति/शास्ति ब्याज (नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ₹4.58 करोड़) के कारण कुल लंबित बकाया राशि ₹8.57 करोड़ (अप्रैल 2022) संविदाकार से वसूल की जानी थी।

तालिका 7.4: समायोजित शास्ति/शास्ति ब्याज का विवरण

शास्ति/ब्याज और अन्य समायोजन का विवरण	राशि ₹ में
9.10.2018 तक शास्ति (₹41,89,387 की पिछली शास्ति सहित)	3,05,52,059
अक्टूबर 2018 से अप्रैल 2022 तक 12% की दर से ब्याज	1,67,16,992
कम: आरओ मद्रुरै पत्र सं. एनएचएआई/14011/18/2018/आरओ मद्रुरै/486 दिनांक 26.02.2019 के माध्यम से निष्पादन प्रतिभूति राशि का समायोजन (शेनबागमपेट्टाई टोल प्लाजा)	(9,99,238)
कम: टीडीएस - जेवी सं. 27 दिनांक 31.03.2021 के माध्यम से अप्रत्याशित दावों पर टीडीएस- जीएसटी और टीडीएस संविदाकार।	(4,34,186)
	4,58,35,627

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदाकार ने नवंबर 2017 से देरी से प्रेषण किया और जून 2018 के पहले सप्ताह तक संविदा अवधि के लिए भुगतान किया। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ टीपीआरसीएल प्रबंधन वित्तीय हानियों से बचने के लिए संविदा शर्तों के अनुसार बकाया देय राशियों को समायोजित करने और/अथवा वसूलने तथा संविदा को समाप्त करने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा। चूंकि

²⁶ 3 अक्टूबर 2018 को ₹15,00,000 के एकल भुगतान को छोड़कर।

²⁷ मूलधन: ₹3,91,13,473 और स्रोत पर कर संग्रह: ₹8,43,479

बकाया देय राशि (साप्ताहिक प्रेषण और शास्ति) जुलाई 2018 के पहले सप्ताह में निष्पादन प्रतिभूति (अर्थात् ₹3.96 करोड़) से अधिक हो गई थी, इसलिए संविदा को अक्टूबर 2018 तक प्रतीक्षा करने के बजाय जुलाई 2018 में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। संविदा की समाप्ति न होने से संविदाकार को कंपनी को प्रयोक्ता फीस प्रेषण (₹3.99 करोड़) का भुगतान किए बिना लगभग पूरी संविदा अवधि के लिए प्रयोक्ता फीस एकत्र करने की अनुमति मिली, जिसके पास 25 सितंबर 2018 के बाद कोई निष्पादन प्रतिभूति भी नहीं थी। टीपीआरसीएल को समय पर प्रेषण प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए टीपीआरसीएल को एनएचएआई से आरम्भिक चरण में त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करना चाहिए था।

इस प्रकार, टीपीआरसीएल के बकाया राशियों को समायोजित करने और/अथवा वसूलने तथा संविदा को समय पर समाप्त करने के लिए एनएचएआई के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप संविदाकार से ₹8.57 करोड़ की देय राशि की वसूली संदिग्ध हो गई।

टीपीआरसीएल प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि एनएचएआई ने संविदाकार से बकाया देय राशि एकत्र करने के लिए विभिन्न प्रयास किए थे और जिला अपराध शाखा-थुथुकुड़ी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि:

i. यद्यपि संविदाकार संविदा की शुरुआत से ही प्रेषण में देरी कर रहा था, लेकिन एनएचएआई ने संविदा को समाप्त करने के लिए संविदात्मक खंडों को लागू नहीं किया। करार के खंड 29 में यह भी कहा गया कि करार में निहित नियमों और शर्तों का कोई भी उल्लंघन जो एनएचएआई को कोई वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं, संविदा को तत्काल समाप्त कर सकता है। हालांकि संविदाकार जून 2018 से संविदा अवधि के लिए प्रेषण करने में विफल रहा, फिर भी टीपीआरसीएल/एनएचएआई ने संविदाकार को सितंबर 2018 तक ₹6.97 करोड़ की प्रयोक्ता फीस एकत्र करने की अनुमति दी और संविदा अवधि की शुरुआत के बाद से संविदाकार द्वारा प्रेषण के देरी से भुगतान/गैर-भुगतान के बावजूद इस खंड को लागू नहीं किया।

ii. एनएचएआई द्वारा प्राप्त कानूनी राय (जनवरी 2019) में भी संविदा के खंड 27 में प्रावधान के अनुसार मामले को मध्यस्थ को भेजने पर जोर दिया गया था। इसके अलावा, कानूनी राय में यह सलाह दी गई थी कि संविदाकार के विरुद्ध पुलिस में किसी भी शिकायत से एनएचएआई को देय राशि की वसूली करने में मदद नहीं मिलेगी और यह वर्षों तक

चलेगा। इसके बावजूद, एनएचएआई ने मामले को मध्यस्थ के पास भेजने के बजाय मार्च 2019 में पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई।

इस प्रकार, संविदात्मक प्रावधानों को लागू न करने, पिछले कार्यों में संविदाकार के निष्पादन का मूल्यांकन न करने और देय राशियों के प्रेषण के अनुसरण में विलंब के परिणामस्वरूप ₹21.35 करोड़ (एनएचएआई द्वारा दी गई संविदाओं में ₹12.78 करोड़ और इसके विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा दी गई गए संविदा में ₹8.57 करोड़) की वसूली संदिग्ध हो गई। इसके परिणामस्वरूप चूककर्ता संविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति प्रदान किए बिना संविदा अवधि से आगे जारी रखने की अनुमति देकर अनुचित लाभ भी हुआ।

इस मामले की सूचना मंत्रालय को दी गई थी (जनवरी 2022); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2022)।

सिफारिश संख्या 16: एनएचएआई संविदाकारों से टोल देय राशि के साथ-साथ शास्ति की वसूली सुनिश्चित करने के लिए संविदात्मक प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कर सकता है। वसूली न होने की स्थिति में समय रहते कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इस मामले में चूक के लिए एनएचएआई के दोषी अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है।

सिफारिश संख्या 17: एक केंद्रीकृत डेटाबेस में प्रयोक्ता फीस संग्रहण एजेंसियों के निष्पादन का आकलन और रिकॉर्ड करने के लिए एक उपयुक्त निगरानी तंत्र भी स्थापित किया जा सकता है जो एनएचएआई की सभी परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों/क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ एनएचएआई द्वारा गठित विशेष प्रयोजन वाहनों के लिए सुलभ हो ताकि किसी भी क्षेत्र/इकाई में चूककर्ताओं को ब्लैकलिस्ट किया जा सके और उन्हें कहीं और संविदाएं न दी जाएं।

अध्याय VIII: लेखापरीक्षा में बताए जाने पर सीपीएसई द्वारा की गई वसूली और सुधार/परिशोधन

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयर इंडिया लिमिटेड, एपिटको लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, दामोदर घाटी निगम, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स पेमेंट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

8.1 लेखापरीक्षा में बताए जाने पर वसूली

13 सीपीएसईज से संबंधित 19 मामलों में, लेखापरीक्षा ने बताया कि वसूली के लिए ₹357.54 करोड़ की राशि देय थी। सीपीएसईज के प्रबंधन ने ₹209.90 करोड़ की राशि की वसूली/बचत की थी जिस *अनुलग्नक-IV* में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

8.2 लेखापरीक्षा में बताए जाने पर सुधार/परिशोधन

नमूना जांच के दौरान, नियमों/विनियमों के उल्लंघन और प्रणाली में कमियों से संबंधित मामलों का अवलोकन किया गया और प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया। उन मामलों का ब्यौरा *अनुलग्नक-V* में दिया गया है जहां लेखापरीक्षा में बताए जाने पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी, या प्रबंधन द्वारा अपने नियमों में परिवर्तन किए गए थे।

अध्याय IX

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में रखे गए लेखाओं और अभिलेखों की संवीक्षा की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यपालिका से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त की जाए।

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया था (जुलाई 1985) कि वे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निर्दिष्ट विभिन्न पैराग्राफों/मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई को दर्शाते हुए टिप्पणी (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांचे गए) प्रस्तुत करें। ऐसी टिप्पण उन पैराग्राफों/मूल्यांकनों के संबंध में भी प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (सीओपीयू) द्वारा विस्तृत जांच के लिए नहीं चुना गया था। सीओपीयू ने अपनी दूसरी रिपोर्ट (1998-99 - 12वीं लोक सभा) में उपर्युक्त अनुदेशों को दोहराते हुए सिफारिश की:

- अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) प्रस्तुत करने की निगरानी के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना;
- विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों से संबंधित पैरावाले प्रतिवेदनों के संबंध में एटीएन प्रस्तुत करने की निगरानी के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) में निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना; और
- प्रासंगिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह माह के भीतर संसद में प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सभी प्रतिवेदनों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांचे गए अनुवर्ती एटीएन समिति को प्रस्तुत करना।

उपर्युक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते समय सीओपीयू ने अपने पहले प्रतिवेदन (1999-2000 - तेरहवीं लोक सभा) में अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराया कि डीपीई को अलग-अलग उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निर्दिष्ट अभ्युक्तियों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की


निगरानी करने के लिए डीपीई में ही एक पृथक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। तदनुसार, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा एटीएन प्रस्तुत करने पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी करने के लिए अगस्त 2000 से डीपीई में एक निगरानी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर एटीएन प्रस्तुत करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के भीतर निगरानी प्रकोष्ठ भी स्थापित किए गए हैं। लेखापरीक्षा की समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद, विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित पिछले पांच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निर्दिष्ट 41 संव्यवहार लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों, एक संपूर्ण स्टैंडअलोन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा कि *अनुलग्नक VI* में विस्तृत है, पर उपचारात्मक/सुधारात्मक एटीएन लेखापरीक्षा को पुनरीक्षण के लिए प्राप्त नहीं हुए थे।

नई दिल्ली
दिनांक: 05 दिसम्बर 2022

डा. जी. विश्वनाथन
(आर जी विश्वनाथन)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(वाणिज्यिक) और अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 06 दिसम्बर 2022


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1

(पैरा 2.10 में उल्लिखित)

दुलियाजन, असम में एलपीजी संयंत्र में उत्पादित कंडेनसेट की बिक्री के लिए निविदा रद्द किए जाने के कारण ₹24 करोड़ के राजस्व की हानि को दर्शाने वाला विवरण

महीना और वर्ष	कंडेनसेट का उत्पादन	संविदा मात्रा	न्यूनतम गारंटीकृत मात्रा (संविदा उठान (संविदा से शुद्ध प्राप्ति मात्रा का 80%))	प्रति मीट्रिक टन कच्चे तेल से प्राप्त	कंडेनसेट मीट्रिक टन पीएलएटीटीएस का औसत मूल्य	प्रति टन कीमत (एच 1 जो पीएलएटीटीएस दर से 18.51% अधिक था)	कंडेनसेट की प्राप्ति कीमत (एच 1 जो पीएलएटीटीएस दर से 18.51% अधिक था)	प्रति मीट्रिक टन अंतर राजस्व	राजस्व की हानि
	(मीट्रिक टन में)	(मीट्रिक टन में)	(मीट्रिक टन में)	(₹ में)	(₹ में)	(₹ में)	(₹ में)	(₹ में)	(₹ में)
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4	कॉलम 5	कॉलम 6	कॉलम 7	कॉलम 8 = कॉलम 7 - कॉलम 5	कॉलम 9 = कॉलम 4 X कॉलम 8	
जनवरी-20	1,518	600	480	22,197.05	39,124.02	46,365.88	24,168.83	1,16,01,036.53	
फरवरी-20	1,366	600	480	19,635.79	33,669.42	39,901.63	20,265.84	97,27,603.03	
मार्च-20	1,449	600	480	12,610.42	20,699.35	24,530.80	11,920.38	57,21,782.25	
अप्रैल-20	1,413	600	480	82,75.24	11,881.51	14,080.78	58,05.54	27,86,658.00	
मई-20	1,726	600	480	10,552.40	17,910.52	21,225.76	10,673.36	51,23,211.48	
जून-20	1,654	600	480	14,374.25	26,563.01	31,479.82	17,105.57	82,10,675.11	
जुलाई-20	1,865	600	480	15,427.17	29,357.34	34,791.38	19,364.21	92,94,822.54	

2022 की प्रतिवेदन संख्या 33

महीना और वर्ष	कंडेनसेट का उत्पादन	संविदा मात्रा	न्यूनतम गारंटीकृत मात्रा (संविदा का 80%)	प्रति मीट्रिक टन कचरे से शुद्ध प्राप्ति	कंडेनसेट प्रति मीट्रिक टन पीएलएटीटीएस का औसत मूल्य	कंडेनसेट की प्राप्ति कीमत (एच 1 जो पीएलएटीटीएस से 18.51% अधिक था)	प्रति मीट्रिक टन अंतर राजस्व	राजस्व की हानि
अगस्त-20	1,849	600	480	15,840.84	28,781.25	34,108.66	18,267.82	87,68,553.30
सितम्बर-20	1,656	600	480	14,112.78	28,429.18	33,691.42	19,578.64	93,97,747.78
अक्टूबर-20	1,767	600	480	14,090.37	27,509.86	32,601.94	18,511.57	88,85,551.24
नवंबर-20	1,450	600	480	15,221.27	27,045.27	32,051.35	16,830.08	80,78,438.15
दिसम्बर-20	1,667	600	480	17,198.60	31,519.83	37,354.15	20,155.55	96,74,664.26
जनवरी-21	1,653	600	480	18,886.71	36,568.49	43,337.32	24,450.61	1,17,36,291.60
फरवरी-21	1,429	600	480	20,909.14	40,400.15	47,878.22	26,969.08	1,29,45,157.33
मार्च-21	1,666	600	480	22,548.76	42,466.42	50,326.95	27,778.19	1,33,33,533.28
अप्रैल-21	1,593	600	480	22,444.95	41,620.45	49,324.40	26,879.45	1,29,02,133.74
मई-21	1,928	600	480	23,073.63	42,007.70	49,783.33	26,709.70	1,28,20,653.73
जून-21	1,240	600	480	24,930.84	46,672.51	55,311.59	30,380.75	1,45,82,760.77
जुलाई-21	596	596	476.8	25,610.62	50,618.70	59,988.22	34,377.60	1,63,91,240.33
अगस्त-21	2,058	600	480	24,000.30	47,438.13	56,218.93	32,218.63	1,54,64,941.37
सितम्बर-21	1,958	600	480	27,071.68	49,648.93	58,838.95	31,767.27	1,52,48,288.13
अक्टूबर-21	1,902	600	480	29,533.10	55,364.00	65,611.88	36,078.78	1,73,17,812.67
कुल								24,00,13,556.64
								24.00 करोड़

अनुलग्नक II
(पैरा 4.1 में उल्लिखित)
20 स्ट्रिप्स के लेखापरीक्षा विश्लेषण का सारांश

क्र. सं.	स्ट्रिप का नाम/पहली खरीद का वर्ष	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20			2020-21		
		आदि शेष बेंलेंस (शेयरों की संख्या) - ऑफलोड किए गए शेयर	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो बेची जा सकती थी (₹ करोड़ में)	कंपनी द्वारा बेचे गए शेयरों की संख्या, यदि कोई हो,	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	कंपनी द्वारा बेचे गए शेयरों की संख्या, यदि कोई हो,	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)		
1	बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बिल्ट लिमिटेड) 2005-06	12000000 -300000	110367622/ 12.87	15.06	1964870	169779525/ 11.30	11.00	0	107177593/ 2.87	2.8	120467951/ 0.31	0.30	516948071/ 0.32	0.31		
2	हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड (एचएफसीए) 2005-06	521000	236481851/ 11.09	0.58	0	577690024/ 11.85	0.62	0	260595595/ 17.20	0.90	107189157/ 8.15	0.42	237547380/ 8.65	0.45		
3	पेंटामीडिया ग्राफिक्स लिमिटेड 2005-06	195800	29154948/ 0.55	0.011	0	14661139/ 0.48	0.009	0	15205560/ 0.25	0.005	10692845/ 0.21	0.004	21468177/ 0.24	0.005		

2022 की प्रतिवेदन संख्या 33

क्र. सं.	स्क्रिप का नाम/पहली खरीद का वर्ष	आदि शेष बैलेंस (शेयरों की संख्या) - ऑफलोड किए गए शेयर	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21			
			वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों के कारोबार की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	कंपनी द्वारा बेचे गए शेयरों की संख्या, यदि कोई हो,	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों के कारोबार की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	कंपनी द्वारा बेचे गए शेयरों की संख्या, यदि कोई हो,	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों के कारोबार की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों के कारोबार की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)		
4	जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेपीएसओएसआईएटी) 2005-06	775000	1580813826/5.30	0.41	0	240420339/9.15	0.71	0	1471587570/4.72	0.37	362042708/1.06	0.08	1124716616/1.05	0.08
5	रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2005-06	1917750-817750	94558801/426.45	46.91	700000	89836082/390.60	15.62	0	163422790/99.10	4.0	393991576/8.65	0.35	119024883/10.60	0.42
6	बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड - बजाजहिंद 2006-07	275907	204878143/12.90	0.36	0	290229668/8.55	0.24	0	181165340/5.65	0.2	68356872/2.34	0.06	244323610/2.76	0.08
7	पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (पटेलिंग) 2018-19 (दूसरी खरीद)	225010#		0.00			0.00	0		0.0	11033825/8.10	0.18	17149193/8.95	0.20

क्र. सं.	स्क्रिप का नाम/पहली खरीद का वर्ष	आदि शेष बैलेंस (शेयरों की संख्या) - ऑफलोड किए गए शेयर	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21			
			वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	कंपनी द्वारा बेचे गए शेयरों की संख्या, यदि कोई हो,	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	कंपनी द्वारा बेचे गए शेयरों की संख्या, यदि कोई हो,	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)		
8	ग्लोबल ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड (ग्लोबोफस) 2006-07	755325	11883812/42.00	3.17	0	6483560/20.60	1.56	0	1729276/9.21	0.7	1977003/2.60	0.20	1217413/2.60	0.20
9	करतुरी ग्लोबल लिमिटेड (केजीएल) 2007-08	1500000	122504559/1.13	0.17	0	24794137/1.02	0.15	0	166075793/1.18	0.2	68014381/0.19	0.03	94446697/0.19	0.03
10	फ्यूचर मार्केट्स नेटवर्क लिमिटेड (एफएमएनएल) 2010-11 में कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से प्राप्त किया गया	31184	4247263/17.60	0.05	0	5849788/63.65	0.20	0	5489846/33.30	0.1	1149417/8.55	0.03	4169115/8.72	0.03

2022 की प्रतिवेदन संख्या 33

क्र. सं.	स्क्रिप का नाम/पहली खरीद का वर्ष	आदि शेष बैलेंस (शेयरों की संख्या) - ऑफलोड किए गए शेयर	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21			
			वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों के कारोबार की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों के कारोबार की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों के कारोबार की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों के कारोबार की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों के कारोबार की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)		
11	गोयनका डायमंड ज्वेल्स लिमिटेड (गोयनका) 2013-14	5993904	8827145/ 0.63	0.38	0	28612070/ 0.24	0.14	0	5887717/ 0.26	0.2	3961115/ 0.21	0.13	35503731/ 0.22	0.13
12	फ्लेक्सिस्टफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (फ्लेक्सिस्ट) 2013-14	800000	3642034/ 171.20	13.70	0	2071598/ 51.30	4.10	0	545204/ 27.40	2.2	619789/ 3.09	0.25	606077/ 4.45	0.36
13	अरविंद इंटरनेशनल लिमिटेड (अरविंद)- 2017-18 में दूसरी खरीद	400000*	0	0.00			0.00	0	64383093/ 72.80	2.91	81694031/ 19.00	0.76	162984556/ 19.50	0.78
14	किलॉस्कर इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड	5488	35440521/ 32.10	0.02	0	26315482/ 27.80	0.02	0	5271978/ 13.00	0.01	2417411/ 6.70	0.004	5575011/ 8.05	0.004

क्र. सं.	स्क्रिप का नाम/पहली खरीद का वर्ष	आदि शेष बैलेंस (शेयरों की संख्या) - ऑफलोड किए गए शेयर	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21			
			वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	कंपनी द्वारा बेचे गए शेयरों की संख्या, यदि कोई हो,	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	कंपनी द्वारा बेचे गए शेयरों की संख्या, यदि कोई हो,	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)		
	(केईसीएल) - 2008-09 में कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से प्राप्त किया गया													
15	पायनियर कढ़ाई (पायनियर इएमबी) 2006-07	500000	6282294/38.70	1.94	0	4828832/28.50	1.43	0	1726915/17.75	0.9	765640/14.65	0.73	1477659/15.30	0.77
16	इंडियन बैंक	57500\$		0.00			0.00	0		0.0		0.00	60991492/42.65	0.25
17	जय कॉर्प लिमिटेड (जयकॉर्प लिमिटेड)	100000	72939354/52.30	0.52	0	15630085/68.05	0.68	0	89169494/85.50	0.9	58058201/42.65	0.43	41781718/46.90	0.47

2022 की प्रतिवेदन संख्या 33

क्र. सं.	स्क्रिप का नाम/पहली खरीद का वर्ष	आदि शेष बैलेंस (शेयरों की संख्या) - ऑफलोड किए गए शेयर	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21			
			वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों के कारोबार की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	कंपनी द्वारा बेचे गए शेयरों की संख्या, यदि कोई हो,	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों के कारोबार की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	कंपनी द्वारा बेचे गए शेयरों की संख्या, यदि कोई हो,	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों के कारोबार की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान बीएसई पर किए गए शेयरों के कारोबार की संख्या/वर्ष के दौरान न्यूनतम मूल्य (बीएसई)	कम से कम राशि जो वसूली जा सकती थी (₹ करोड़ में)		
18	जीएसएस इन्फोटेक लिमिटेड (जीएसएस)	393992	1303210/ 20.05	0.79	0	31633496/ 19.00	0.75	0	29203753/ 51.30	2.0	5877436/ 19.00	0.75	7431283/ 19.00	0.75
19	द बाइक हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड (बीवाईकेई)	1800000 -550000	14182742/ 151.10	18.89	822496	10257675/ 150.25	6.42	51532	4639057/ 25.20	0.9	1961389/ 7.65	0.29	4304283/ 8.60	0.32
20	टाटा मोटर्स (डीवीआर) (टाटाएमटीआर डीवीआ)	1233907	56785465/ 258.85	31.94	0	48478165/ 183.00	22.58	0	64806480/ 72.05	8.9	139562685 / 28.35	3.50	154473892/ 28.85	3.56
				134.89			66.22			28.03		8.49		9.19

*- 2018-19 में ओपनिंग बैलेंस

#- 2019-20 में ओपनिंग बैलेंस

₹- 2020-21 में ओपनिंग बैलेंस

अन्य स्क्रिप के लिए ओपनिंग बैलेंस 2016-17 में है।

कम से कम राशि जो प्राप्त की जा सकती थी (₹ करोड़ में) = (ओपनिंग बैलेंस (शेयरों की संख्या) - विक्रय किए गए शेयर) * वर्ष के दौरान कम कीमत (बीएसई)

अनुलग्नक III
(पैरा 4.2 में संदर्भित)

2017-18 से 2020-21 के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट कि हानि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	फॉर्म जीएसटीआर-2 ए के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट	फॉर्म जीएसटीआर-3 बी के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का उठाया गया लाभ	इनपुट टैक्स क्रेडिट कि हानि
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
2017-18	154.47	106.27	48.20
2018-19	200.29	156.35	43.94
2019-20	224.87	207.40	17.47
2020-21	101.72	91.82	9.90
कुल	681.35	561.84	119.51
कम: आपूर्तिकर्ता द्वारा भेजे गए बीजकों और कम राशि पर निपटाये गये बीजकों के बीच अंतर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट			16.45
कम: केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) के अनुसार अवरुद्ध क्रेडिट			5.62
इनपुट टैक्स क्रेडिट कि शुद्ध हानि			97.44

नोट:

(1) जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है (अप्रैल 2021), ऐसे उदाहरण थे जहां एनआईसी द्वारा निपटाई गई दावा राशि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिलों की राशि से कम थी। ऐसे मामलों में, कंपनी ऑटो-पॉपुलेटेड फॉर्म जीएसटीआर -2 ए में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा उस हद तक नहीं कर सकती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इस प्रकार लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं था, ₹16.45 करोड़ था।

(2) प्रबंधन ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17 (5) के अनुसार, कुछ इनपुट विशेष रूप से कंपनी द्वारा लाभ उठाए जाने से वंचित हैं। इन्हें अवरुद्ध क्रेडिट के रूप में जाना जाता है। कंपनी द्वारा प्राप्त वास्तविक क्रेडिट की तुलना में ऐसे क्रेडिट की राशि बहुत नाममात्र (एक प्रतिशत से कम) है। तदनुसार, रूढ़िवादी आधार पर, अवरुद्ध क्रेडिट की गणना फॉर्म जीएसटीआर -3 बी के माध्यम से कंपनी द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (अर्थात् ₹561.84 करोड़) के एक प्रतिशत के रूप में की गई है, जो ₹5.62 करोड़ बैठता है।

अनुलग्नक-IV
(पैरा 8.1 में संदर्भित)
लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूली

(राशि ₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीपीएसई का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा टिप्पणियां	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूली की राशि	प्रबंधन द्वारा वसूली/सहेजी गई राशि
नागर विमानन	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण को प्रदान की गई जनशक्ति सहायता के संबंध में कर्मचारियों की लागत की वसूली न होना	641.00	250.00
नागर विमानन	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	संविदाकार को भविष्य निधि के नियोक्ता के हिस्से का अधिक भुगतान	6.22	6.09
नागर विमानन	एयर इंडिया लिमिटेड	बिना सत्यापन के डीआईएएल द्वारा किए गए विलंबित भुगतान पर ब्याज दावा स्वीकार करना	18,300.00	5,500.00
कोयला	कोल इंडिया लिमिटेड	आपूर्तिकर्ता से मूल सीमा शुल्क की अंतर राशि की वसूली न करना	6,793.00	6,793.00
वित्तीय सेवा विभाग	एपिटको लिमिटेड	अपात्र अधिकारी को आवास से आनेजाने के लिए सरकारी सुविधा के साथ वाहन भत्ता प्रदान करना	0.00	2.78
वित्तीय सेवा विभाग	एसबीआई कार्ड्स पेमेंट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड	न्यूनतम मजदूरी की गलत मैपिंग के कारण विक्रेता को भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली न होना	110.00	62.17

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीपीएसई का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा टिप्पणियां	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूली की राशि	प्रबंधन द्वारा वसूली/सहेजी गई राशि
भारी उद्योग	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं के साथ एचईसी प्रबंधन का अनुनय न किए जाने के कारण काफी समय बीत जाने के बावजूद प्रतिभूति जमा और बयाना राशि जमा की वसूली न होना	271.00	49.08
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का अनियमित भुगतान	15.00	3.00
विद्युत	दामोदर घाटी निगम	बैंक गारंटी शुल्क के कारण बैंक द्वारा अतिरिक्त कटौती	393.00	334.00
विद्युत	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अगरतला गैस टरबाइन संयंत्र-संयुक्त चक्र विस्तार परियोजना के चालू होने में देरी के कारण ठेकेदार से परिसमापन क्षति की वसूली न होना	1,600.00	1,401.30
विद्युत	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	दोषपूर्ण कंडक्टरों की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता से हानि की वसूली न होना	3,126.00	4,520.00
विद्युत	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सामग्री की कम आपूर्ति के कारण आपूर्तिकर्ता से वसूली न होना	161.00	102.00
विद्युत	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	400 केवी डीसी लोअर सुबनसिरी-विश्वनाथ चरियाली ट्रांसमिशन लाइन (I और II) परियोजना के भंडार में सामग्री की कमी	2,297.00	1,737.00

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीपीएसई का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा टिप्पणियां	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूली की राशि	प्रबंधन वसूली/सहेजी राशि	द्वारा गई
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	कर्मचारियों से अमान्य परिवहन भत्ता की वसूली	1.25		1.09
सड़क परिवहन और राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही से उपकर की वसूली न करना	25.90		25.90
सड़क परिवहन और राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	रियायतग्राही द्वारा रिलेइंग कार्य शुरू करने में विलंब के लिए नुकसान की वसूली न करना	1,942.00		132.00
इस्पात	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	गलत गणना के कारण परिसमाप्त हानि की कम वसूली	7.17		7.17
इस्पात	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	प्लॉट किराए का अधिक भुगतान	7.74		6.56
इस्पात	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	संविदात्मक शर्तों के अनुसार शास्ति की वसूली न होना	56.83		56.83
		कुल	35,754.11 लाख		20,989.97 लाख
		यानि	357.54 करोड़		209.90 करोड़

अनुलग्नक-V
(पैरा 8.2 में संदर्भित)
लेखापरीक्षा के इंगित सुधार/परिशोधन

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीपीएसई का नाम	संक्षिप्त में लेखापरीक्षा टिप्पणियां/सुझाव	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
कोयला	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता के लिए ग्रेड स्लिपेज/लाभ पर पहुंचने के लिए गलत तरीका अपनाना	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की मूल कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने (मार्च 2021) अपनी सभी सहायक कंपनियों द्वारा कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता की एक समान लेखा नीति/पद्धति तैयार की है।

अनुलग्नक-VI
(अध्याय IX में संदर्भित)

वर्ष 2021 तक पिछले पांच वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण, जिनके लिए पहली की गई कार्रवाई टिप्पण लंबित थी

प्रतिवेदन संख्या और वर्ष	प्रतिवेदन का नाम	पैरा संख्या
नागरिक उड्डयन मंत्रालय		
2019 का 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 1.1
2019 का 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 1.2
2019 का 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 1.3
2019 का 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 1.4
2020 का 18	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.1
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.1
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.2
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.3
कोयला मंत्रालय		
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 1.1
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 1.2
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 1.3
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 1.4
वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएँ विभाग)		
2017 का 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.1
2019 का 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.1
2019 का 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.3
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 4.1
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 4.2
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 4.3
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 4.4
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 4.5

प्रतिवेदन संख्या और वर्ष	प्रतिवेदन का नाम	पैरा संख्या
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 4.6
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय		
2021 का 11	निष्पादन लेखापरीक्षा	पूरी रिपोर्ट
खान मंत्रालय		
18 का 2020	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.1
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 6.1
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 6.2
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
18 का 2020	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.1
18 का 2020	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.2
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.1
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.2
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.4
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.5
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.8
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.9
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.10
2021 का 19	स्टैंडअलोन अनुपालन लेखापरीक्षा	पूरी रिपोर्ट
विद्युत मंत्रालय		
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.1
इस्पात मंत्रालय		
2019 का 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 10.5
2019 का 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 10.6
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.1
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.6
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.7

2022 की प्रतिवेदन संख्या 33

प्रतिवेदन संख्या और वर्ष	प्रतिवेदन का नाम	पैरा संख्या
कपड़ा मंत्रालय		
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.1
2021 का 14	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.2

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in